



प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
भारत सरकार

25^{वीं} वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

विषय-वस्तु



सचिव की कलम से	01
टीडीबी का अधिदेश	02
बोर्ड के सदस्य	04
विहंगावलोकन	06
टीडीबी – वर्ष एक दृष्टि में	19
हस्ताक्षरित समझौते	27
पूर्ण की गई परियोजनाएँ	41
संवर्धनात्मक गतिविधियाँ	45
प्रशासन	57
वर्ष 2020-21 के लिए लेखा-परीक्षित वार्षिक विवरण	61
प्रथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2020-21	91







सचिव की कलम से

विगत वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर हमें बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस महामारी ने हमें एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होने में सहायता की जिससे हम डटकर इसका सामना करने के सक्षम हुए।

इस महामारी के दौरान स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को यथायोग्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता हुई।

वर्ष 2020-21 में, टीडीबी को 284 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें "फाइटिंग कोविड-19" प्रस्तावों के लिए कॉल के प्रति 235 आवेदन शामिल थे। टीडीबी ने परीक्षण किट, मास्क और स्वच्छता, थर्मल स्कैनर और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में अपने उत्पादों के वाणिज्यीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय कंपनियों, प्रमुख रूप से स्टार्ट-अप से कोविड-19 सबसे लड़ने के लिए समाधान मांगने के प्रस्ताव के लिए कॉल जारी किया। इनमें से कुछ कंपनियों ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सार्थक योगदान दिया है।

टीडीबी ने 11 मई को "आरई-एसटीएआरटी - रिव्यू टॉ टेक्नोलॉजी थ्रू साईंस, टेक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च ट्रांसलेशन" पर एक डिजिटल सम्मेलन आयोजित करके प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन किया जिसमें वैश्विक स्वास्थ्य संकट में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने और समाधान खोजने हेतु वैज्ञानिकों, टेक्नोक्रेट, सरकारी अधिकारियों, राजनयिकों, डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों के गणमान्य व्यक्तियों को एक साथ लाया गया और इससे महामारी के दौरान सहायता करने के साथ-साथ आगे की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। टीडीबी ने राष्ट्रीय सम्मेलन, वेबिनार और अन्य कार्यक्रमों में वास्तविक विधि के माध्यम से भी सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रौद्योगिकी प्रवर्तक के रूप में टीडीबी की भूमिका को बढ़ाने में मदद की।

इस वर्ष, टीडीबी ने विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय

सहायता प्रदान करने के लिए 13 समझौते किए। इन समझौतों के माध्यम से, टीडीबी ने स्वास्थ्य और चिकित्सा, इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हुए कुल परियोजना लागत ₹ 80.92 करोड़ में से ऋण के रूप में ₹ 23.74 करोड़ और अनुदान के रूप में ₹ 7.30 करोड़ देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा, टीडीबी ने थालू, नई परियोजनाओं और अन्य योजनाओं के लिए ₹ 47.80 करोड़ की राशि का वितरण किया है। इसमें ऋण के रूप में ₹ 47.57 करोड़ अनुदान के रूप में ₹ 0.12 करोड़ और निवेश के लिए यूटीआई/अन्य वीसीएफ/आईटीवीयूएस को ₹ 0.11 करोड़ शामिल है।

टीडीबी ने "फाइटिंग कोविड-19" प्रस्तावों के आह्वान के हेतु ₹ 3.51 करोड़ की राशि भी वितरित की, जिसमें ऋण के रूप में ₹ 2.12 करोड़ और अनुदान के रूप में ₹ 1.39 करोड़ शामिल है।

पहले स्वीकृत परियोजनाओं में से 02 को पूर्ण और व्यावसायिकृत घोषित किया गया था, जिनमें से एक टाटा पावर लिमिटेड एसईडी द्वारा रक्षा उत्पादों के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए टीडीबी से ₹ 109.00 करोड़ की वित्तीय सहायता के साथ कुल परियोजना लागत ₹ 385.00 करोड़ थी। दूसरा एसटीएआरटी प्रोजेक्ट सॉफ्टटेक इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा रूल बडी के विकास और व्यावसायिकरण के लिए एक ई-कॉमर्स पोर्टल के रूप में था, जो कुल परियोजना लागत ₹ 615.46 लाख के प्रति ₹ 245.00 लाख की सहायता से परियोजना व्यवहार्यता और बिलिंग परमिट के लिए सेवाएं प्रदान करता है।

यह वर्ष संकट का वर्ष रहा है जिसके दौरान काफी नुकसान हुआ है और चुनौतियां प्रस्तुत की हैं। लेकिन हर चुनौती के साथ एक अवसर साथ में आता है। टीडीबी ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बढ़ावा देने वाले अपने उत्पादों को बढ़ाने और उनके उत्पादों के व्यावसायिकरण में स्टार्ट-अप का समर्थन करके स्वदेशी नवाचारों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

डॉ. नीरज शर्मा

टीडीबी का अधिदेश

- स्वदेशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक अनुप्रयोग का प्रयास करने वाली या व्यापक घरेलू अनुप्रयोगों के लिए आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाने का प्रयास करने वाली औद्योगिक संस्थाओं और अन्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना;
- स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करने या वाणिज्यिक अनुप्रयोग के लिए आयातित प्रौद्योगिकी के अनुकूलन में संलग्न ऐसे अनुसंधान और विकास संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिसे केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो;
- ऐसे अन्य कार्य करना जो केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं।

स्थापना के बाद से टीडीबी द्वारा पोषित क्षेत्र:

टीडीबी क्षेत्र अज्ञेयवादी है और अब तक निम्नलिखित क्षेत्रों को व्यापक रूप से वित्त पोषित किया है :

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा 	दूरसंचार 	अभियांत्रिकी 
रसायन 	सूचना प्रौद्योगिकी 	रक्षा एवं नागर विमानन 
सड़क परिवहन 	ऊर्जा एवं अपशिष्ट उपयोग 	इलेक्ट्रॉनिक्स 
कृषि 	तस्त्र 	अन्य 

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की संरचना

(31 मार्च, 2021 के अनुसार)

<p>प्रो. आशुतोष शर्मा सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग</p>	पदेन अध्यक्ष
<p>डॉ. शेखर सी. मांडे सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग</p>	पदेन सदस्य
<p>डॉ. जी. सतीश रेड्डी सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग</p>	पदेन सदस्य
<p>डॉ. टी. वी. सोमनाथन सचिव, व्यय विभाग</p>	पदेन सदस्य
<p>डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग</p>	पदेन सदस्य
<p>श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा सचिव, ग्रामीण विकास विभाग</p>	पदेन सदस्य
<p>श्री प्रदीप गोयल अध्यक्ष, प्रदीप मेटल्स लिमिटेड, नवी मुंबई</p>	सदस्य
<p>सुश्री विनीशा पी. कार्यकारी निदेशक, अंतरराष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर</p>	सदस्य
<p>प्रो. देशदीप सहदेव परामर्शदाता, क्वाजर टेक्नोलॉजीस प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली</p>	सदस्य
<p>श्री साबू एम. जैकबे प्रबंधक निदेशक, कीटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड अर्नाकुलम, केरल</p>	सदस्य
<p>डॉ. नीरज शर्मा सचिव, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड</p>	पदेन सदस्य (सदस्य सचिव)

बोर्ड के सदस्य

(31 मार्च, 2021 तक)



प्रो. आशुतोष शर्मा
अध्यक्ष टीडीवी और
सचिव, डीएसटी



डॉ. शेखर सी. मांडे



डॉ. जी. सतीश रेड्डी



डॉ. टी. वी. सोमनाथन



डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र



श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा



श्री प्रदीप गोयल



सुश्री विनीशा पी.



प्रो. देशदीप सहदेव

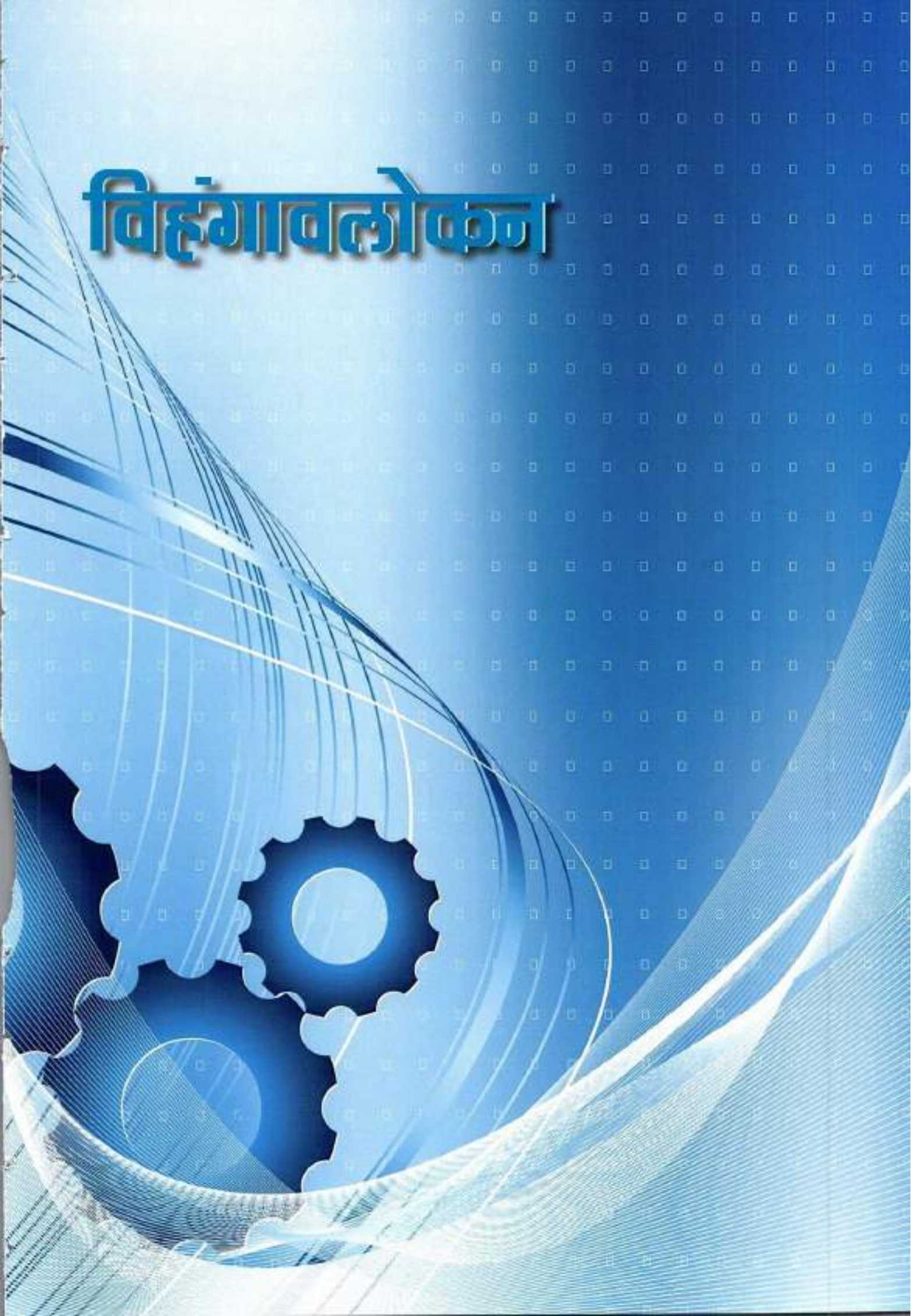


श्री साबू एम. जैकेव



डॉ. नीरज शर्मा

विहंगावलोकन



विहंगावलोकन

भारत सरकार ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास और वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन देने और व्यापक घरेलू अनुप्रयोगों के लिए आयातित प्रौद्योगिकी के अनुकूलन के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार 01 सितंबर, 1996 को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) का गठन किया। टीडीबी औद्योगिक प्रतिष्ठानों और इस तरह के विकास और वाणिज्यिक अनुप्रयोग का प्रयास करने वाली अन्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

टीडीबी द्वारा इस अधिनियम में प्रशासित प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग के लिए एक कोष के निर्माण को सक्षम बनाया गया। उक्त निधि कोष में अनुसंधान एवं विकास उपकर अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत औद्योगिक प्रतिष्ठानों से सरकार द्वारा एकत्रित अनुसंधान एवं विकास उपकर में से भारत सरकार से अनुदान प्राप्त की जाती है, जिसे 1995 में संशोधित किया गया था। इस अधिनियम से टीडीबी को किसी अन्य स्रोत से टीडीबी द्वारा प्राप्त सभी राशियों, निधि से दी गई राशि से की गई वसूली, और निधि कोष की राशि के निवेश से होने वाली किसी भी आय को क्रेडिट करके निधि कोष बनाने में सक्षम बनाया जाता है। वित्त अधिनियम, 1999 के माध्यम से आयकर उद्देश्यों के लिए कोष में दान के लिए पूर्ण कटौती को सक्षम बनाया गया।

केंद्र सरकार ने अपने आम बजट 2017-18 में, 01 अप्रैल, 2017 से 'अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986' को समाप्त कर दिया। सरकार ने वर्ष 1996-97 से 2016-17 की अवधि के दौरान, अनुसंधान एवं विकास उपकर के रूप में ₹ 7974.32 करोड़ एकत्र किए।

टीडीबी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के गैर-योजना बजट से सहायता अनुदान के रूप में 25 वर्षों (1996-97 से 2020-21) की अवधि में ₹ 987.47 करोड़ की संचयी राशि प्राप्त हुई। इसके अलावा, टीडीबी को वित्त वर्ष 2019-20 में "फाइटिंग कोविड-19" के विशिष्ट उद्देश्य के लिए अलग से में ₹ 75.00 करोड़ की अनुदान सहायता प्राप्त हुई।

1.0 वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रकार

टीडीबी से वित्तीय सहायता ऋण या इक्विटी और/या अनुदान के रूप में (असाधारण मामलों में) उपलब्ध है। कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत निगमित औद्योगिक प्रतिष्ठानों से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पूरे वर्ष स्वीकार किए जाते हैं।

1.1 ऋण

औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए वित्तीय सहायता 5 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर सॉफ्ट लोन के रूप में प्रदान की जाती है। ऋण के रूप में वित्तीय सहायता की सीमा बिना खर्च वाली परियोजना लागत का 50 प्रतिशत है। ऋण समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार संबंधित उपलब्धियों के कार्यान्वयन के अनुसार ऋण राशि किरतों में वितरित की जाती है। ऋण की सहमति के दौरान टीडीबी की परियोजना के तहत उत्पादों की बिक्री पर रॉयल्टी देय है।

कुछ मामलों में, टीडीबी द्वारा वित्त पोषित औद्योगिक प्रतिष्ठान के निदेशक मंडल में नामित निदेशक हो

सकते हैं। किसी परियोजना की कार्यान्वयन अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऋण और ब्याज कोलेटरल और गारंटी के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है। आम तौर पर, ऋण की अदायगी और ब्याज का भुगतान परियोजना के पूरा होने और एक वर्ष से अधिक की अधिस्थगन अवधि के बाद शुरू होता है। ऋण राशि आम तौर पर नौ, अर्ध वार्षिक किश्तों में बसूली योग्य होती है। पहली किश्त के पुनर्भुगतान तक का संचित ब्याज तीन साल की अवधि में वितरित किया जाता है। टीडीबी आवेदकों से प्रशासनिक, प्रक्रमण या प्रतिबद्धता शुल्क नहीं लेता है।

1.2 इक्विटी

टीडीबी, ऋण-इक्विटी अनुपात को ध्यान में रखते हुए, टीडीबी द्वारा मूल्यांकन की गई आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इक्विटी पूंजी के रूप में इसके प्रारंभ, स्टार्ट-अप और/या विकास चरणों में योगदान देता है। टीडीबी के पूर्ण बोर्ड द्वारा इक्विटी सदस्यता का निर्णय लिया जाता है। यह स्वीकृत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक है, बशर्ते ऐसा निवेश प्रमोटर्स द्वारा प्रदत्त पूंजी से अधिक न हो।

टीडीबी उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मौजूदा ऋण या इक्विटी को प्रतिस्थापित करने पर विचार नहीं करता है, जिन्होंने अन्य संस्थानों से इस तरह के वित्त प्राप्त किए हैं।

1.3 अनुदान

टीडीबी स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास में लगे औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। अनुदान की स्वीकृति का निर्णय पूर्ण बोर्ड द्वारा किया जाता है और राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए महत्व वाले असाधारण मामलों में प्रदान किया जाता है।

1.4 औद्योगिक प्रतिष्ठानों में टीडीबी का वित्तीय योगदान (1996-2021)

औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रति टीडीबी के वित्तीय योगदान का विवरण नीचे दिया गया है :

1.4.1 निम्न तालिका, टीडीबी के वित्तीय विधि और योगदान को दर्शाया जाता है (स्थापना से 31 मार्च, 2021 तक) :

(रु. करोड़ में)

विधि	*टीडीबी द्वारा स्वीकृत	टीडीबी द्वारा संवितरण
ऋण	1753.74	1553.72
इक्विटी	33.06	35.67
अनुदान	157.13	150.50
वैचर फंडस	285.00	258.13
कुल	2228.93	1998.02

* टीडीबी द्वारा 31.03.2021 को वास्तविक स्वीकृत राशि अतीत में कुछ मामलों में ऋण को इक्विटी में बदलने और वित्तीय सहायता की मात्रा में संशोधन, फोरक्लोजर और रद्द करने के कारण भिन्न हो सकती है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 तक, टीडीबी द्वारा किया गया वास्तविक संवितरण ₹ 1950.23 करोड़ था जिसमें ₹ 1506.16 करोड़ ऋण, ₹ 150.38 करोड़ अनुदान, ₹ 35.67 करोड़ इक्विटी के रूप में और ₹ 258.02 करोड़ वैचर फंड के रूप में शामिल हैं।

1.4.2 "कोविड-19 से निपटने" के आह्वान के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए टीडीबी का वित्तीय योगदान :

(रु. करोड़ में)

विधि	टीडीबी द्वारा स्वीकृत	टीडीबी द्वारा संवितरण
ऋण	3.25	2.12
अनुदान	7.65	1.39
कुल	10.90	3.51

2.0 क्षेत्र

टीडीबी क्षेत्र के प्रति अज्ञेयवादी है और इसने उद्योगों के लगभग सभी क्षेत्रों को वित्त पोषित किया है। स्थापना के बाद से, क्षेत्रवार और राज्यवार क्वरेज नीचे दिया गया है :

2.1 क्षेत्र-वार कवरेज (1996–2021)

टीडीबी की वित्तीय सहायता सभी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है। वर्ष 1996 में स्थापना के बाद से 31 मार्च, 2021 तक, टीडीबी ने अलग-अलग क्षेत्रों की

औद्योगिक प्रतिष्ठान के साथ कुल 373 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कुल परियोजना लागत ₹ 8488.56 करोड़ और टीडीबी की ₹ 2228.93 करोड़ की प्रतिबद्धता है।

निम्नलिखित तालिका में वर्ष 1996–97 में स्थापना के बाद से 31 मार्च, 2021 तक टीडीबी द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	समझौतों की संख्या	कुल लागत	टीडीबी प्रतिबद्धता
1	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	105	2083.47	612.92
2	अभियांत्रिकी	71	706.57	259.95
3	सूचना प्रौद्योगिकी	47	461.00	172.31
4	रसायन	26	236.80	84.69
5	कृषि	27	217.48	69.85
6	दूरसंचार	12	99.88	37.85
7	सड़क परिवहन	10	527.04	81.20
8	ऊर्जा और अपशिष्ट उपयोग	10	140.10	59.61
9	इलेक्ट्रॉनिक्स	4	52.56	17.75
10	रक्षा एवं नागर विमानन	10	648.83	229.95
12	वस्त्र	1	689.00	250.00
13	अन्य			
	(क) बैंकर फंडस	11	2463.00	285.00
	(ख) एसटीईपी-टीबीआई	35	35.00	35.00
	(ग) सीआईआई	1	0.83	0.50
	घ) मिलेनियम एलायंस	1	112.00	25.00
	ड) ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एलायंस	1	15.00	7.35
	च) इनवेंट कार्यक्रम	1		
	कुल	373	8488.56	2228.93

टीडीबी द्वारा समर्थन बड़े पैमाने पर बाजार संचालित और अपने सभी नए उद्यमों और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी उन्मुख है।

2.2 राज्य-वार कवरेज (1996-2021)

वर्ष 1996-2021 के दौरान हस्ताक्षरित समझौतों का राज्य-वार वितरण (कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के आधार पर) नीचे दिया गया है :

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	समझौतों की संख्या	कुल लागत	टीडीवी की प्रतिबद्धता
1	असम	1	18.31	8.20
2	आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	88	1719.36	557.08
3	कर्नाटक	49	1040.78	361.59
4	महाराष्ट्र	51	1641.75	456.35
6	तमिलनाडु	38	321.87	101.56
7	दिल्ली	24	313.10	115.36
8	गुजरात	14	149.06	45.94
9	पश्चिम बंगाल	10	137.39	57.57
10	उत्तर प्रदेश	12	94.77	50.44
11	मध्य प्रदेश	7	155.92	42.20
12	हरियाणा	7	47.57	19.48
13	पंजाब	7	91.79	21.98
14	छत्तीसगढ़	4	43.75	16.50
15	केरल	5	21.63	8.15
16	हिमाचल प्रदेश	1	6.24	1.90
17	जम्मू और कश्मीर	1	5.65	2.38
18	मणिपुर	1	7.94	2.70
19	पुदुच्चेरी	1	5.83	1.90
20	राजस्थान	1	35.77	3.00
21	ओडिशा	1	4.25	1.80
22	अन्य - सहित :			
	उद्यम निधि	11	2463.00	285.00
	एसटीईपी-टीबीआई	35	35.00	35.00
	सीआईआई	1	0.83	0.50
	मिलेनियम एलायंस	1	112.00	25.00
	ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एलायंस	1	15.00	7.35
	इनपैट कार्यक्रम	1		
	कुल योग	373	8488.56	2228.93

3.0 टीडीबी को परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना

टीडीबी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठान को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। वित्तीय सहायता और अन्य विवरण प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्रारूप टीडीबी की वेबसाइट (<http://tdb.gov.in>) पर उपलब्ध "परियोजना के वित्तपोषण के दिशानिर्देश" में दिया गया है।

औद्योगिक प्रतिष्ठान @<http://e-techcom.tdb.gov.in> के माध्यम से वर्ष भर में किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

4.0 परियोजना प्रस्तावों का प्रसंस्करण

प्राप्त आवेदनों को तकनीकी और वित्तीय दोनों पक्षों के कार्यक्षेत्र विशेषज्ञों वाली समिति द्वारा व्यापक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। इस व्यापक प्रक्रिया का विवरण नीचे दिया गया है :

4.1 मूल्यांकन मानदंड

आवेदन के वैज्ञानिक, तकनीकी, वाणिज्यिक और वित्तीय गुणों के लिए इसका मूल्यांकन इस किया जाता है। मूल्यांकन के इस प्रकार हैं :

- प्रस्ताव की विशिष्टता और नवीन विषय वस्तु
- सुदृढ़ता, वैज्ञानिक गुणवत्ता और तकनीकी योग्यता;
- व्यापक अनुप्रयोग की संभावना और व्यावसायीकरण से प्राप्त होने वाले प्रत्याशित लाभ;
- प्रस्तावित प्रयास की पर्याप्तता;
- प्रस्तावित कार्रवाई नेटवर्क में अनुसंधान एवं विकास संस्थान (संस्थाओं) की क्षमता;
- उद्यम की संगठनात्मक और वाणिज्यिक क्षमता जिसमें इसके आंतरिक प्राप्ति शामिल हैं;
- प्रस्तावित लागत और वित्तपोषण पैटर्न की युक्तिसंगतता;
- मापने योग्य उद्देश्य, लक्ष्य और उपलब्धियां;
- उद्यमी की पृष्ठभूमि।

4.2 गोपनीयता और पारदर्शिता

टीडीबी का मानना है कि गोपनीयता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक प्रस्ताव एक वाणिज्यिक प्रस्ताव है जिसमें एक नया उत्पाद या प्रक्रिया शामिल है। इसलिए मूल्यांकन के दौरान संबंधित प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है।

साथ ही, ऐसे मामलों में जहां आवेदक ने उल्लेख किया है कि परियोजना प्रस्ताव में प्रदान की गई कुछ जानकारी पूरी तरह से गोपनीय है की वहां समिति भी इसका सम्मान करती है।

4.3 आवेदन की प्रारंभिक जांच

एक विधिवत गठित प्रारंभिक जांच समिति (आईएससी) वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक रूप से, इसकी पूर्णता, परियोजना के उद्देश्य, एवं प्रौद्योगिकी आदि के दृष्टिकोण से जांच करती है।

समिति की संरचना में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों / संगठनों के तकनीकी और वित्तीय डोमेन विशेषज्ञ शामिल हैं। प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव पर अधिक स्पष्टता के लिए आवेदकों और/या प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को समिति के समक्ष एक विस्तृत प्रस्तुति देने का मौका दिया जाता है।

समिति के सुझाव / टिप्पणियों के अनुसार, यदि मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त जानकारी / विवरण या और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है यह जानकारी मांगी जाती है।

यदि परियोजना प्रस्ताव टीडीबी की वित्तीय सहायता के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो आईएससी आवेदक को लिखित कारण प्रदान करने के बाद आगे की प्रक्रिया के लिए आवेदन की सिफारिश नहीं कर सकता है।

4.4 परियोजना मूल्यांकन समिति (पीईसी)

आईएससी की सिफारिशों के आधार पर, आवेदन को परियोजना मूल्यांकन समिति (पीईसी) को परियोजना स्थल के दौरे सहित अधिक विस्तृत आंकलन और मूल्यांकन के लिए भेजा जाता है। प्रत्येक परियोजना के लिए परियोजना की प्रकृति को ध्यान में रखते

हुए एक पीईसी का गठन किया जाता है।

पीईसी में परियोजना के निष्पक्ष और स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए टीडीबी के बाहर एवं से संबंधित क्षेत्रों के कार्यक्षेत्र विशेषज्ञ (वैज्ञानिक और तकनीकी और वित्तीय) शामिल किये जाते हैं। ये विशेषज्ञ (सेवारत या सेवानिवृत्त) सरकारी विभागों, अनुसंधान एवं विकास संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग, उद्योग संघों, वित्तीय संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित हो सकते हैं।

आवेदक को प्रौद्योगिकी प्रदाता (यदि कोई हो) के साथ परियोजना के वैज्ञानिक, तकनीकी, विपणन, वाणिज्यिक और वित्तीय पहलुओं पर उक्त समिति के समक्ष एक विस्तृत प्रस्तुति देने का उचित अवसर दिया जाता है, ताकि परियोजना और कंपनी से विभिन्न संबंधित मुद्दों पर गहन जानकारी प्रदान की जा सके।

4.5 वित्तीय सहायता का अनुमोदन

उक्त पीईसी की सिफारिशों को आगे अध्यक्ष, टीडीबी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। पीईसी द्वारा अनुशंसित सभी परियोजना प्रस्ताव जहां टीडीबी की सहायता ₹ 10.00 करोड़ से अधिक है, तीसरे पक्ष के उचित उद्यम के लिए संसाधित किए जाते हैं।

पीईसी इनपुट के साथ-साथ तीसरे पक्ष के उचित उद्यम की रिपोर्ट को उनके अनुमोदन के लिए बोर्ड के सामने रखा जाता है। शेष अनुशंसित मामलों को उनके अनुमोदन के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी के पास भेज दिया जाता है।

4.6 निगरानी और समीक्षा

टीडीबी द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत ऋण समझौते के अनुसार पूर्व-निर्धारित उपलब्धि के अनुपालन पर आधारित किस्तों में लाभार्थियों को अनुमोदित वित्तीय सहायता वितरित की जाती है।

परियोजना निगरानी समिति (पीएमसी) द्वारा समय-समय पर परियोजना की निगरानी की जाती है। पीएमसी में वैज्ञानिक/तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञ होते हैं।

5.0 सक्रिय भूमिका

औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य एजेंसियों से प्राप्त आवेदनों का उत्तर देने के अलावा, टीडीबी प्रौद्योगिकी विकास और वाणिज्यीकरण के लिए व्यापक समर्थन सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाता है।

अपने अधिदेश के तत्वावधान में, टीडीबी ने विभिन्न पहलों के माध्यम से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास और वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहित किया है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

5.1 वेंचर कैपिटल फंड वीसीएफ में भागीदारी:

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने महसूस किया कि कई तकनीकी परियोजनाएं वित्तीय संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों की पारंपरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। वाणिज्यीकरण के लिए सीधे स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का समर्थन करने के अलावा, टीडीबी ने प्रौद्योगिकी केंद्रित वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य संस्थानों के साथ नेटवर्किंग की आवश्यकता महसूस की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्याप्त फंड की कमी नवीन और तकनीकी रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए एक बाधा नहीं है।

इस प्रकार टीडीबी ने नवाचार और नवीन उत्पादों/सेवाओं वाले एसएमई के माध्यम से प्रारंभिक चरण के उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए वीसीएफ में भाग लिया। टीडीबी की प्रेरणा और भागीदारी के परिणामस्वरूप उद्यम पूंजीपतियों ने टीडीबी के मिशन के लिए अपनी सहायता की रूपरेखा तैयार की। बोर्ड ने वीसीएफ में टीडीबी की भागीदारी को विशेष रूप से एमएसएमई/एसएमई श्रेणी में नवाचार और नवीन उत्पादों/सेवाओं वाली प्रौद्योगिकी कंपनियों का समर्थन करने के लिए टीडीबी के अधिदेश के भौगोलिक प्रसार को बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया।

टीडीबी की पहल से वेंचर कैपिटलिस्ट / प्राइवेट इक्विटी निधियों को बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी-आधारित परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए आने का विश्वास मिला है, जो उन क्षेत्रों पर स्पष्ट जोर देते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास चालक हैं।

5.2 इन्क्यूबेटर में स्टार्ट-अप के लिए

मूल सहायता

वर्ष 2005 में, टीडीबी ने युवा उद्यमियों को प्रारंभिक चरण/स्टार्ट-अप वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी उद्यम विचारों को विकसित करने और अपने विचारों को विकास के तहत लाने और अंत में बाजार तक पहुंचने के लिए मूल सहायता योजना की स्थापना की। प्रस्तावित सहायता को प्रौद्योगिकियों के विकास और वाणिज्यीकरण के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए उपयोग किया। यह योजना डीएसटी के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड (एनएसटीईडीबी) द्वारा प्रशासित विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क/प्रौद्योगिकी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स (एसटीईपी/टीबीआई) में इन्क्यूबेटेड स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।

31 मार्च 2018 तक, टीडीबी ने 35 टीबीआई और एसटीईपी (4 टीबीआई/एसटीईपी को दो बार वित्तीय सहायता सहित) को ₹ 1.00 करोड़ की वित्तीय सहायता के साथ कुल ₹ 35.00 करोड़ की सहायता दी है।

इन इन्क्यूबेटर्स ने दूरसंचार, आईटी, रोबोटिक्स, कृषि, इंस्ट्रुमेंटेशन, इंजीनियरिंग, पर्यावरण, फार्मा, खाद्य, सौर, वस्त्र और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अपनी परियोजना के प्रसार के लिए कई इन्क्यूबेटियों को सहायता प्रदान की है। योजना अच्छी तरह से आगे बढ़ी और कई उद्यमियों को अप-स्केलिंग और संबंधित कार्यों में लाभ हुआ। इसके जरिए इन्क्यूबेटर्स द्वारा इन्क्यूबेशन फंड का एक कोष बनाने में भी सुविधा हुई।

5.3. अंतरराष्ट्रीय सहयोग

5.3.1 बीपीआई-फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन

टीडीबी ने बीपीआईफ्रांस फ्रांस के साथ अपने तकनीकी सहयोग को जारी रखा गया, पूर्व में ओएसईओ, फ्रांस ने टीडीबी और बीपीआईफ्रांस के बीच नए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के साथ-साथ सीईएफआईपीआरए के साथ प्रबंध भागीदार के रूप में अपना तकनीकी सहयोग जारी रखा। इस समझौते पर 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे

और यह 5 साल की अवधि के लिए वैध है।

इस समझौते में फ्रांस और भारत की कंपनियों, संगठनों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में तकनीकी आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान और समन्वित उपायों की स्थापना से संबंधित गतिविधियों को पूरा किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैमानिकी, मोटर वाहन और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर प्रस्तावों को निधि देना है।

5.3.2 अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग

(डीएफआईडी), यूके के साथ समझौता ज्ञापन

टीडीबी ने डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी), यूके के साथ साझेदारी में वित्त वर्ष 2015-16 में इनोवेटिव वेंचर्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर डेवलपमेंट (इनवेंट) कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम को तकनीकी और प्रक्रिया उन्मुख दोनों समावेशी नवाचार समाधानों का समर्थन करने के लिए एक मंच बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसका निम्न आय वर्ग के लोगों पर सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ता है, जिसे बॉटम ऑफ पिरामिड (बीओपी) के रूप में भी जाना जाता है। समर्थन में शामिल है, लेकिन भारत के 8 निम्न आय वाले राज्यों (एलआईएस) उ. प्र., म. प्र., विहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल) में वित्त पोषण, गहन सलाह, ज्ञान और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तक पहुंच, समर्थन सेवाओं और संगत नेटवर्क के प्रावधान तक सीमित नहीं है।

अंतिम उद्देश्य उपर्युक्त 8 एलआईएस में प्रभाव निवेश के लिए व्यवहार्य सामाजिक उद्यम पाइपलाइन बनाना; 8 निम्न आय वाले राज्यों में लाभ के लिए तैयार 50 निवेश उत्पन्न करना; इन 8 निम्न आय वाले राज्यों में 160 उद्यमियों का समर्थन करना था।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में टीडीबी और मेसर्स विलग्रो इनोवेशन फाउंडेशन (वीआईएफ) के बीच एक समझौते को निष्पादित किया गया था, जिसमें विलग्रो को भारत के 8 एलआईएस में प्रभाव निवेश के लिए एक व्यवहार्य सामाजिक उद्यम (लाभ के लिए)

पाइपलाइन बनाने के उद्देश्य से इंक्यूबेटर समर्थन प्रदान करने के लिए प्रमुख इनक्यूबेटर के रूप में कार्य करने के लिए चुना गया था। वीआईएफ ने सीड पर अभिनव व्यवसायों को हाथ में लेने के लिए एलआईएस में चार इंक्यूबेटर्स अर्थात आईआईएम कलकत्ता इनोवेशन पार्क (आईआईएमसीआईपी), भुवनेश्वर (केआईआईटी टीबीआई) में केआईआईटी टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर, आईआईटी कानपुर (एसआईआईसी आईआईटीके) में एसआईडीबीआई इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर और स्टार्टअप ओएसिस (सीआईआईई, आईआईएम अहमदाबाद और आरआईआईसीओ की एक पहल) का समर्थन किया या उद्यम विकास के शुरुआती चरणों में जो व्यावसायिक रूप से सफल होने के साथ-साथ भारत के एलआईएस में पिरामिड के निचले हिस्से को लाभान्वित करता है।

5.4 राष्ट्रीय सहयोग :

5.4.1. वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर

(डब्ल्यूडब्ल्यूएफ)-इंडिया फॉर क्लाइमेट सॉल्वर पार्टनर के साथ समझौता ज्ञापन नवाचार में भारत की मजबूती को ध्यान में रखते हुए, जिसमें इसे ग्लोबल क्लीनटेक इनोवेशन इंडेक्स 2012 में 12वें स्थान पर रखा गया है, टीडीबी ने 21 मई 2012 को डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए क्लाइमेट सॉल्वर प्लेटफॉर्म में शामिल होने का फैसला किया।

भारत में, टीडीबी के अलावा, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), न्यू वेंचर्स इंडिया, सेंटर फॉर इनोवेशन इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (आईआईएम अहमदाबाद) और स्काई क्वेस्ट टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

5.4.2. प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (टाइफेक) के साथ समझौता ज्ञापन

टीडीबी और प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और आंकलन परिषद (टीआईएफएसी) ने डीएसटी के तहत एक स्वायत्त निकाय ने 10 फरवरी, 2018 को "परिवर्तनकारी तकनीकी नवाचार" पर एक समझौता

ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य नवीन प्रौद्योगिकियों की खोज करना, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यीकरण करना और ऐसी तकनीकों का व्यावसायीकरण करने वाली कंपनियों में निवेश करना है। सहयोग के क्षेत्रों और दायरे में शामिल हैं :

- निवेश प्रवृत्तियों के साथ उभरती (मुख्य बल) प्रौद्योगिकियों / तकनीकी क्षेत्रों की खोज और उन्हें चलाने वाली ताकतें;
- उन प्रौद्योगिकियों की पहचान करना जो सामाजिक और आर्थिक वातावरण को बदलने के साथ-साथ देश के आगे बढ़ते युवाओं के लिए तत्काल, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक आधार पर रोजगार पैदा करने की क्षमता रखते हैं;
- प्रौद्योगिकी को आसानी से अपनाने के लिए नीतिगत संरचना का विकास करना; पहचान किए गए कार्यक्षेत्र के लिए राष्ट्र में इसके व्यावसायीकरण के लिए स्कैलिंग और विनिर्माण।

5.4.3. इनोवेटिव चेंज कोलैबोरेटिव इंडिया ऑर्गनाइजेशन (आईसीसीओ) के साथ समझौता ज्ञापन

टीडीबी और इनोवेटिव चेंज कोलैबोरेटिव (आईसीसीओ) इंडिया ऑर्गनाइजेशन, भारत में काम कर रहे एक डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन ने 6 मार्च, 2018 को "ट्रांसफॉर्मेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी बिजनेस सॉल्यूशंस" पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य नवीन कृषि प्रौद्योगिकियों के लिए स्काउट, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण और कंपनियों में निवेश करना है, जो किसानों की आय को दोगुना करने की क्षमता प्रदर्शित करेगा। सहयोग के क्षेत्रों और दायरे में शामिल हैं :

- फसल-पूर्व कार्यक्षेत्र, संबद्ध कृषि, फसल-पश्चात कार्यक्षेत्र में संगत कृषि प्रौद्योगिकी व्यवसाय समाधानों की खोज;
- उन प्रौद्योगिकियों और व्यावसायिक समाधानों की पहचान करना जो ग्रामीण आर्थिक वातावरण को बदलने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं और साथ ही देश के ग्रामीण युवाओं के लिए तत्काल, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक आधार पर रोजगार पैदा करते हैं।
- व्यावसायिक और वित्तीय व्यवहार्यता के लिए

उनकी प्रौद्योगिकी तत्परता और व्यवसाय मॉडल का मूल्यांकन करके किसानों की आय के स्तर में वास्तव में सुधार करने के लिए पहचाने गए कार्यक्षेत्र में इच्छुक कृषि-तकनीकी व्यवसायों की क्षमता का आकलन करना।

5.4.4. पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के साथ समझौता ज्ञापन
टीडीबी और पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने 25 अप्रैल, 2018 को राष्ट्रीय महत्व की उभरती प्रौद्योगिकियों / तकनीकी क्षेत्रों जैसे कि कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य देखभाल और फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, पानी और अपशिष्ट से ऊर्जा, ऑटोमोबाइल आदि और उन्हें चलाने वाले कारकों की पहचान करना; प्रौद्योगिकी को आसानी से अपनाने, उन्नयन और विनिर्माण के लिए नीतिगत संरचनाओं को विकसित करने के लिए इसके व्यावसायीकरण के लिए अग्रणी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों संगठन प्रौद्योगिकी-संचालित परियोजनाओं वाले उद्योगों की पहचान करने में सहयोग कर रहे हैं, जिनके सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ हो सकते हैं और तत्काल, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक आधार पर रोजगार पैदा कर सकते हैं।

5.4.5. एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) के साथ समझौता ज्ञापन

टीडीबी और एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने 3 मई, 2018 को राष्ट्रीय महत्व की उभरती प्रौद्योगिकियों / तकनीकी क्षेत्रों जैसे फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण और निदान, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ऑटोमोबाइल और उन्हें चलाने वाले कारकों की पहचान; प्रौद्योगिकी को आसान अंगीकार करने, उन्नयन और विनिर्माण के लिए नीतिगत संरचना को विकसित करने के लिए इसके व्यावसायीकरण के लिए आगे बढ़ने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों संगठन तत्काल, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक

आधार पर व्यावसायिक परिणामों के साथ प्रोटोटाइप प्रौद्योगिकियों / प्रौद्योगिकी संचालित परियोजनाओं वाली कंपनियों की पहचान करने के लिए संगोष्ठी, सेमिनार और परियोजना-लेखन कार्यशालाओं के माध्यम से निकट सहयोग में काम कर रहे हैं।

5.4.6. जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरैक) के साथ समझौता ज्ञापन
"स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण" के लिए विभिन्न उद्योग सहायक संगठनों के बीच तालमेल लाने के लिए, 7 सितंबर, 2018 को जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरैक) और प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) के बीच एक सहज तरीके से जैव चिकित्सा / जैव प्रौद्योगिकी नवाचार, ट्रांसलेशन और वाणिज्यीकरण के लिए एक वैश्विक और राष्ट्रीय परिस्थितिकी तंत्र बनाने और बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

सहयोग के क्षेत्र और दायरे में शामिल हैं :

- बाइरैक और टीडीबी नवाचार और व्यावसायीकरण अंतर को पूरा करने के लिए संयुक्त प्रयासों के लिए संयुक्त अंतर-संगठनात्मक तंत्र को सक्षम करेंगे।
- जैव प्रौद्योगिकी परियोजनाओं पर पारस्परिक रूप से सहमत है जो एक सहकारी शासन संरचना की स्थापना द्वारा निर्बाध मूल्यांकन और वित्त पोषण सहायता के विचार के लिए संबंधित संगठनात्मक दायरे में आ सकते हैं।
- पक्षकार प्रभावी निधिकरण जुटाने और प्रौद्योगिकी तत्परता अंतराल को कम करने के लिए अपनी-अपनी संगठनात्मक ताकत से लाभ उठाने के लिए एक तालमेल बनाएंगे।
- एमओयू की संचालन अवधि के संबंध में, वित्तीय दायित्वों और सहयोग की सीमा के अनुसार आपसी समझ के आधार पर क्रॉस रेफरेंस के लिए परियोजनाओं का निर्णय लिया जाएगा।
- इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से पक्षकार संयुक्त पहल की प्राप्ति के लिए ज्ञान आधार, आंतरिक प्रक्रियाओं और परियोजना इनपुट को साझा करने के लिए संयुक्त रूप से सहमत हुए हैं।

5.5. गठबंधन

5.5.1 ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एलायंस (जीआईटीए)

व्यापार और उद्योग पर प्रधान मंत्री परिषद के परिणाम के रूप में, भारत के औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के त्वरण का समर्थन करने के लिए, ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एलायंस (जीआईटीए) की स्थापना 2011 में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार के बीच पीपीपी संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी।

जीआईटीए एक ऐसा नवाचारी मंच है जहां प्रौद्योगिकी अंतराल को मैप किया जाता है, दुनिया भर में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन किया जाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त तकनीकी-कार्यनीतिक सहयोगी साझेदारी बनाता है। जीआईटीए प्रभावी मेचमेकिंग और सहयोगी औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए औद्योगिक और संस्थागत भागीदारों को जोड़ा जाता है, जिससे प्रौद्योगिकी विकास/अधिग्रहण/अनुकूलन/तैनाती के लिए वित्त पोषण की सुविधा मिलती है।

पिछले कुछ वर्षों में, जीआईटीए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईआईटीवाई), भारी उद्योग विभाग (डीएचआई), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई) की साझेदारी के तहत विभिन्न राष्ट्रीय और द्विपक्षीय औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण परियोजनाओं का सफलतापूर्वक प्रबंधन कर रही है। जीआईटीए ने नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए यूरोपीय आयोग जैसे बहुपक्षीय निकायों के साथ भी सहयोग किया है।

इन हस्तक्षेपों में भारत की तकनीकी आकांक्षाओं के लिए राष्ट्रीय सार्थकता के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जैसे, सस्ती स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा और

परिवहन सहित स्वच्छ प्रौद्योगिकी, उन्नत विनिर्माण, पूंजीगत सामान क्षेत्र, रक्षा और एयरोस्पेस, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और निर्माण (ईएसडीएम), जल प्रौद्योगिकी (जल शोधन, विलवणीकरण, सिंचाई प्रौद्योगिकी, अपशिष्ट जल उपचार और प्रबंधन सहित), आदि।

जीआईटीए ने जीआईटीए इनोवेशन एक्सचेंज (जीआईएक्ससी) के साथ भारतीय इनोवेशन इकोसिस्टम के साथ अपने जुड़ाव को व्यापक और औपचारिक बनाया। जीआईएक्ससी एक अनूठा, आभासी मंच है जो नवाचार स्पेक्ट्रम में अभिकारकों के लिए तकनीकी साझेदारी, प्रौद्योगिकियों, आईपी सेवाओं और नवाचार के लिए वित्त के लिए विश्वसनीय कनेक्शन बनाने का प्रयास करता है।

5.5.2 मिलेनियम एलायंस (एमए)

मिलेनियम एलायंस (एमए) कार्यक्रम नवाचारों की पहचान, परीक्षण और पैमाने के लिए एक मंच के रूप में 2011 में टीडीबी, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) और फंडेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था, जो पिरामिड (बीओपी) स्तर के निम्न में सुधार लाने वाले है। यह गठबंधन स्वास्थ्य, बुनियादी शिक्षा, पानी और स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा/कृषि और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक विकास के लिए एक नवाचार साझेदारी के रूप में बनाया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नवाचार का लाभ बीओपी आबादी को मिले। बाद में, इस प्लेटफॉर्म को यूके के डीएफआईडी, आईसीसीओ कोऑपरेशन, आईसीआईसीआई फाउंडेशन फॉर इनक्लूसिव ग्रोथ, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और फेसबुक ने ज्वाइन किया।

प्रत्येक एमए भागीदार सामाजिक उद्यमों का समर्थन करने के अंतिम उद्देश्य के साथ वित्तीय और ज्ञान आधारित संसाधनों को साथ लाता है जो परिवर्तनकारी परिवर्तन ला सकते हैं। एमए भारत और दुनिया भर में बीओपी आबादी को लाभान्वित करने वाली विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत में विकसित और परीक्षण किए जा रहे नवाचारी समाधानों

की पहचान करने और स्केल करने के लिए भारतीय रचनात्मकता, विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाने के लिए एक समावेशी मंच था। एमए विभिन्न सामाजिक नवप्रवर्तनकर्ताओं, परोपकारी संगठनों, सामाजिक उद्यम पूंजीपतियों, एंजेल निवेशकों, दाताओं, सेवा प्रदाताओं और कॉर्पोरेट नींवों को एक साथ लाने के लिए एक नेटवर्क था ताकि नवप्रवर्तकों को वित्तीय और अन्य सहायता को प्रोत्साहित किया जा सके।

इन 5 वर्षों की अवधि के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड स्थापित किया गया था जिसमें से ₹ 25.00 करोड़ (₹ 5.00 करोड़ प्रति वर्ष) का योगदान दिया गया था। कार्यक्रम के तहत, नवप्रवर्तकों को बीज वित्त पोषण, अनुदान, ऊष्मायन, नेटवर्किंग अवसर, व्यापार सहायता, ज्ञान विनिमय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी जो इक्विटी, ऋण और अन्य पूंजी तक आगे पहुंच की सुविधा प्रदान करता है।

कार्यक्रम में वर्ष 2018-19 में अपने 5 दौर पूरे किए गए। इन दौर के माध्यम से, कार्यक्रम में ₹ 86.7 करोड़ के वित्त पोषण समर्थन के साथ सीधे 124 नवीन परियोजनाओं का समर्थन किया गया। इन परियोजनाओं से लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित हुआ है, किसानों की आय में वृद्धि की है, उन्हें प्रारंभिक ग्रेड शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, उनके घरों के लिए ऊर्जा, सस्ती और डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की है।

समर्थित उद्यम बाहरी निधि जुटाने के साथ-साथ व्यापक और स्थायी परियोजना कार्यान्वयन के लिए साझेदारी विकसित करने के लिए उत्प्रेरक निधि के रूप में दिए गए अनुदान का लाभ उठाने में सक्षम थे। एमए द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को भारत के 21 राज्यों में कार्यान्वित किया गया था। फंड द्वारा 11 देशों में हस्तक्षेप का भी समर्थन किया। एमए अफ्रीका (केन्या, रवांडा, युगांडा, इथियोपिया, बुर्किना फासो और मलावी) और दक्षिण एशिया (अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल) में अपने नवाचारों को दोहराने और स्केल करने के लिए 22 भारतीय कंपनियों का समर्थन करने के लिए अपनी तरह का एकमात्र कार्यक्रम है।

कार्यक्रम द्वारा दुनिया भर में सामाजिक क्षेत्र में उद्यमिता विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है।

5.6 प्रौद्योगिकी दिवस और राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति

5.6.1 प्रौद्योगिकी दिवस

प्रत्येक वर्ष 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन शक्ति (पोखरण-2) परमाणु परीक्षण के पांच परीक्षणों में से पहले की वर्षगांठ मनाने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जा रहा है जो 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया गया था।

इस दिन पहले स्वदेशी विमान हंसा -3 का बेंगलूर में परीक्षण किया गया था और भारत ने उसी दिन त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण फायरिंग भी किया था। इन सभी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने के लिए चुना गया था।

इस दिन दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व पर जोर दिया जाता है और इससे छात्रों को विज्ञान को कैरियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

इस दिवस के अवसर पर उद्योग से राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के साथ शक्तिशाली साझेदारी बनाने और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक बाजारों में प्रवेश पाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ ज्ञान नेटवर्क बनाने का आग्रह किया गया।

5.6.2 राष्ट्रीय पुरस्कार

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने और तकनीकी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए, टीडीबी ने राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की थी। यह पुरस्कार नवाचारी स्वदेशी प्रौद्योगिकी के सफल वाणिज्यीकरण के लिए विभिन्न उद्योगों को प्रदान किया जाता है।

यह पुरस्कार पहली बार 11 मई, 1999 को होने वाले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर दिया गया

था। मेसर्स शांता बायोटेक्निक प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा भारत के तत्कालीन माननीय प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रचारित किए गए "रीकॉम्बिनेंट डीएनए आधारित हेपेटाइटिस-बी टीका" के व्यावसायिक उत्पादन के लिए इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे।

इस पुरस्कार में ₹ 10.00 लाख का नकद पुरस्कार और एक ट्रॉफी प्रदान की गई। यदि अलग-अलग संस्थाओं द्वारा एक प्रौद्योगिकी विकसित और व्यावसायीकरण किया गया है, तो दोनों अलग-अलग पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र हैं। वर्ष 2016 में, पुरस्कार की राशि बढ़ाकर ₹ 25.00 लाख कर दी गई।

टीडीबी ने अगस्त 2000 में एक लघु क्षेत्र उद्योग (एसएसआई) इकाई के लिए ₹ 2.00 लाख का नकद पुरस्कार और एक ट्रॉफी की शुरुआत की, जिसने एक प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद का सफलतापूर्वक व्यावसायीकरण किया है। पहला एसएसआई पुरस्कार 11 मई 2001 को दिया गया था। वर्ष 2011 में पुरस्कार की संख्या और मात्रा क्रमशः तीन और ₹ 5.00 लाख तक बढ़ा दी गई थी।

वर्ष 2016 में, इस पुरस्कार का नाम बदलकर 'एमएसएमई अवार्ड' कर दिया गया और इसे बढ़ाकर ₹ 15.00 लाख कर दिया गया।

वर्ष 2017-18 के दौरान, टीडीबी ने ₹ 15.00 लाख के पुरस्कार की एक नई श्रेणी और व्यावसायीकरण की क्षमता वाली नई तकनीक का वादा करने के लिए स्टार्ट-अप के लिए एक ट्रॉफी की शुरुआत की।

11 मई 2017 से, प्रौद्योगिकी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में निम्नलिखित तीन श्रेणियों के पुरस्कार दिए जाते हैं :

- स्वदेशी प्रौद्योगिकी के सफल व्यावसायीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (01')- ₹ 25.00 लाख का नकद पुरस्कार और एक स्वदेशी प्रौद्योगिकी के सफल विकास और व्यावसायीकरण की दिशा में एक औद्योगिक संस्था को एक ट्रॉफी; यदि प्रौद्योगिकी विकासकर्ता और व्यावसायीकरण

करने वाले संगठन अलग हैं, तो प्रत्येक नकद पुरस्कार और ट्रॉफी के लिए पात्र है;

- प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद (03') के सफल व्यावसायीकरण के लिए एमएसएमई श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार - ₹ 15.00 लाख का नकद पुरस्कार और एक एमएसएमई को एक ट्रॉफी जिसने स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पाद का सफलतापूर्वक व्यावसायीकरण किया है;
- स्टार्ट-अप श्रेणी (01') के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार - ₹ 15.00 लाख का नकद पुरस्कार और व्यावसायीकरण की क्षमता वाली नई तकनीक का वादा करने के लिए एक ट्रॉफी।

* राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चयन समिति दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या में बदलाव कर सकती है या यदि प्रविष्टियां उपयुक्त नहीं पाई जाती हैं तो उनमें अंतर हो सकता है।

5.7 "प्रस्तावों के लिए आमंत्रण" जारी करना
बोर्ड एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाता है और समय-समय पर नीतियों के अनुसार विभिन्न कार्यनीतिक क्षेत्रों में टीडीबी समर्थन नवाचार-संचालित प्रौद्योगिकी केंद्रित परियोजनाओं के इरादे से स्थानीय उद्योग को परिचित करने के लिए महत्व के विभिन्न क्षेत्रों में "प्रस्ताव के लिए आमंत्रण" जारी करता है और भारत सरकार की पहल जैसे "मेक इन इंडिया", "स्टार्टअप इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" आदि।

5.8 विवाद समाधान समिति (डीआरसी)
टीडीबी की स्थापना के बाद से, कई मामलों को या तो प्रौद्योगिकी विफलता या व्यावसायीकरण विफलता के कारण तनावग्रस्त घोषित किया गया है। इन एनपीए / दबाव वाले मामलों, पूर्व-मुकदमेबाजी और मुकदमेबाजी के मामलों के कारण, बोर्ड ने 2015 के अंत में "विवाद समाधान समिति (डीआरसी)" का गठन करके ऐसे मामलों को संबोधित करने के लिए एक तंत्र शुरू किया।

डीआरसी का उद्देश्य कंपनियों को टीडीबी बकाया के

भुगतान से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। हालांकि, डीआरसी कहीं भी टीडीबी द्वारा पहले से शुरू की गई कानूनी कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करता है। डीआरसी की सिफारिशों को अनुमोदन के लिए बोर्ड के सामने रखा जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से, कई कंपनियों के साथ मुद्दों का समाधान किया गया है और वसूली की गई है।

5.9 परियोजना प्रस्तावों का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण

वर्ष 2017-18 से, टीडीबी आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को डिजिटल और पेपरलेस जमा करने का प्रयास कर रहा है, जो "डिजिटल इंडिया" की दिशा में एक रास्ता है। इस पहल ने कार्य प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता और दक्षता लाई। "परियोजना प्रस्तावों का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण" "परियोजना प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस)" @<http://www.e-techcom.tdb.gov.in/> के माध्यम से किया जाता है।

5.10 प्रदर्शनियां/सेमिनार

टीडीबी से उपलब्ध वित्तीय सहायता के बारे में उद्योग,

उद्यमियों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में जागरूकता पैदा करने के लिए, अन्य संगठनों के सहयोग से विभिन्न गतिविधियों जैसे परस्पर क्रिया बैठकें / प्रदर्शनियों में भागीदारी की गई।

5.11 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का निर्माण

कामकाज में पारदर्शिता लाने, व्यापक कनेक्टिविटी प्राप्त करने और वर्तमान परिदृश्य में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के महत्व पर विचार करने के लिए, टीडीबी ने अपने स्वयं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आवश्यकता महसूस की और अपने आधिकारिक पेज इस प्रकार बनाए :

फेसबुक : www.facebook.com/tdbgoi

लिंक्डइन : <https://www.linkedin.com/in/technology-development-board/>

ट्विटर : <https://twitter.com/tdbgoi>

इंस्टाग्राम : www.instagram.com/technologydevelopmentboard/



वर्ष एक
दृष्टि में

वर्ष एक दृष्टि में

वित्त वर्ष 2020-21 में, टीडीबी ने विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तेरह समझौते किए हैं। इन समझौतों के माध्यम से, टीडीबी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हुए ₹ 80.92 करोड़ की कुल परियोजना लागत में से ₹ 23.74 करोड़ ऋण और ₹ 7.30 करोड़ अनुदान के रूप में प्रतिबद्ध की गई है।

1.0 वर्ष 2020-21 में प्राप्त हुए आवेदन

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, टीडीबी को नियमित विधि के माध्यम से 29 आवेदन प्राप्त हुए और 235 आवेदन "फाइटिंग कोविड-19" प्रस्ताव के लिए आमंत्रण के माध्यम से प्राप्त हुए। इस आमंत्रण की घोषणा 23 मार्च, 2020 को की गई थी, जिसमें टीडीबी ने भारतीय कंपनियों और उद्यमों से प्रस्ताव/आवेदन आमंत्रित किए थे। इन 235 आवेदनों में से 114 आवेदन टीडीबी के वित्तपोषित दिशानिर्देशिका के अनुसार सही पाए गए। तो इस साल कुल 143 आवेदनों का मूल्यांकन किया गया।

1.1 क्षेत्रवार ब्यौरा :

इन 143 आवेदनों का क्षेत्रवार वितरण निम्नानुसार है :

(₹. करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	आवेदनों की संख्या	अनुमानित कुल लागत	टीडीबी से अपेक्षित राशि
1	स्वास्थ्य और चिकित्सा	80	1349.67	599.60
2	अभियांत्रिकी	4	141.48	63.06
3	सूचना प्रौद्योगिकी	42	254.08	108.21
4	रसायन	1	21.25	10.00
5	कृषि	3	75.13	10.87
6	दूर-संचार	1	19.79	3.10
7	सड़क परिवहन	2	27.40	12.45
8	ऊर्जा – और अपशिष्ट उपयोग	2	16.46	6.73
9	इलेक्ट्रॉनिक्स	8	111.40	43.80
	कुल	143	2016.66	857.81

1.2. राज्यवार ब्यौरा :

इन 143 आवेदनों का राज्यवार वितरण निम्नानुसार है :

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	आवेदनों की संख्या	अनुमानित कुल लागत	टीडीबी से अपेक्षित राशि
	कर्नाटक	40	267.65	129.55
2	नई दिल्ली	22	177.27	76.57
3	आंध्र प्रदेश / तेलंगाना	14	349.99	150.03
4	हरियाणा	3	201.35	55.00
5	महाराष्ट्र	26	562.27	251.10
6	गुजरात	1	7.10	1.00
7	तमिलनाडु	11	99.99	33.34
8	उत्तर प्रदेश	10	159.63	69.97
9	ओडिशा	2	0.77	0.32
10	मणिपुर	0	0.00	0.00
11	बिहार	1	1.18	0.52
12	झारखंड	1	0.15	0.15
13	पंजाब	2	70.43	10.10
14	पश्चिम बंगाल	5	12.03	5.89
15	गोवा	1	100.00	70.00
16	केरल	1	0.80	0.35
17	मध्य प्रदेश	1	1.33	1.33
18	राजस्थान	2	4.71	2.60
कुल		143	2016.66	857.81

2.0 वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान हस्ताक्षर किए गए समझौते

इस वर्ष टीडीबी ने विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ तेरह समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	कंपनी का नाम	परियोजना का नाम	क्षेत्र
1	मैसर्स मायलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, पुणे	मेन्यूफेक्चरिंग ऑफ टेस्टिंग किट टू डिटेक्ट कोविड कोरोना वायरस	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
2	मैसर्स थिंक टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पुणे	डिवलेपमेंट ऑफ लो कोस्ट एण्ड मोर एफिशियंट मास्क कोटेड विद एंटी वायरल एजेन्ट टू प्रोटेक्ट स्पेयरड एण्ड प्रोटेक्शन ऑफ कोविड-19 एण्ड अदर वाइरल इन्फेक्शनस	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

3	मेसर्स मेडजोम लाइफ साइंसज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	डिवलेपमेंट एण्ड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ फलयरोरसेंशिस बेस्ड रेपिड कोविड-19 डिटेक्शन किट	स्वास्थ्य और चिकित्सा
4	मेसर्स क्यूएनयू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलोर	कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ क्यून्यूस कआनटम टैकनोलॉजी सक्चोरिटी प्रोडेक्टस	सूचना प्रौद्योगिकी
5	मेसर्स एडवांस मैकेनिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बंगलोर	इन्डस्ट्रीयल आईओटी एनेबल्ड आईआर थर्मोग्राफी-बेस्ड टेम्प्रेचर स्केनर	अभियांत्रिकी
6	मेसर्स कोकोस्लैब्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, बंगलोर	अडवान्सड वीडियो अनेलेटिक्स फार लो-कोस्ट थर्मल कैमरास टू आईडेन्टीफाई परसन विद अबनॉर्मल बोडी टेम्प्रेचर इन पब्लिक प्लेसिस	अभियांत्रिकी
7	मेसर्स इवोबी ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, बंगलोर	पोर्टेबल अल्ट्रा-वाइलेट बेस्ड बॉक्स स्टेरिलाइजर एण्ड मोडयूलर मूवेबल अल्ट्रा-वाइलेट बेस्ड इनडोर रूम स्टेरिलाइजर	स्वास्थ्य और चिकित्सा
8	मेसर्स नैनोक्लीन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	नमोमारक सेमि ऑटोमेटिक एन95 प्रोडेक्शन मशीन	स्वास्थ्य और चिकित्सा
9	मेसर्स इनडीएनए लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, मुबनेश्वर	इनफीलिया-सोल्युशन फार पेरन्टहुड कम्प्रीहेंसिव जेनेटिक स्क्रीनिंग फॉर ओपटीमाइज्ड पेरनटिंग	स्वास्थ्य और चिकित्सा
10	मेसर्स साल्सिट टेकनोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	केएस, अ स्क्रीनिंग एण्ड मोनिटरिंग टूल फार कोविड-19	सूचना प्रौद्योगिकी
11	मेसर्स आईटोम इलेक्ट्रिक (आई) प्राइवेट लिमिटेड, कोयंबटूर	बैट्री पावर्ड कॉम्पेक्ट डिजीटल पोर्टेबल एक्स-रे मशीन	स्वास्थ्य और चिकित्सा
12	मेसर्स ब्रियोटा टेकनोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, पुणे	कोविड-19 मोनीट्रींग एण्ड नेगजमेंट सॉल्यूशन फार अकैक्टिड, क्यूरनटाईड और कॉ-मोरबीडिटी हाई रिस्क पेशन्ड टू अवाइड और डिसे लन्ग कोमप्लिकेशन्स इन ऑर्डर टू रिड्यूज केस फेटेलिटी रेट (सीएफआर)	स्वास्थ्य और चिकित्सा
13	मेसर्स आरसीसी लेबोरेटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	इस्टेब्लिशमेंट आफ स्पेसिक पैथोजन फ्री (एसपीएफ) लेबोरेट्रीज एनीमल ब्रीडिंग एण्ड टेस्टिंग फेसिलिट	स्वास्थ्य और चिकित्सा

3.0 संवितरण

टीडीबी ने वित्त वर्ष 2020-21 में चालू नई परियोजनाओं और अन्य योजनाओं के लिए ₹ 47.80 करोड़ की राशि का संवितरण किया। इसमें ऋण के रूप में ₹ 47.57 करोड़ अनुदान के रूप में ₹ 0.12 करोड़ और निवेश के लिए यूटीआई/अन्य वीसीएफ/आईटीवीयूएस के लिए ₹ 0.11 करोड़ शामिल थे।

टीडीबी ने "फाइटिंग कोविड-19" प्रस्तावों के लिए ₹ 3.51 करोड़ की राशि का संवितरण किया है, इसमें ₹ 2.12 करोड़ ऋण के रूप में और ₹ 1.39 करोड़ अनुदान के रूप में शामिल हैं।

4.0 पूर्ण की गई परियोजनाएं

टीडीबी द्वारा समर्थित निम्नलिखित कंपनियों ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अपनी परियोजना के पूरा होने की घोषणा की :

क्र. सं.	कंपनी का नाम	परियोजना का नाम	क्षेत्र
1	मेसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, बंगलोर	सेटिंग-अप डिफेंस मेन्यूफेक्चरिंग फेसिलिटी एट 50 ऐकर्स लैंड एट वेमागल इनडस्ट्रीज़ एरिया, कोलर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका	रक्षा एवं नागर विमानन
2	मेसर्स सॉफ्टटेक इंजीनियर्स लिमिटेड, पुणे	डिवलपमेंट एण्ड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ रूल बड्डी प्रोडक्ट (अर्थवाइल 'आर्कीटक्ट')	सूचना प्रौद्योगिकी

5.0 ऋण का निपटान/भुगतान

वर्ष के दौरान, टीडीबी द्वारा वित्तपोषित निम्नलिखित कंपनियों ने अपना ऋण चुकाया / अपने ऋण खाते का निपटान किया :

क्र. सं.	कंपनी का नाम	परियोजना का शीर्षक
1	मेसर्स बेसिक हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़	कॉमर्शियलाइजेशन आफ इण्डीजीनियस बोन ग्राफिटिंग टेक्नॉलोजी
2	मेसर्स आई2आई टेलीसोल्यूशंस एंड टेलीमेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड, बंगलोर	डिवलपमेंट एण्ड कॉमर्शियलाइजेशन आफ टेक्नॉलोजी फार अ टेलीपीएसीएसटीएम बेस्ड हेल्थकेयर एक्सचेंज फार इंटरनेट एण्ड मोबाइल बेस्ड हेल्थकेयर एक्सिस
3	मेसर्स सिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद	ग्रेडिंग एण्ड शोर्टिंग मशीन फार फ्रूट एण्ड वेजीटेबलस
4	मेसर्स सीकेम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई	डिवलपमेंट एण्ड कॉमर्शियलाइजेशन आफ (i) हाई टेम्प्रेचर रजिस्टेन्ट हाईड्रीड ईबीएक्सएल केबल विच इज रोडेन्ट, टर्मिटेड इनसेक्ट रजिस्टेन्ट फार यूज इन हाई रिस्क बिल्डिंग्स, रनिंग ट्रेनिंग एण्ड मेराइन अप्लीकेशन, एण्ड (ii) वाईट कलर संथेटिक कोटिड, इलेक्ट्रोन बीम कर्ड लीथर फार मेकिंग क्रिकेट बॉल
5	मेसर्स इंड-स्विफ्ट लेबोरेटरीज लिमिटेड, चंडीगढ़	सिटिंगअप ए प्रोजेक्ट फार कॉमर्शियलाइजेशन आफ एपीआई। द कम्पनी प्रोजेक्ट टू मेन्यूफेक्चर एपीआई नेमली: क्योशियापाईन, फूमारेट, रोपीनरोल एचसीआई, एरीपाईपराज़ोल, क्लोपीडोजरिल बिजीलेट, राइजड्रोनेट सोडियम, बन्लाफेक्साइन एचसीआई, डोनपीज़िल, नेटीग्लीनाइड एण्ड फल्यूसेस्टेटिन सोडियम

6.0 प्रौद्योगिकी दिवस

निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अंतर्गत निम्नलिखित विजेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार-2020 से सम्मानित किया गया है :

पुरस्कार श्रेणी	पुरस्कार विजेता (कंपनी का नाम)
स्वदेशी प्रौद्योगिकी के सफल वाणिज्यीकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार	<ul style="list-style-type: none"> एम/एस एल एण्ड टी स्पेशल स्टील एण्ड हेवी फोरिंग्स फार (टेक्नॉलोजी प्रोवाइडर - न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र) फार - "इंडीजीनियस टेक्नॉलोजी डिवलेपमेंट आफ लो अलोय स्टील हेवी फोरिंग्स फार 700 एम डब्ल्यू न्यूक्लियर पावर प्लान्ट स्टीम जनरेटर" एम/एस ओरगेनिक्स लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (टेक्नॉलोजी प्रोवाइडर - सीएसआईआर-इंडियन इन्स्टिट्यूट आफ केमिकल टेक्नॉलोजी, हेदराबाद, तेलंगाना) फार - "पी-टर्टब्यूटलटोल्यून्स एण्ड पी-टर्टब्यूटलबेन्ज़ोइयिक एसिड (फ्राम लेब टू पायलेट टू कॉमर्शियल स्केल)"
प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद के सफल वाणिज्यीकरण के लिए एमएसएमई श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार	<ul style="list-style-type: none"> एम/एस एकेएस इंफोरमेशन टेक्नॉलोजी सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली फार <ol style="list-style-type: none"> 1. एकेएस फोरेंसिक वर्कस्टेशन, 2. वेब एप्लीकेशन फायरवाल 3. एंटी-डीडीओएस सोल्यूशन एम/एस एसएपी लेजर टेक्नॉलोजी प्राइवेट लिमिटेड, चैन्नई, तमिलनाडू, फार 'मल्टी सीएससी लार्ज स्केल फॉर्म रेपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन (एलएसएफआरपी) विद इंडीजीनियस डिवलपड मल्टी एसएनसी कंट्रोलर एण्ड ऑटोकेमट्री सोफ्टवेयर' एम/एस कैनबायोसिस प्राइवेट लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र, फार 'स्पीड कमपोस्ट टीएम फार इन-सेतु एक्सीविलरेटिड एण्ड ससटेनेबल राइस स्ट्रॉ डीकम्पोज्ड (एएसआरएसडी)' एम/एस एलगलआर न्यूट्रॉ फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, थनजावूर, तमिलनाडू, फार 'वीगन ओमेगा-3 (एलगल डा ऑइल, एलगल डा पाउडर), ओमेगा-3 एनीमल फीड'
स्टार्ट-अप श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार	<ul style="list-style-type: none"> एम/एस आरएआर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली फार - 'इंडीजीनियस ऐक्टिव रीकोइल बफर सिस्टम एण्ड वाइब्रेशन कंट्रोल इक्युपमेंट फार डिफेंस, एरोस्पेस एण्ड सीविल एप्लीकेशन' एम/एस फायरहील वाचन्डकेयर प्राइवेट लिमिटेड, बेन्गलौर, कर्नाटका फार - "फब्रोहील - सिल्क प्रोटीन ड्रावड वाचन्ड ड्रेसिंग" एम/एस एलथीऑन टेक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, हेदराबाद, तेलंगाना "नोवल आरओ मेम्ब्रेन एण्ड प्रोसिस फार अल्ट्रा-थोर वाटर" एम/एस कंबीकोइल्स साइंस प्राइवेट लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - "नेच्यूरल एण्ड सेफ कलर फ्राम रिन्यूवेबल रिसयोरसिस एज एन अल्टरनेटिव टू हार्मफुल केमिकल कलरस यूज्ड इन ऑल इनडस्ट्रीज (ईजी: टेक्सटाईल, फूड, कॉस्मेटिक्स) एम/एस सिरामेड टेक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात "सीरा क्लमस" एम/एस नवेन्द्रा इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान - "जयपुर बेल्ट: एफीशियंट, एफोर्डेबल, अन-पावर्ड एण्ड लाईटवेट एक्जोस्केलटन फार स्पाईन एण्ड वेस्ट प्रोबलम्स"

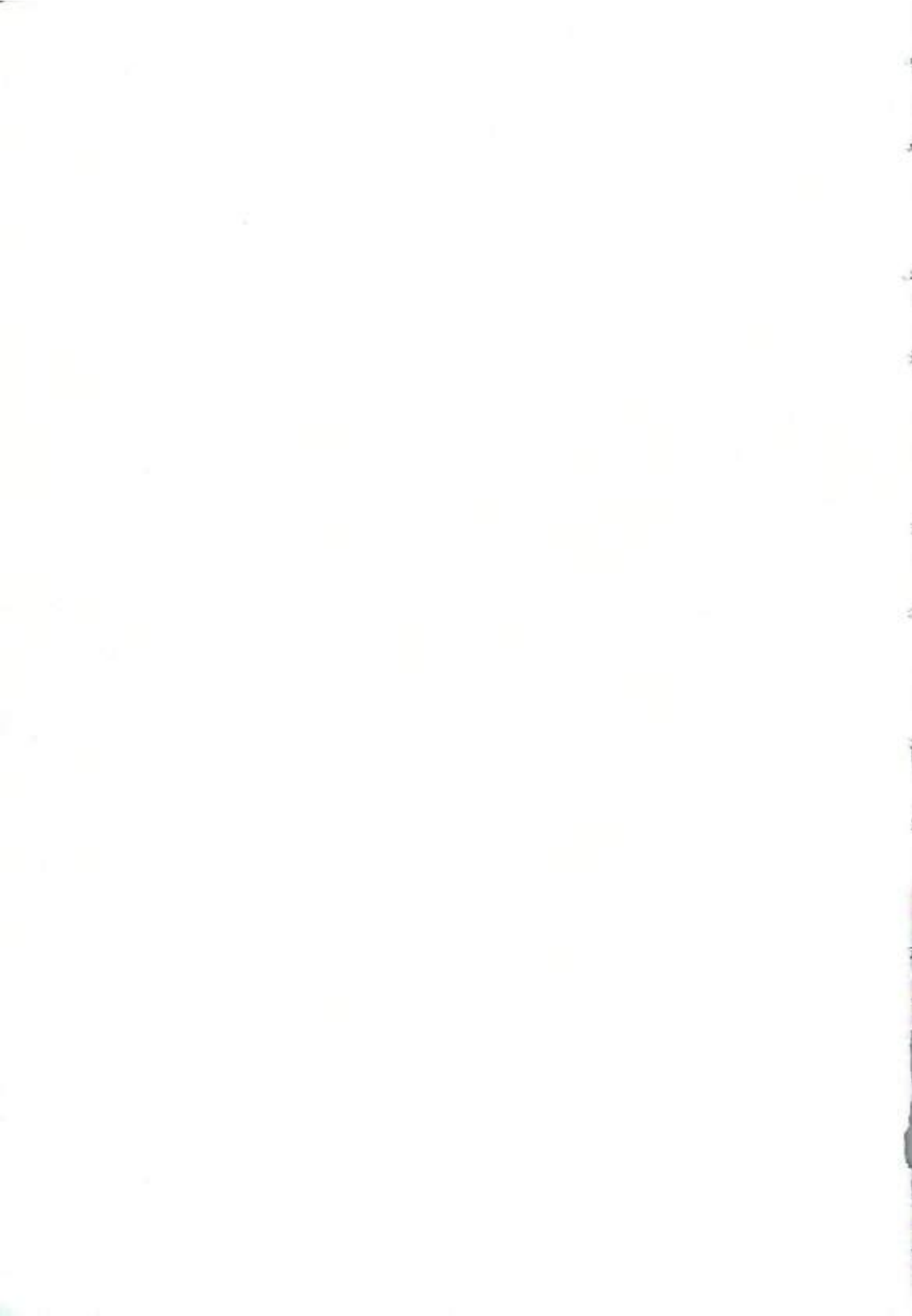
7.0 वेंचर कैपिटल फंडस (वीसीएफ) में भागीदारी

टीडीबी ने अब तक (31 मार्च, 2021 तक) अन्य निवेशकों के साथ 11 वेंचर कैपिटल फंडस में भाग लिया है, जहां अन्य निवेशकों से कुल 285.00 करोड़ की प्रतिबद्धता के साथ, अन्य निवेशकों से 2281.77 करोड़ (निवेश प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत) के कुल निधियों का लाभ उठाते हुए अपने प्रतिबद्ध संवितरण के लिए 258.13 करोड़ का वितरण किया है तथा इन निधियों की निकासी आय से 225.55 करोड़ की राशि प्राप्त की है। वीसीएफ में भागीदारी के माध्यम से, टीडीबी के निधि को करीब 209 कंपनियों में निवेश किया गया है।

इस वर्ष मोघन के प्रति ₹ 15.88 करोड़ की राशि की प्राप्ति हुई। नीचे दी गई तालिका में विवरण दिए गए हैं :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निधि का नाम	निवेश प्रबंधक	कुल निधि	टीडीबी की प्रतिबद्धता	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्ति
01	बॉयोटेक्नोलॉजी वेंचर फंड (बीवीएफ)	एपीआईडीसी वेंचर कैपिटल लिमिटेड, हैदराबाद	155.00	30.00	0.396
02	एसएमई टेक्नोलॉजी वेंचर फंड	गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड (जीवीएफएल), अहमदाबाद	89.32	15.00	-
03	आईवीकैप वेंचर ट्रस्ट फंड I	आईवीकैप वेंचर्स एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई	238.20	25.00	1.57
04	मल्टी सेक्टर सीड केपिटल फंड	ब्लूम वेंचर्स एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई	100.00	25.00	9.61
05	एसएमई टेक फंड आरवीसीएफ II	राजस्थान एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान	150.00	15.00	1.18
06	सीईएफ इंडिया एग्रीबिजनेस फंड	सीईएफ इंडिया इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई	106.25	25.00	0.11
07	इंडिया अपरच्युनिटीज फंड (आईओएफ)	सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड, फंड	421.30	25.00	2.25
08	वेंचरइस्ट टेनेट फंड II	वेंचरइस्ट फंड एडवाइजर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई	54.45	15.00	-
09	इंडियन फंड फॉर सरटेनेबल एनर्जी	सीआईआई, आईआईएम अहमदाबाद	125.00	10.00	0.77
कुल					15.88





हस्ताक्षरित
समझौते



मैन्यूफक्चरिंग ऑफ टेस्टिंग किट टू डिटेक्ट कोविड कोरोना वायरस



मैसर्स मायलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, पुणे

क्षेत्र : स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) द्वारा दिनांक 22.05.2020 को मैसर्स मायलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, पुणे के साथ उनकी परियोजना "मैन्यूफक्चरिंग ऑफ टेस्टिंग किट टू डिटेक्ट कोविड कोरोना वायरस" के कार्यान्वयन के लिए कुल परियोजना लागत ₹ 1360.00 लाख के सापेक्ष ₹ 400.00 लाख की वित्तीय सहायता के लिए एक समझौता किया है।

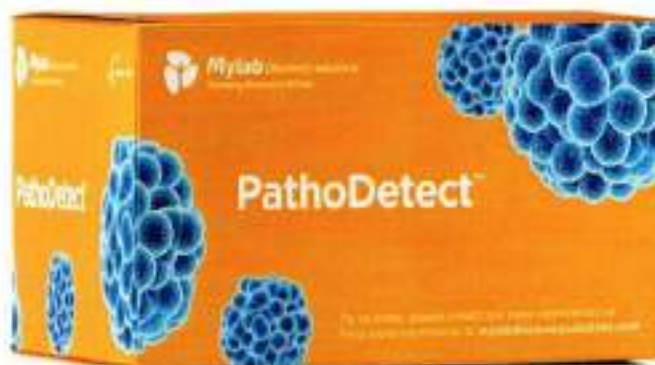
कंपनी के विषय में

मैसर्स मायलैब डिस्कवरी प्राइवेट लिमिटेड, पुणे पहली स्वदेशी कंपनी थी जिसने एक रियल टाइम पीसीआर-आधारित आण्विक डाइग्नोस्टिक किट विकसित की थी जो पलू जैसे लक्षण प्रदर्शित करने वाले लोगों के नमूनों की जांच और पता लगाती है। बहुत ही कम समय में इस किट को विकसित किया गया जिसे आईसीएमआर और सीडीएससीओ द्वारा अनुमोदन प्रदत्त हुआ। इसके अलावा, कंपनी ने दूरदराज के क्षेत्रों में 2 करोड़ से अधिक भारतीयों तक पहुंचने के लिए एक अत्यधिक संवेदनशील एंटीजन किट विकसित की है, उनके लिये, जिनके पास आरटी-पीसीआर परीक्षण के साथ - साथ आरटी-पीसीआर परीक्षण को स्वचालित

करने और डाइग्नोस्टिक में देरी और त्रुटियों को हल करने हेतु कॉम्पैक्ट एक्सप्ल की पहुंच नहीं है।

परियोजना और उत्पाद के विषय में

इस परियोजना का उद्देश्य इस प्रक्रिया में स्वचालन मशीनों को लाकर एक दिन में 4000 किट (एक दिन में 4 लाख परीक्षण) के निर्माण के लिए एक सेटअप विकसित करना है। इस परियोजना के साथ कंपनी कोविड-19 किट की बढ़ती हुई मांग को दृष्टिगत रखते हुए उसके उत्पादन एवं पूर्ति करने में सक्षम होगी। इन किटों की उपलब्धता से देश को उन परीक्षणों की संख्या बढ़ाने में भी मदद मिलेगी जो दैनिक आधार पर किए जा सकते हैं।



मैसर्स मायलैब डिस्कवरी प्राइवेट लिमिटेड, पुणे द्वारा बनाई गई आरटी-पीसीआर परीक्षण किट

वित्तीय सहायता

₹ 400.00 लाख

परियोजना लागत

₹ 1360.00 लाख

डिवलेपमेंट ऑफ लो कॉस्ट एण्ड मोर एफिसियंट मास्क कोटेड विद एंटी वायरल एजेंट्स टू प्रोटेक्ट स्पेयरड एण्ड प्रोटेक्शन ऑफ कोविड-19 एण्ड अदर वायरल इनफेक्शन



मेसर्स थिंकर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पुणे

क्षेत्र : स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) द्वारा दिनांक 08.07.2020 को मेसर्स थिंकर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पुणे के साथ "डिवलेपमेंट ऑफ लो कॉस्ट एण्ड मोर एफिसियंट मास्क कोटेड विद एंटी वायरल एजेंट्स टू प्रोटेक्ट स्पेयरड एण्ड प्रोटेक्शन ऑफ कोविड-19 एण्ड अदर वायरल इनफेक्शन" नामक कुल परियोजना लागत ₹ 27.40 लाख के सापेक्ष में ₹ 7.50 लाख की वित्तीय सहायता के लिए परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता किया है।

कंपनी के विषय में

मेसर्स थिंकर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पुणे होम ऑटोमेशन सिस्टम, 3डी-प्रिंटर, ऑटोमेटिक डिस्पेंसर, ऑटोमेटिक एलिवेटेड प्लस मैज सिस्टम जैसे विभिन्न नए नवाचारी उत्पादों पर काम कर रहा है। कंपनी ने नवाचारी एफडीएम टाइप 3डी प्रिंटर बनाए हैं। उनके 3डी-थिंकर प्रोजेक्ट पर काम करने का उनका मुख्य उद्देश्य फार्मा स्यूटिकल अनुप्रयोगों के लिए 3डी प्रिंटर विकसित करना और नए 3डी प्रिंटेड फार्मा स्यूटिकल फॉर्मूलेशन विकसित करना है। उन्होंने कुछ दवाओं (जैसे एम्लोडिपाइन, टेल्मिसर्टन और डेक्सट्रोमेथोर्फन) और इसके 3डी प्रिंटेड फॉर्मूलेशन के 3डी प्रिंटिंग फिलामेंट्स पर काम किया।

परियोजना और उत्पाद के विषय में

टीडीबी को प्रस्तुत की गई यह परियोजना कोविड-19 के खिलाफ निवारक उपाय के रूप में मास्क पर एंटी-वायरल एजेंटों की 3डी प्रिंटिंग के लिए थी। सौंदर्य प्रसाधनों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सोडियम ओलेफिन सल्फोनेट आधारित मिश्रण को मास्क पर एक लेप के रूप में तैयार किया जाता है। सोडियम ओलेफिन सल्फोनेट, जो एक साबुन बनाने वाला एजेंट है, इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक गुण होते हैं, जब यह आवरण में बंधे हुए वायरस के संपर्क में आता है तो यह बाद वाले की बाहरी झिल्ली को बाधित करता है।

कंपनी सफलतापूर्वक सेटअप और रासायनिक सूत्रीकरण स्थापित कर सकी और फरवरी 2021 के माह में एंटी वायरल कोटेड मास्क का उत्पादन शुरू कर दिया।

इसके अलावा, कंपनी विभिन्न प्रकार के विषाणु नाशक कोटिंग फॉर्मूलेशन विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सहयोग करेगी। इन फॉर्मूलेशन को एन-95 मास्क, 3-प्लेई मास्क, 3 डी प्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से साधारण कपड़े के मास्क में एक अतिरिक्त परत के रूप में शामिल किया जा सकता है और सामान्य मास्क से परे एक अतिरिक्त सुरक्षा हो सकती है। कंपनी नए फार्मास्यूटिकल फॉर्मूलेशन और विभिन्न प्रकार के ड्रग-लोडेड फिलामेंट्स के लिए फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग (एफडीएम) 3डी प्रिंटर का उपयोग करने की संभावना तलाश रही है।



थिंकर - मेसर्स थिंकर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पुणे द्वारा विषाणुनाशक लेपित मास्क

वित्तीय सहायता

₹ 7.50 लाख

परियोजना लागत

₹ 27.40 लाख

डिवलेपमेंट एण्ड कॉमरशियलाईजेशन ऑफ फ्लोरोसेंस-बेसड रेपिड कॉविड-19 डिटेक्शन किट



मेसर्स मेडजोम लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली

क्षेत्र : स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) द्वारा दिनांक 09.07.2020 को मेसर्स मेडजोम लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ कुल परियोजना लागत ₹ 100.00 लाख की सापेक्ष में ₹ 47.50 लाख की ऋण सहायता हेतु उनके परियोजना शीर्षक "डिवलेपमेंट एण्ड कॉमरशियलाईजेशन ऑफ फ्लोरोसेंस-बेसड रेपिड कॉविड-19 डिटेक्शन किट" के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता किया है।

कंपनी के विषय में

मेसर्स मेडजोम लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली पार्श्व प्रवाह इन्स्यूनेसे पर आधारित रेपिड डायग्नोस्टिक उपकरणों के लिए एक निर्माण इकाई है। कंपनी नई दिल्ली में पंजीकृत है, जबकि परियोजना कार्यान्वयन स्थल बड़ी, हिमाचल प्रदेश में है। यह कंपनी वर्तमान में विभिन्न डायग्नोस्टिक किट जैसे मलेरिया / डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड एवं के साथ सिफिलिस पहले से ही बाजार में कंपनी का मिशन दुनिया भर में विविध आबादी के लिए उच्च गुणवत्ता, लागत प्रभावी, तकनीकी रूप से उन्नत नैदानिक परीक्षण किट का निर्माण करना है।

परियोजना और उत्पाद के विषय में

कंपनी लेटरल फ्लो क्रोमेटोग्राफिक इन्स्यूनेसे पर आधारित फ्लोरोसेंस आधारित रेपिड कोविड-2019 डिटेक्शन किट विकसित करेगी। नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले एंटीबॉडी-आधारित पार्श्व प्रवाह इन्स्यूनेसे क्रोमेटोग्राफी परीक्षण की कल्पना कोलाइडल गोल्ड-नैनो कणों द्वारा की जाती है। कंपनी इस परीक्षण को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए फ्लोरोसेंस टैग का उपयोग करेगी। डिटेक्टिंग एंटीजन को फ्लोरोसेंस डाइ से लेबल कर दिया जाएगा और डाइ का पता लगाने हेतु फ्लोरोसेंस रीडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एंटीबॉडी परीक्षण का उपयोग अस्पतालों, क्लीनिकों और परीक्षण प्रयोगशालाओं में कोविड-19 वाहक, रोगसूचक या लक्षण रहित व्यक्तियों की तेजी से जांच हेतु किया जा सकता है। इस परीक्षण के लिए अच्छी तरह से स्थापित प्रयोगशाला सुविधाओं या तकनीकी व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए इसके लागत प्रभावी होने की उम्मीद है।



मेसर्स मेडजोम लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा फ्लोरोसेंस रीडर

वित्तीय सहायता

₹ **47.50** लाख

परियोजना लागत

₹ **100.00** लाख

कॉमरशियलाइजेशन ऑफ क्यूएनयू टेक्नोलॉजी सिक्यूरिटी प्रोडक्ट्स



मेसर्स क्यूएनयू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलोर

क्षेत्र : सूचना प्रौद्योगिकी

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) द्वारा दिनांक 28.08.2020 को मेसर्स क्यूएनयू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलोर के साथ उनकी परियोजना जिसका नाम है "कॉमरशियलाइजेशन ऑफ क्यूएनयू टेक्नोलॉजी सिक्यूरिटी प्रोडक्ट्स" के कार्यान्वयन हेतु ₹ 586.00 लाख की कुल परियोजना लागत सापेक्ष ₹ 280.00 लाख की ऋण सहायता पाने के लिए एक समझौता किया है। समझौते के अनुसार, परियोजना 31 मार्च, 2021 तक पूरी हो जाएगी।

कंपनी के विषय में

क्वांटम सुरक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेसर्स क्यूएनयू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर आधारित सुरक्षा उत्पादों के विकास में संलग्न है। कंपनी वाणिज्यिक समाधान प्रदान करती है जिनकी सुरक्षा क्वांटम यांत्रिकी के नियमों द्वारा सुनिश्चित की जाती है।

परियोजना और उत्पाद के विषय में

कंपनी क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर आधारित सुरक्षा उत्पादों के विकास में कार्य कर रही है। प्रारंभिक प्लेटफार्मों में क्वांटम कुंजी वितरण (क्यूकेडी) प्रणाली और क्वांटम रैंडम नंबर जेनरेटर (क्यूआरएनजी) शामिल हैं। इन प्लेटफार्मों पर निर्मित उत्पाद प्रकार नीचे सूचीबद्ध हैं :

जेनरेटर (क्यूआरएनजी)। इन प्लेटफार्मों पर बने विभिन्न उत्पाद नीचे सूचीबद्ध हैं

ब्रांड	उत्पाद की श्रेणी
आर्मोस	क्वांटम कुंजी वितरण
होडीस	क्यूकेडी के लिए क्वांटम सिक्योर प्लेटफॉर्म
ट्रोपोस	क्वांटम रैंडम नंबर जेनरेटर



मेसर्स क्यूएनयू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलोर द्वारा एआरएमजेएस

इस प्रस्ताव में उपरोक्त उत्पादों के व्यावसायीकरण की परिकल्पना की गई है। क्वांटम कुंजी वितरण (क्यूकेडी) एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा क्वांटम यांत्रिकी के कानूनों द्वारा सुनिश्चित सुरक्षा के साथ संचार लिंक के दो शीर्षों के बीच एन्क्रिप्शन के लिए एक कुंजी का आदान-प्रदान किया जा सकता है। प्रमुख विनिमय प्रक्रिया क्वांटम चैनल नामक एक अलग फाइबर चैनल पर की जाती है, जिस पर सूचना एन्कोडेड क्वांटम बिट्स या "क्विबिट्स" के रूप में भेजी जाती है। आम तौर पर, एन्कोडेड फोटॉन का उपयोग किया जाता है और चूंकि तीव्रता कम होती है, उनमें से केवल कुछ ही दूसरे छोर तक पहुंचते हैं। इसके बाद, दोनों पक्षों के बीच "क्लासिकल" चैनल के माध्यम से हैडशेकिंग की प्रक्रिया से, दोनों पक्ष एक सिपिटड कुंजी पर पहुंचते हैं। यह आगे अपनी गोपनीयता को और बढ़ाने हेतु त्रुटि सुधार और गोपनीयता प्रवर्धन की प्रक्रिया से गुजरता है।

इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त ऐसी कुंजी को "बिना शर्त सुरक्षित" माना जाता है या दूसरे शब्दों में, भले ही किसी विरोधी के पास भौतिक रूप से अनुमेय कम्प्यूटेशनल ऊर्जा की कोई भी राशि हो, वह कुंजी को समझने में सक्षम नहीं होगा। यदि कोई विरोधी संचार लिंक पर छिपकर बात करने की कोशिश करता है, तो या तो उसका पता लगाया जाएगा या वह पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ होगा और इस तथ्य की गारंटी क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों द्वारा दी गई है।

क्यूएनयू ने क्यूकेडी प्लेटफॉर्म को कई बड़े ओईएम और पीएसयू के राउटर/एन्क्रिप्टर्स/स्वामित्व उपकरण के साथ सफलतापूर्वक इंटरफेस किया है जो भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों को एन्क्रिप्शन समाधान प्रदान करते हैं।

वित्तीय सहायता

₹ **280.00** लाख

परियोजना लागत

₹ **586.00** लाख

इन्डस्ट्रीज़ आईओटी इनेबलड आईआर थर्मोग्राफी-बेस्ड टेम्प्रेचर स्केनर



मेसर्स एडवांस मैकेनिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एएमएसपीएल), बैंगलोर

क्षेत्र : अभियांत्रिकी

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीवी) द्वारा दिनांक 04.09.2020 को ₹ 70.00 लाख की कुल परियोजना लागत के सापेक्ष ₹ 21.50 लाख की अनुदान सहायता हेतु अपनी परियोजना "इन्डस्ट्रीज़ आईओटी इनेबलड आईआर थर्मोग्राफी-बेस्ड टेम्प्रेचर स्केनर" के कार्यान्वयन हेतु मेसर्स एडवांस मैकेनिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एएमएसपीएल), बैंगलोर के साथ एक अनुदान समझौता किया है। समझौते के अनुसार, परियोजना 31 जुलाई, 2021 से पहले पूरी हो जाएगी।

कंपनी के विषय में

कंपनी दुनिया भर में अपने ग्राहकों को ऑटोमेशन और इंजीनियरिंग के समाधान और सेवाएं प्रदान करने वाला एक समूह है।

पिछले कई वर्षों से, कंपनी सीएडी/सीएएम/सीई/पीएलएम, डिजाइन इंजीनियरिंग, नियंत्रण इंजीनियरिंग, स्वचालन, रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग, विनिर्माण प्रक्रिया योजना और प्रबंधन, कार्यक्रम/परियोजना प्रबंधन और डिजिटल विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान कर रही है।

परियोजना और उत्पाद के विषय में

यह परियोजना एक वाणिज्यिक पैमाने और विश्वसनीय औद्योगिक आईओटी सक्षम आईआर थर्मोग्राफी-आधारित तापमान स्कैनर विकसित करने के लिए है। एएमएसपीएल का इरादा एआई और आईआईओटी का उपयोग करते हुए रियल-टाइम अलर्ट और एनालिटिक्स प्रदान करने वाले स्वदेशी रूप से विकसित एक अनकूल्ड माइक्रो बोलोमीटर और वीडियो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए रैपिड मेजरमेंट और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग के लिए इन्फ्रारेड थर्मोग्राफी-आधारित स्कैनर का व्यावसायीकरण करना है। उत्पाद को एएमएस थर्मल मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेशन सिस्टम (एटीएमएस) के नाम से शुभारंभ किया जाएगा।

वित्तीय सहायता

₹ **21.50** लाख

परियोजना लागत

₹ **70.00** लाख

एडवान्सड वीडियो एनालेटिक्स फॉर लो-कॉस्ट
थर्मल केमरास टू आईडेन्टीफाई परसन विद
अबनोरमल बोडी टेम्प्रेचर इन पब्लिक प्लेसिस



मेसर्स कोकोरस्लेब्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर

क्षेत्र : अभियांत्रिकी

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) द्वारा दिनांक 23 सितंबर, 2020 को मेसर्स कोकोरस्लेब्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर के साथ कुल परियोजना लागत ₹ 590.94 लाख की तुलना में ₹ 275.00 लाख की ऋण सहायता हेतु अपनी परियोजना "एडवान्सड वीडियो एनालेटिक्स फॉर लो-कॉस्ट थर्मल केमरास टू आईडेन्टीफाई परसन विद अबनोरमल बोडी टेम्प्रेचर इन पब्लिक प्लेसिस" के कार्यान्वयन हेतु एक ऋण समझौता किया है। समझौते के अनुसार, परियोजना 31 मार्च, 2021 से पहले पूरी हो जाएगी।

कंपनी के विषय में

मेसर्स कोकोरस्लेब्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर, इंटेलिजेंट वीडियो एनालेटिक्स स्पेस में है। कोकोरस्लेब्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस 'पिक्सुएट' ब्रांड नाम के तहत अपना व्यापार संचालित करता है। यह कंपनी कंप्यूटर विज्ञान, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उन्नत सॉफ्टवेयर बनाने में माहिर है।

परियोजना और उत्पाद के विषय में

कोकोरस्लेब्स ने कोविड-19 स्थितियों से निपटने और सार्वजनिक स्थानों पर संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एक नवाचारी थर्मल विश्लेषण समाधान विकसित किया है। थर्मल विश्लेषण समाधान है। वे शरीर के तापमान का पता लगाने के लिए थर्मल कैमरा फीड का उपयोग करते हैं और इसे व्यक्ति के चेहरे की इमेज के साथ मैप करते हैं, साथ ही शरीर के ऊंचे तापमान के साथ, समाधान अतिरिक्त विश्लेषण जैसे मास्क डिटेक्शन, सोशल डिस्टेंस चेक, पर्सन फेस स्क्रीन शॉट, एंटी की तिथि और समय, लिंग और उम्र की जानकारी भी प्रदान करता है। संपर्क रहित उपस्थिति को सक्षम करने के लिए समाधान को कार्यालयों और कंपनियों के लिए पिक्सुएट के चेहरे की पहचान समाधान के साथ भी जोड़ा जा सकता है।

वित्तीय सहायता

₹ **275.00** लाख

परियोजना लागत

₹ **590.94** लाख

पोरटेबल अल्ट्रा-वायलेट बेस्ड बॉक्स स्टेरिलाइजर एण्ड मोड्यूलर मूवेबल अल्ट्रा- वायलेट बेस्ड इनडोर रूम स्टेरिलाइजर



मेसर्स इवोबी ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूर

क्षेत्र : स्वास्थ्य एवं विकित्सा

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) द्वारा दिनांक 25.09.2020 को मेसर्स इवोबी ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूर के साथ "पोरटेबल अल्ट्रा-वायलेट बेस्ड बॉक्स स्टेरिलाइजर एण्ड मोड्यूलर मूवेबल अल्ट्रा- वायलेट बेस्ड इनडोर रूम स्टेरिलाइजर" नामक ₹ 35.50 लाख की कुल परियोजना लागत की तुलना में ₹ 15.00 लाख की वित्तीय सहायता हेतु अपनी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता किया है।



मेसर्स इवोबी ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूर द्वारा विभिन्न सरकारी संगठनों में यूवी सैनिटाइजर बॉक्स का वितरण

कंपनी के विषय में

कंपनी प्रौद्योगिकी के साथ निकट तालमेल बनाए रखने के लिए अगली पीढ़ी के उत्पादों और सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है। उत्पादों में बच्चों के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म शामिल हैं ताकि वे अपने मन में किसी भी विचार को सोच सकें और साकार कर सकें। प्लेटफॉर्म डोमेन में छोटे बच्चों के लिए रोबोटिक्स, गेमिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर), वर्चुअल रियलिटी (वीआर), पर्सनल स्मार्ट टॉय, लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन लर्निंग टॉयज शामिल हैं।

परियोजना और उत्पाद के विषय में

कंपनी ने अपने उत्पाद "पोरटेबल अल्ट्रा-वायलेट आधारित बॉक्स स्टेरिलाइजर और मोड्यूलर मूवेबल अल्ट्रा-वायलेट आधारित आंतरिक रूम स्टेरिलाइजर" के व्यावसायीकरण के लिए एक समझौता किया है। कंपनी ने दो अलग-अलग मॉडलों में अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर विकसित किए हैं : जिनमें से एक पोर्टेबल मॉडल है जबकि दूसरा जगह से हटाने योग्य है। कंपनी ने जेजे अस्पताल, मुंबई, सैसन अस्पताल, पुणे, टीएमसी और नायर अस्पताल, मुंबई और देश भर के विभिन्न सरकारी स्कूलों सहित विभिन्न अस्पतालों में 450 यूवी सैनिटाइजर बॉक्स वितरित किए हैं। कंपनी ने 500 से अधिक यूवी सैनिटाइजर बॉक्स बेचे हैं और विभिन्न संगठनों से ऑर्डर प्राप्त कर रहे हैं।

वित्तीय सहायता

₹ **15.00** लाख

परियोजना लागत

₹ **35.50** लाख

नासोमास्क सेमी-ऑटोमैटिक एन 95 प्रोडक्शन मशीन



मेसर्स नैनोक्लीन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली

क्षेत्र : स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) द्वारा दिनांक 24.11.2020 को मेसर्स नैनोक्लीन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ "नासोमास्क सेमी-ऑटोमैटिक एन 95 प्रोडक्शन मशीन" नामक ₹ 153.65 लाख की कुल परियोजना लागत की तुलना में ₹ 50.00 लाख की वित्तीय सहायता के लिए अपनी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता किया है।

कंपनी के विषय में

मेसर्स नैनोक्लीन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, मुख्य रूप से एंटी-पॉल्यूशन फेस मास्क, डिस्पोजेबल नोज फिल्टर और डिस्पोजेबल नोज मास्क से संबंधित है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा उत्पाद, नासोफिल्टर्स के लिए 2017 में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

परियोजना और उत्पाद के विषय में

टीडीबी ने कोविड महामारी के दौरान एन95 मास्क उत्पादन के लिए कंपनी का समर्थन किया है। टीडीबी की वित्तीय सहायता से कंपनी ने सेमी-ऑटोमैटिक एन95 मास्क उत्पादन मशीन को सफलतापूर्वक असेंबल और स्थापित किया है और एन95 मास्क का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन शुरू किया है। टीडीबी की मदद के बदले कंपनी ने दिल्ली पुलिस को एक लाख एन95 मास्क बांटे हैं। इसके अलावा, कंपनी ने नागरिकों के लिए 3.0 लाख से अधिक एन95 मास्क का निर्माण और प्रदान करके कोविड 19 के खिलाफ भारत के संघर्ष का समर्थन किया है।



अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर



दिल्ली पुलिस को मास्क वितरण

वित्तीय सहायता

₹ **50.00** लाख

परियोजना लागत

₹ **153.65** लाख

इनफीलिया-सोल्यूशन फॉर पेरनथुड-कम्प्रीहेन्सिव जेनेटिक स्क्रीनिंग फॉर आर्टिमाईज़िड पेरेन्टिंग



मेसर्स इनडीएनए लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर

क्षेत्र : स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) द्वारा दिनांक 02.12.2020 को मेसर्स इनडीएनए लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर के साथ "इनफीलिया-सोल्यूशन फॉर पेरनथुड-कम्प्रीहेन्सिव जेनेटिक स्क्रीनिंग फॉर आर्टिमाईज़िड पेरेन्टिंग" शीर्षक से ₹ 425.00 लाख की कुल परियोजना लागत के सापेक्ष ₹ 180.00 लाख की ऋण सहायता हेतु अपनी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता किया है।

कंपनी के विषय में

इंडीएनए लाइफ साइंसेज पहला डीएनए आधारित क्लिनिक और एक आण्विक मंच है जो डीएनए आधारित परिवर्तनों की पहचान और स्वास्थ्य और रोग के परिणाम पर इसके प्रभाव की पहचान के लिए अनुकूलित समाधान प्रदान करने हेतु नवाचार किया गया है। कंपनी ने साइटो जेनेटिक्स, कैंसर, आनुवंशिक विकार और मेंडेलियन दोषों के क्षेत्र में, नैदानिक समस्याओं की एक श्रृंखला के लिए डीएनए आधारित समाधानों की एक श्रृंखला की पेशकश करके रोग प्रबंधन को निजीकृत करने के लिए पहला कदम उठाया है। कंपनी ने अपनी तरह का एक अगली जेनरेशन डीएनए सिक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म सफलतापूर्वक स्थापित किया है जो पूर्वी भारत में इस तरह के इंस्टॉलेशन में पहला है। प्रयोगशाला एक एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है, जो वर्तमान में देश के पूर्वी भाग में संचालित होने वाली पहली और एकमात्र मान्यता प्राप्त आण्विक आनुवंशिक प्रयोगशाला बन गई है। प्रयोगशाला में इन क्षेत्रों में अग्रणी चिकित्सकों के साथ सफलतापूर्वक गठबंधन या सहयोग किया गया है।

परियोजना और उत्पाद के विषय में

टीडीबी से वित्तीय सहायता के साथ कंपनी का लक्ष्य अपने स्वदेशी उत्पाद 'इनफीलिया' का व्यावसायीकरण करना

है जिसमें आण्विक परीक्षण और आवर्तक गर्भावस्था हानि और भारतीय जनसंख्या में पुरुष और महिला इंफर्टिलिटी के आण्विक आधार से संबंधित आनुवंशिक विविधताओं की जांच के लिए दो आंतरिक विकसित पैनल शामिल हैं।

इस परियोजना का परिणाम एक आनुवंशिक अनुक्रम पुस्तकालय का निर्माण और भारतीय मूल की आबादी के लिए संगत ज्ञात और नवीन उत्परिवर्तन के डेटाबेस का उत्पादन होने की उम्मीद है। इससे गर्भावस्था के बार-बार होने वाले नुकसान, आईवीएफ विफलताओं और इडियोपैथिक इंफर्टिलिटी के पीछे के कारणों की पहचान हो सकेगी और बांझपन के साथ जीवनशैली में बदलाव को चिकित्सकीय रूप से सहसंबंधित किया जा सकेगा। इन आनुवंशिक पैनलों की उपलब्धता होने से भारत में इन परीक्षणों को बेंचमार्क करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट डेटाबेस तैयार किया जाएगा।

इसके अलावा, अनुकूल प्रदर्शन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले से विकसित तकनीक को भारतीय आनुवंशिक मेक अप के साथ सत्यापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारत के नागरिकों के लिए सामर्थ्य बढ़ाने हेतु लागतों को अनुकूलित किया जाएगा।

जब इस समाधान को स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में प्रस्तुत किया जाता है, तो इससे आईवीएफ शिशुओं में आनुवंशिक रोगों के बोझ को कम करने तथा अनुकूल प्रजनन परीक्षण प्रदान करने में सहायता की उम्मीद है। इससे भारत में आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

वित्तीय सहायता

₹ **180.00** लाख

परियोजना लागत

₹ **425.00** लाख

केएस, ए स्क्रीनिंग एण्ड मोनीटरिंग टूल फॉर कोविड-19



मेसर्स साल्सिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद

क्षेत्र : सूचना प्रौद्योगिकी

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) द्वारा दिनांक 11.12.2020 को मेसर्स साल्सिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद के साथ "केएस, ए स्क्रीनिंग एण्ड मोनीटरिंग टूल फॉर कोविड-19" शीर्षक से कुल परियोजना लागत ₹ 60.00 लाख के सापेक्ष ₹ 20.00 लाख की अनुदान सहायता के लिए अपनी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता किया है। समझौते के अनुसार, परियोजना 30.04.2021 को पूरी हो जाएगी।

कंपनी के विषय में

मेसर्स साल्सिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद हैदराबाद में वीजेएचयूबी (विगना ज्योति सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल एक्सिलेंस, एक धारा 8 में पंजीकृत कंपनी) से इनक्यूबेट किया गया है। कंपनी उनके पेटेंट स्वासा एआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए श्वसन संबंधी ध्वनियों के ऑडियोमेट्रिक मूल्यांकन के आधार पर श्वसन रोगों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य समाधान विकसित कर रही है।

परियोजना और उत्पाद के विषय में

कंपनी ने एक मोबाइल एप्लिकेशन के विकास और व्यावसायीकरण का प्रस्ताव रखा है ताकि कोविड-19 को नियंत्रित करने की दिशा में लोगों की स्क्रीनिंग और निगरानी की जा सके। यूजर इंटरफेस के साथ केएस मोबाइल एप्लिकेशन लक्षणों के डेटा को कैप्चर करता है और खांसी की आवाज रिकॉर्ड करता है। प्रयोक्ता को समग्र जोखिम स्कोर और जोखिम रुझान दिखाने के लिए एप्लिकेशन में इंटरफेस भी है। स्वासा एआई प्लेटफॉर्म जो मशीन लर्निंग आधारित एनालिटिक्स के आधार पर ऑडियोमेट्रिक विश्लेषण करता है। मंच द्वारा मोबाइल या वेब क्लाइट से इनपुट प्राप्त किया गया, डेटा को संसाधित किया गया और पूर्वानुमान और विस्तृत विश्लेषण को आउटपुट के रूप में वापस दिया गया। एआई प्लेटफॉर्म "स्वासा" द्वारा संचालित साल्सिट टूल "केएस", सांस की

बीमारी के रोगियों को प्राथमिकता देने में सरकार और अन्य नागरिक अधिकारियों की सहायता करने के लिए ठीक यही क्षमता प्रदान करता है।

यह जोखिम स्कोर व्यक्ति के जोखिम के बारे में बताने वाला बेहतर पूर्वानुमानकर्ता है क्योंकि खांसी की आवाज के विश्लेषण से फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्थिति में एक विस्तृत अंतर्दृष्टि प्रदान की जाती है। तब बड़ी आबादी के लिए साल्सिट प्रणाली इस जोखिम स्कोर को समय के साथ ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करती है।

इस उपकरण का उपयोग करते हुए निचले श्वसन पथ के संक्रमण और संबंधित श्वसन पैटर्न जैसे प्रतिबंधात्मक या अवरोधक का पता लगाया जा सकता है। साथ ही निमोनिया जैसी बीमारियों पर सांकेतिक जानकारी प्रदान की जा सकती है।

स्वासा की तकनीक को क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री-इंडिया (सीटीआरआई) और डब्ल्यूएचओ के इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म (आईसीटीआरपी) के साथ श्वसन ध्वनि विश्लेषण और नैदानिक अध्ययन के साथ इसके सहसंबंधों के लिए पंजीकृत किया गया है।

साल्सिट सी-कैम्प में भारत सरकार के बायो-इनक्यूबेटर का हिस्सा है।



लागत नहीं है

मेसर्स साल्सिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा केएस मोबाइल एप्लिकेशन

वित्तीय सहायता

₹ 20.00 लाख

परियोजना लागत

₹ 60.00 लाख

बैटरी पावरड् कॉम्पैक्ट डिजिटल पोर्टेबल एक्स-रे मशीन



मेसर्स आईएटीओएमई इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोयंबटूर

क्षेत्र : स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2021 को मेसर्स आईएटीओएमई इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोयंबटूर के साथ "बैटरी पावरड् कॉम्पैक्ट डिजिटल पोर्टेबल एक्स-रे मशीन" नामक कुल परियोजना लागत ₹ 236.00 लाख के सापेक्ष ₹ 118.00 लाख की अनुदान सहायता के लिए अपनी परियोजना के कार्यान्वयन हेतु एक अनुदान समझौता किया है। समझौते के अनुसार, परियोजना 30 सितंबर, 2022 से पहले पूरी हो जाएगी।

कंपनी के विषय में

मेसर्स आईएटीओएमई इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोयंबटूर एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो एक्स-रे जेनरेटर्स और हाइ वॉल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स पर उत्पाद प्रोफाइल के साथ है। उन्होंने एक्स-रे जनरेशन के लिए अपनी स्वदेशी तकनीक विकसित की है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उच्च वॉल्टेज, सामग्री और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उन्नत तरीके शामिल हैं।



मेसर्स आईएटीओएमई इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोयंबटूर द्वारा पोर्टेबल "एक्स-रे मशीन"

परियोजना और उत्पाद के विषय में

कंपनी एक्स-रे जेनरेटर और उच्च वॉल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स की उत्पाद विशेषज्ञता के साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में है। कंपनी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्रों में इंजीनियरिंग डिजाइन विकास सेवाएं प्रदान करती है। इन वर्षों में, कंपनी ने संसाधनों का निवेश किया और एक्स-रे और उच्च वॉल्टेज उत्पादों के लिए अपनी तकनीक विकसित की। उच्च आवृत्ति बिजली रूपांतरण और समग्र इन्सुलेशन के साथ डिजिटल नियंत्रण को एकीकृत करने की नई तकनीक के परिणामस्वरूप कॉम्पैक्ट एक्स-रे स्रोत प्राप्त हुए। इसके अलावा, आइएटोम पहले से ही एईआरबी लाइसेंस प्राप्त सुविधा से लैस है जहां एक्स-रे उपकरण का निर्माण किया जा रहा है और आंतरिक परीक्षण और प्रमाणन किया जा रहा है। हमारे देश और राज्य की जनता में कोरोना वायरस के संक्रमण के तेजी से फैलने के मद्देनजर, प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य हाथ से चलने वाली एकल एक्स-रे प्रणाली विकसित करना है जिसे रोगी तक ले जाया जा सकता है, और एक रेडियोग्राफी; सीने, हाथ-पैर की इमेज (बहुत मोटी शरीर रचना के अलावा कुछ भी) प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार, वर्तमान परियोजना के तहत, आइएटोम कुल 9 इकाइयों, संकल्पना के लिए 01, प्रोटोटाइप के लिए 03, प्रायोगिक उत्पादन और नियामक के लिए 05 को विकसित करने का आशय रखता है।

वित्तीय सहायता

₹ **118.00** लाख

परियोजना लागत

₹ **236.00** लाख

कोविड -19 मोनिटोरिंग एण्ड मेन्जमेंट सोल्यूशन फॉर अफेक्टिड, क्वारंटाइनड ओर कॉ-मोरबीडीटी हाई रिस्क पेसन्ड्स टू अवाईड ओर डिले लग्स् कॉमपिलीकेशनस् इन ऑर्डर टू रिड्यूस् केस फेटेलिटी रेट (सीएफआर)



मेसर्स ब्रियोटा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, पुणे

क्षेत्र : स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

परियोजना और उत्पाद के विषय में

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) द्वारा 2 मार्च, 2022 को मेसर्स ब्रियोटा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, पुणे के साथ "कोविड -19 मोनिटोरिंग एण्ड मेन्जमेंट सोल्यूशन फॉर अफेक्टिड, क्वारंटाइनड ओर कॉ-मोरबीडीटी हाई रिस्क पेसन्ड्स टू अवाईड ओर डिले लग्स् कॉमपिलीकेशनस् इन ऑर्डर टू रिड्यूस् केस फेटेलिटी रेट (सीएफआर)" मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सोल्यूशन के लिए ₹ 85.00 लाख की ऋण सहायता और ₹ 370.00 लाख की कुल परियोजना लागत के खिलाफ ₹ 50.00 लाख की अनुदान सहायता दी है। समझौते के अनुसार, परियोजना 31 अप्रैल, 2022 से पहले पूरी हो जाएगी।

कंपनी के विषय में

कंपनी डिजिटल स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में काम करती है। वे पुरानी श्वसन स्थितियों के लिए दूरस्थ देखभाल, निदान और प्रबंधन हेतु नवीन तकनीकी समाधान प्रदान कर रहे हैं। अस्थना और सीओपीडी जैसी स्थितियों के उपचार और निगरानी को आसान बनाने के लिए, उन्होंने रोगियों और डॉक्टरों दोनों के अनुरूप अत्याधुनिक तकनीकी समाधान प्रदान किए हैं।

ब्रियोटा के डिजिटल रेस्पिरेटरी प्लेटफॉर्म का विकास, वृद्धि और व्यावसायीकरण "कोविड -19 निगरानी और प्रबंधन समाधान के रूप में प्रभावित, संस्रोध या सह-बीमारियों के उच्च जोखिम वाले रोगियों के लिए फेफड़ों की जटिलताओं से बचने या देरी करने के लिए केस घातक दर (सीएफआर) को कम करने हेतु" के रूप में उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना में "स्पिरोप्रो" नामक उत्पाद के व्यावसायीकरण की परिकल्पना की गई है - जो भारत का पहला लागत प्रभावी सीडीएससीओ अनुमोदित स्वदेशी स्पाइरोमीटर है। फेफड़ों की क्षमता को मापने और निगरानी करने हेतु फेफड़ों के संक्रमण/कम क्षमता का निदान करने के लिए डिजिटल हैंडहेल्ड स्पाइरोमीटर का उपयोग किया जाएगा। यह एक मोबाइल ऐप, नेहा (नर्स प्रशिक्षक और स्वास्थ्य सहायक) के साथ आता है जो फेफड़ों की स्थिति की निगरानी और टेलीमेडिसिन/टेली परामर्श सुविधा के साथ वेंटिलेटर समर्थन के प्रबंधन में सहायता करता है। कोविड-19 की अत्यधिक संक्रामक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इस परियोजना से कंपनी को अपने स्पाइरोमीटर हार्डवेयर को समानांतर रूप से फिर से डिजाइन करने और एक बार उपयोग अर्थात् - डिस्पोजेबल यूनिट और घरेलू उपयोग हेतु भी आवश्यक सॉफ्टवेयर इंटरफेस जोड़ने में सहायता मिलेगी।



"स्पिरोप्रो" मेसर्स ब्रियोटा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

वित्तीय सहायता

₹ **135.00** लाख

परियोजना लागत

₹ **370.00** लाख

इसटेबलिसमेंट्स ऑफ स्पेसीफिक पथोजेन फ्री (एसपीएफ) लैबोरेट्री ऐनीमल ब्रीडिंग एण्ड टेस्टिंग फेसिलिटी



मेसर्स आरसीसी लेबोरेटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद

क्षेत्र : स्वास्थ्य एवं विकित्सा

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) द्वारा दिनांक 10.3.2021 को मेसर्स आरसीसी लेबोरेटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद के साथ "इसटेबलिसमेंट्स ऑफ स्पेसीफिक पथोजेन फ्री (एसपीएफ) लैबोरेट्री ऐनीमल ब्रीडिंग एण्ड टेस्टिंग फेसिलिटी" नाम से ₹ 40.79 करोड़ की कुल परियोजना लागत के सापेक्ष ₹ 15.54 करोड़ की ऋण सहायता हेतु अपनी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता किया है। समझौते के अनुसार, परियोजना 30.8.2023 को/या उससे पहले पूरी हो जाएगी।

कंपनी के विषय में

आरसीसी लेबोरेटरीज प्री क्लिनिकल, संपटी, टॉक्सिकोलॉजी और केमिकल टेस्टिंग प्रदान करने वाली प्रमुख कंपनियों में से एक है और उच्च गुणवत्ता मानकों और सेवाओं को बनाए रखा जाता है। कंपनी को राष्ट्रीय जीएलपी अनुपालन निगरानी प्राधिकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ओईसीडी जीएलपी प्रमाणपत्र और प्रयोगशाला पशु देखभाल (एएएलएसी) के आकलन और प्रत्यायन संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है। आरसीसी विभिन्न उत्पादों जैसे फार्मास्यूटिकल्स/ड्रग्स, एग्रोकैमिकल्स (कीटनाशकों), बायोटेक, चिकित्सा उपकरणों, औद्योगिक रसायन, तंबाकू, प्रसाधन सामग्री आदि के लिए पंजीकरण आदेश को पूरा करने हेतु नियामक विषय विज्ञान अध्ययन आयोजित करता है।

परियोजना और उत्पाद के विषय में

इस परियोजना के माध्यम से, कंपनी भारतीय और वैश्विक फार्मास्यूटिकल और जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों की जरूरतों को पूरा करने हेतु एक विशिष्ट रोगजनक मुक्त (एसपीएफ) पशु प्रजनन और परीक्षण सुविधा स्थापित करने का आशय रखती है। इस सुविधा में यूएसएफडीए, यूएसईपीए, ओईसीडी, ईएमईए, एएएलएसी अनुसूची

वाय, आरसीजीएम आदि द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पशु प्रजनन और परीक्षण हेतु वैश्विक नियामक मानकों का पालन किया जाएगा। यह सुविधा उच्च गुणवत्ता वाले एसपीएफ पशुओं का रखरखाव किया जाएगा, जिन्हें एक ही स्थान पर कीटनाशकों, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि-रसायनों आदि के परीक्षण के लिए नस्ल और उपयोग किया जाएगा।

परिवर्तनशीलता को कम करने, प्रयोगात्मक परिणामों में पुनरुत्पादकता बढ़ाने के लिए एसपीएफ जानवरों की आवश्यकता होती है, जिससे दवा विकास लागत कम हो जाती है। एसपीएफ पशु भी असफल दवा/रसायनिक प्रत्याशियों को जल्दी खत्म करने में मदद करते हैं और सफल प्रत्याशियों की शीघ्र पुष्टि करते हैं। दवाओं, रसायनों और चिकित्सा उपकरणों आदि के लिए विश्व स्तर पर नियामक प्रस्तुत करने हेतु पशु सुरक्षा और प्रभावकारिता अध्ययन से विश्वसनीय और स्पष्ट परिणाम आवश्यक हैं।

वर्तमान में, भारत में एसपीएफ पशु प्रजनन और परीक्षण सुविधा नहीं है जो रोगजनक मुक्त जानवरों का प्रजनन और रखरखाव कर सके। भारत में प्रजनन और परीक्षण हेतु एक एसपीएफ पशु सुविधा की कमी ने कई भारतीय कंपनियों को अपने प्रयोगशाला परीक्षण उद्देश्यों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ से नियमित रूप से पशुओं का आयात करने हेतु आवश्यक होता है। इस प्रस्तावित सुविधा से भारतीय कंपनियों को लागत और समय प्रभावी तरीके से अपने अणुओं का मूल्यांकन करने के लिए विश्वसनीय और स्थानीय मूल संरचना प्रदान किया जाएगा।

वित्तीय सहायता

₹ **1554.00** लाख

परियोजना लागत

₹ **4079.00** लाख



पूर्ण की गई
परियोजनाएं



सिटिंग अप डिफेंस मेन्यूफैक्चरिंग फेसिलिटी
एट 50 एकड लेण्ड एट वेमागल इंडस्ट्रीयल एरिया,
कोलर डिस्ट्रीक्ट, कर्नाटका



मेसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, बेंगलोर

क्षेत्र : रक्षा एवं नागर विमानन



प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने कुल परियोजना लागत ₹ 38500.00 लाख की तुलना में ₹ 10900.00 लाख की ऋण सहायता के लिए परियोजना 'सिटिंग अप डिफेंस मेन्यूफैक्चरिंग फेसिलिटी एट 50 एकड लेण्ड एट वेमागल इंडस्ट्रीयल एरिया, कोलर डिस्ट्रीक्ट, कर्नाटका' के कार्यान्वयन के लिए 17.12.2016 को मेसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, कार्यनीतिक इंजीनियरिंग प्रभाग (टाटा पावर – एसईडी), बेंगलोर राज्य कर्नाटक के साथ एक समझौता किया है।

कंपनी के विषय में

सामरिक इंजीनियरिंग प्रभाग (एसईडी), अब टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह टाटा समूह की सामरिक एयरोस्पेस और रक्षा शाखा है, जिसके द्वारा मिसाइल प्रणालियों और उप-प्रणालियों के क्षेत्रों में स्थापित क्षमताओं और इसके साथ रडार सिस्टम और सब-सिस्टम; कमान और नियंत्रण प्रणाली; एयरोस्पेस और एयरो-स्ट्रक्चर मानव रहित हवाई प्रणाली; ऑप्टोनिक सिस्टम और होमलैंड सुरक्षा समाधान की प्रदायगी प्रदर्शित की जाती है।

परियोजना और उत्पाद के विषय में

इस परियोजना में दूरसंचार उत्पादों, कार्यनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स, ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन (ईएसडीएम) और विनिर्माण के लिए बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में पांच व्यापक रेंज के उपकरणों के उत्पादन हेतु एक अत्याधुनिक नवाचार कार्यनीतिक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। यह प्रौद्योगिकी वास्तव में प्रौद्योगिकी भागीदारों के सहयोग से आंतरिक विकास पर आधारित थी।

कंपनी ने परियोजना को पूरा कर लिया है और 9.09.2020 से वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है।

वित्तीय सहायता

₹ **10900.00** लाख

परियोजना लागत

₹ **38500.00** लाख

डिवलपमेंट एण्ड कॉमरशियलाईजेशन ऑफ रूल बड्डी प्रोजेक्ट (अर्थवाइल 'आर्किटेक्स')



मेसर्स सॉफ्टटेक इंजीनियर्स लिमिटेड, पुणे

क्षेत्र : आईटी

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीवी) ने 6 फरवरी 2017 को मेसर्स सॉफ्टटेक इंजीनियर्स लिमिटेड, पुणे के साथ कुल परियोजना लागत ₹ 615.46 लाख के सापेक्ष ₹ 245.00 लाख की ऋण सहायता हेतु उनकी परियोजना का शीर्षक "डिवलपमेंट एण्ड कॉमरशियलाईजेशन ऑफ रूल बड्डी प्रोजेक्ट (अर्थवाइल 'आर्किटेक्स')" के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता किया था।

कंपनी के विषय में

मेसर्स सॉफ्टटेक इंजीनियर्स लिमिटेड, द पेंटागन, यूनिट नंबर 5ए, शाहू कॉलेज रोड, पुणे में स्थित है। कंपनी अपने ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, ई-शासन और निर्माण व्यापारों के लिए नवाचारी विश्वसनीय और विश्व स्तरीय सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए समर्पित है। सॉफ्टटेक ने स्ट्रुड्स, ऑटोडीसीआर, पीडब्ल्यूआईएमएस, ऑप्टिकॉन और कई अन्य जैसे नवीन सॉफ्टवेयर उत्पादों की एक प्रभावशाली श्रृंखला प्रस्तुत की है। यह कुछ जटिल सरकारी प्रक्रियाओं जैसे भवन अनुमोदन और कार्य प्रबंधन को स्वचालित करने में अग्रणी रहा है।

परियोजना और उत्पाद के विषय में

रूल बड्डी को ई-कॉमर्स पोर्टल के रूप में विकसित और व्यावसायीकरण करना ताकि परियोजना व्यवहार्यता और बिल्डिंग परमिट के लिए अपने प्रमुख उत्पाद ऑटो डीसीआर के लाभ के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जा सकें। रूल बड्डी पोर्टल के कार्य क्षेत्र में व्यावसायिक गहराई के लिए एक डिजाइन प्रदान करना तथा कानूनों द्वारा भवन निर्माण और योजना अनुमोदन जानकारी के बारे में जानकारी प्रदान करना शामिल है।

यह संकल्पना और डिजाइन चरणों के दौरान निर्माण परियोजना व्यवहार्यता और भवन परमिट में वर्तमान कठिनाइयों के क्षेत्रों को संबोधित करने हेतु एक स्थान पर समाधान के रूप में पूरी तरह से स्वदेशी उत्पाद विकसित किया गया है। वर्तमान में, ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत में कोई ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध नहीं है।

वित्तीय सहायता

₹ **245.00** लाख

परियोजना लागत

₹ **615.46** लाख





संवर्धनात्मक
गतिविधियाँ



इस वर्ष, कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा प्रतिबंधों के कारण, टीडीबी ने हाइब्रिड विधि द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन / सेमिनार / अन्य कार्यक्रमों में भाग लिया।

साइबर सुरक्षा निवेशक सम्मेलन

11 अप्रैल, 2020

साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी विकास और उत्पाद उद्यमिता हेतु राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, डीएससीआई तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (एमआईटी) की एक संयुक्त पहल, ने 11 अप्रैल, 2020 को भारत को साइबर सुरक्षा नवाचार का गंतव्य बनाने की दिशा में "सुरक्षा निवेशक सम्मेलन" की मेजबानी की। इस कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया था।

टीडीबी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और साइबर सुरक्षा स्टार्ट-अप्स पर टीडीबी वित्तपोषण पर एक वार्ता दी। जिसमें यह विस्तार से बताया गया था कि चूंकि सुरक्षा उत्पाद और सेवाओं के लिए बाजार साइबर सुरक्षा स्टार्ट-अप में निवेश के लिए एक अनुकूल और फायदेमंद वातावरण बनाता है, अतः भारत में साइबर सुरक्षा में निवेश धीरे-धीरे बढ़ रहा है और प्रमुख मुद्दों की समझ में सुधार की गुंजाइश है जिससे आने वाले वर्षों में निवेश निर्णय लेने को आकार मिलेगा।



साइबर सुरक्षा निवेशक सम्मेलन

स्वदेशी प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण के लिए स्टार्ट-अप / एसएमई हेतु निधिकरण के अवसरों पर एफआईसीसीआई-टीडीबी वेबिनार

28 अप्रैल, 2020

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिककी) ने 28 अप्रैल, 2020 को "स्वदेशी प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण के लिए स्टार्ट-अप / एसएमई हेतु वित्तपोषण के अवसर" पर एक वेबिनार का आयोजन किया।

टीडीबी के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और छोटे भारतीय उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, प्रतिस्पर्धी उपभोक्ता उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने, उत्पाद नवाचार हेतु उद्योगों को प्रेरित करने और

सामाजिक रूप से संगत, लाभदायक प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए टीडीबी के साथ उपलब्ध निधिकरण के अवसरों पर संक्षिप्त जानकारी दी। यह परिलक्षित हुआ कि कोविड-19 संकट में, महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रौद्योगिकी सबसे आगे रही है। जैसे-जैसे दुनिया अपने नए सामान्य से तालमेल बिठाती है, उसी तरह व्यापार की अग्रणी दुनिया के व्यक्ति नई कार्यनीतियों पर पुनर्विचार कर रहे हैं और नई कार्यनीति तैयार कर रहे हैं जो मदद करेगी, लचीलापन बढ़ाएगी और उन्हें संकट से संघर्ष करने के लिए मजबूत बनाएगी।



स्वदेशी प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण के लिए स्टार्ट-अप / एसएमई हेतु निधिकरण के अवसरों पर फिककी-टीडीबी वेबिनार - 28 अप्रैल, 2020

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर “री-स्टार्ट” डिजिटल सम्मेलन

11 मई, 2020

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर एक डिजिटल सम्मेलन “री-स्टार्ट” का आयोजन किया। माननीय केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने इस डिजिटल सम्मेलन “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर “री-स्टार्ट” डिजिटल सम्मेलन” को संबोधित किया था।

कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. सारस्वत के विशेष संबोधन भी शामिल थे; प्रो. के. विजय राघवन, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार; डॉ. सौम्या स्वामीनाथन, मुख्य वैज्ञानिक, विश्व स्वास्थ्य संगठन; प्रो. आशुतोष शर्मा, डीएसटी सचिव; डॉ. रेणु स्वरूप, सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डॉ. शेखर सी. मंडे, महानिदेशक, सीएसआईआर और भारत में इटली के राजदूत, माननीय श्री विन्सेन्जो डी लुका ने भी विभिन्न सत्रों में विशेष भाषण दिए।

इस सम्मेलन में वैश्विक स्वास्थ्य संकट में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए वैज्ञानिकों, टेक्नोक्रेट, सरकारी अधिकारियों, राजनयिकों, डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उद्योग,

अनुसंधान संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों के गणमान्य व्यक्तियों को एक मंच पर एक साथ लाया गया और ऐसे समाधान खोजने का प्रयास किये गये जिनसे न केवल वर्तमान महामारी के दौरान सहायता मिल सके बल्कि आगे की चुनौतियों का सामना करने में भी मदद मिले।

डिजिटल सम्मेलन के अलावा, उन कंपनियों के साथ एक आभासी प्रदर्शनी, जिनकी तकनीकों को टीडीबी द्वारा समर्थित किया गया है, एक डिजिटल बी2बी लाउंज के माध्यम से उपलब्ध थी, जिसमें उनके उत्पादों का प्रदर्शन किया गया था।



कंपनियों द्वारा आभासी प्रदर्शनी



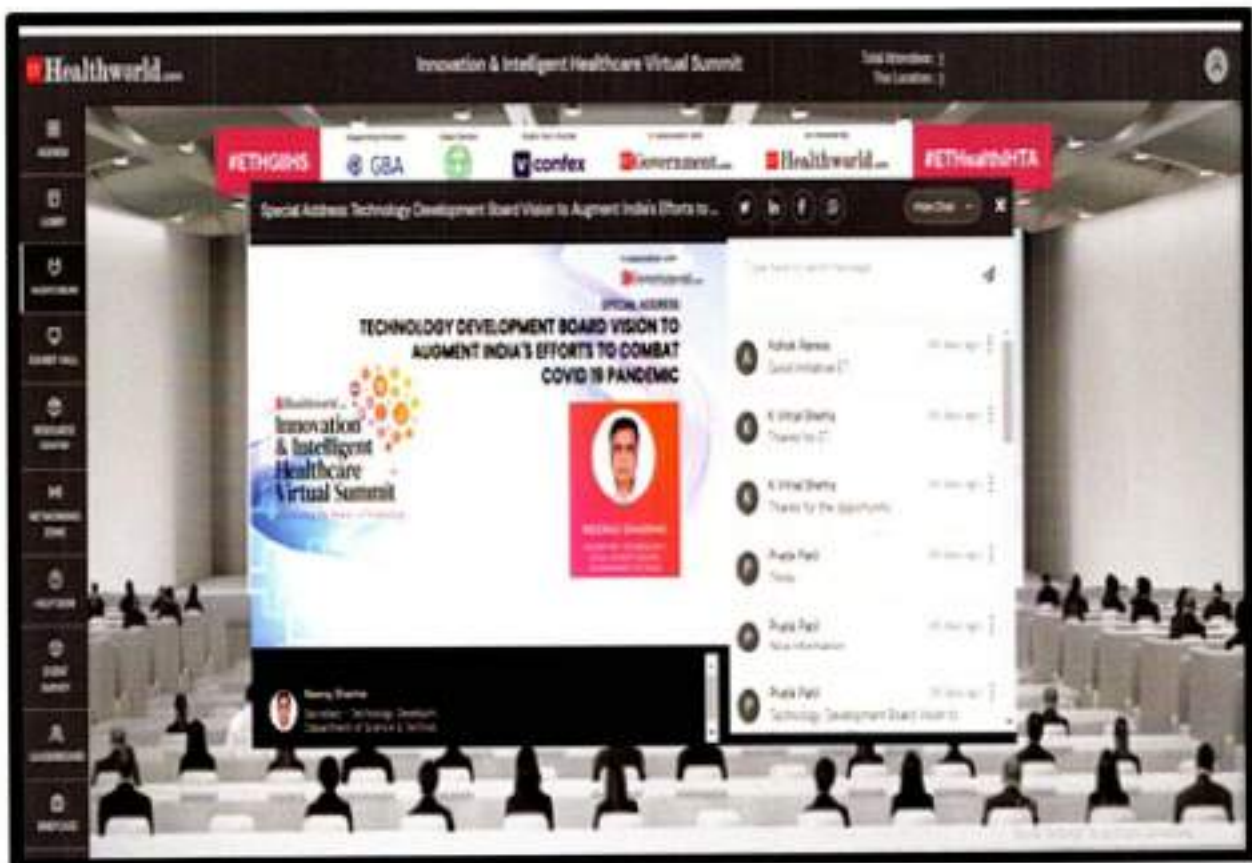
11 मई, 2020 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर डिजिटल सम्मेलन “री-स्टार्ट” का उद्घाटन

इनोवेशन एण्ड इन्टेलिजेंट हैल्थकेयर सम्मिट

15-16 सितंबर, 2020

ईटी सरकार और ईटी स्वास्थ्य विश्व ने दो दिवसीय वर्चुअल ग्लोबल समिट 'इनोवेशन एण्ड इन्टेलिजेंट हैल्थकेयर सम्मिट' का आयोजन 15-16 सितंबर, 2020 को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के साथ समर्थन भागीदार के रूप में किया। यह वर्चुअल महा सम्मेलन देश भर में

स्वास्थ्य देखकर प्रदायगी प्रणाली को मजबूत करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट सहित उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित था। डॉ. नीरज शर्मा, सचिव टीडीबी ने मुख्य भाषण दिया।



नवानार और बुद्धिमान स्वास्थ्य देखभाल महा सम्मेलन

वेस्ट टू वर्थ पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

30 अक्टूबर, 2020

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने 30 अक्टूबर, 2020 को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, भारत सरकार और एसबीएम, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से, देश भर में बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए अपशिष्ट से मूल्य पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। कचरे का प्रभावी प्रबंधन करने से सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में योगदान मिलता है। इससे अंततः स्वच्छ, स्वस्थ, सशक्त, संपन्न और आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाया जाएगा। सम्मेलन का विषय 'नवीन 3आर तकनीकों के माध्यम से गोलाकार अर्थव्यवस्था प्राप्त करना' था।

डॉ. नीरज शर्मा, सचिव, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, भारत सरकार ने भारत के सामने आने वाली चुनौतियों के साथ-साथ भारत में अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकियों के महत्व और आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अब तक, टीडीबी ने इस क्षेत्र के अंदर कुछ कंपनियों को वित्तीय रूप से समर्थन दिया है, तथा भारतीय तकनीकी उद्यमों को प्रोत्साहित करने और अधिक समर्थन देने के इच्छुक हैं।



वेस्ट टू वर्थ पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन – 30 अक्टूबर, 2020

भारत की साइबर सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं पर वर्चुअल रोड शो

06 नवंबर, 2020

टीडीबी ने डीएससीआई रोड शो में भाग लिया, जो डीएससीआई और एमईआईटीवाई की संयुक्त पहल है। साइबर सुरक्षा आर एंड डी रोड शो वर्चुअल विधि में 06 नवंबर, 2020 को आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य अकादमिक अनुसंधानकर्ताओं, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास कार्य को उद्योग के लिए दृश्यमान बनाना है।

यह रोड शो साइबर सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास पर सहयोगात्मक कार्य के बारे में समेकित दृष्टिकोण रखने की एक पहल थी। यह भारत की साइबर क्षमताओं को

विकसित करने के लिए उद्योग, शिक्षाविदों और सरकार के बीच सहयोग हेतु ऐसे कई और भविष्य के उदाहरणों की दिशा में पहला कदम हो सकता है।

टीडीबी के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अनुसंधान कार्य और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं पर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी प्रोटोटाइप और उत्पादों का अनुभव करने और अनुसंधानकर्ताओं और संस्थानों के साथ अवसरों का पता लगाने के लिए रोड शो की खोज की। टीडीबी ने देश की साइबर क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु चर्चा में भी योगदान दिया।



भारत की साइबर सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं पर वर्चुअल रोड शो

भारतीय उर्वरक संघ का 56वां वार्षिक संगोष्ठी

07-09 दिसंबर, 2020

भारत में कृषि हमेशा आजीविका का मुख्य आधार रही है। इस वर्ष के लिए संगोष्ठी का विषय 'कोविड-19 के दौरान उर्वरक और कृषि' है। इस मंच ने कोविड-19 के दौरान उर्वरक आपूर्ति-मांग, मूल्य रुझानों, नीतिगत वातावरण, उर्वरक उपयोग दक्षता, उर्वरक उत्पादन प्रौद्योगिकियों में विकास और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्रों में विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान की।

टीडीबी ने इस आयोजन में भाग लिया तथा भारत के विशिष्ट अंतरालों को समझने और भारतीय कृषि उद्योग को आवश्यक समर्थन देने के अवसर का पता लगाया।



भारतीय उर्वरक संघ का 56वां वार्षिक संगोष्ठी

भारत की साइबर सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं पर वर्चुअल रोड शो

06 नवंबर, 2020

टीडीबी ने डीएससीआई रोड शो में भाग लिया, जो डीएससीआई और एमईआईटीवाई की संयुक्त पहल है। साइबर सुरक्षा आर एंड डी रोड शो वर्चुअल विधि में 06 नवंबर, 2020 को आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य अकादमिक अनुसंधानकर्ताओं, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास कार्य को उद्योग के लिए दृश्यमान बनाना है।

यह रोड शो साइबर सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास पर सहयोगात्मक कार्य के बारे में समेकित दृष्टिकोण रखने की एक पहल थी। यह भारत की साइबर क्षमताओं को

विकसित करने के लिए उद्योग, शिक्षाविदों और सरकार के बीच सहयोग हेतु ऐसे कई और भविष्य के उदाहरणों की दिशा में पहला कदम हो सकता है।

टीडीबी के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अनुसंधान कार्य और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं पर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी प्रोटोटाइप और उत्पादों का अनुभव करने और अनुसंधानकर्ताओं और संस्थानों के साथ अवसरों का पता लगाने के लिए रोड शो की खोज की। टीडीबी ने देश की साइबर क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु चर्चा में भी योगदान दिया।



भारत की साइबर सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं पर वर्चुअल रोड शो

भारतीय उर्वरक संघ का 56वां वार्षिक संगोष्ठी

07-09 दिसंबर, 2020

भारत में कृषि हमेशा आजीविका का मुख्य आधार रही है। इस वर्ष के लिए संगोष्ठी का विषय 'कोविड-19 के दौरान उर्वरक और कृषि' है। इस मंच ने कोविड-19 के दौरान उर्वरक आपूर्ति-मांग, मूल्य रुझानों, नीतिगत वातावरण, उर्वरक उपयोग दक्षता, उर्वरक उत्पादन प्रौद्योगिकियों में विकास और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्रों में विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान की।

टीडीबी ने इस आयोजन में भाग लिया तथा भारत के विशिष्ट अंतरालों को समझने और भारतीय कृषि उद्योग को आवश्यक समर्थन देने के अवसर का पता लगाया।



भारतीय उर्वरक संघ का 56वां वार्षिक संगोष्ठी

26वां डीएसटी-सीआईआई भारत-पुर्तगाल प्रौद्योगिकी सम्मेलन

07-09 दिसम्बर, 2020

टीडीबी ने दिसम्बर 07-09, 2020 के दौरान आयोजित 26वें डीएसटी-सीआईआई प्रौद्योगिकी महा सम्मेलन में भाग लिया। महा सम्मेलन के फोकस के विषय जल तकनीक, एग्रीटेक, स्वास्थ्य तकनीक, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, आईटी, आईसीटी, उन्नत प्रौद्योगिकी, स्टार्ट-अप और नवाचार और अंतरिक्ष-महासागर अंतःक्रिया थे।

भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान के माननीय मंत्री

डॉ. हर्षवर्धन ने 7 दिसम्बर 2020 को महा सम्मेलन और डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, सचिव डीएसटी और अध्यक्ष टीडीबी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस महा सम्मेलन ने द्विपक्षीय साझेदारी बनाने और मजबूत करने हेतु एक मंच के रूप में काम किया है, जिससे नए संयुक्त उपक्रमों का निर्माण हुआ और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए मार्ग तैयार हुए।



26वां डीएसटी-सीआईआई भारत-पुर्तगाल प्रौद्योगिकी महा सम्मेलन

आईआईएसएफ 2020 का पूर्व-कार्यक्रम

10 दिसंबर, 2020

10 दिसंबर, 2020 को 'आईआईएसएफ 2020 का एक पूर्व-कार्यक्रम' आयोजित किया गया था, जिसे संयुक्त रूप से प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, सीएसआईआर-एनईआईआरआई और अंतरराष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान (आईआईडब्ल्यूएम), बेंगलूर द्वारा इस विषय "उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अपशिष्ट प्रबंधन में विकास" पर समन्वित किया गया था। वेबिनार में महत्वाकांक्षी उद्यमियों, प्रारंभिक चरण के स्टार्ट-अप

और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में अन्य पारिस्थितिकी तंत्र के कंपनियों को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने, उप-क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और उद्यमिता और वित्त पोषण के अवसरों के लिए अवसर प्रदान किया गया।

टीडीबी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और नवीन भारतीय तकनीकी उद्यमियों के लिए टीडीबी के पास उपलब्ध वित्तपोषण के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया।



आईआईएसएफ 2020 का पूर्व-कार्यक्रम

छठा स्मार्ट सिटीज इंडिया 2021 एक्सपो

24 – 26 मार्च 2021

यह कार्यक्रम भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) और एक्जीबिशन इंडिया ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया था और 24-26 मार्च 2021 से प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एक्सपो प्रमुख वर्टिकल में इमारतें, सौर, परिवहन, पानी आदि सहित स्मार्ट सिटी के स्मार्ट सिटी फ्रेमवर्क को दिखाया गया है।

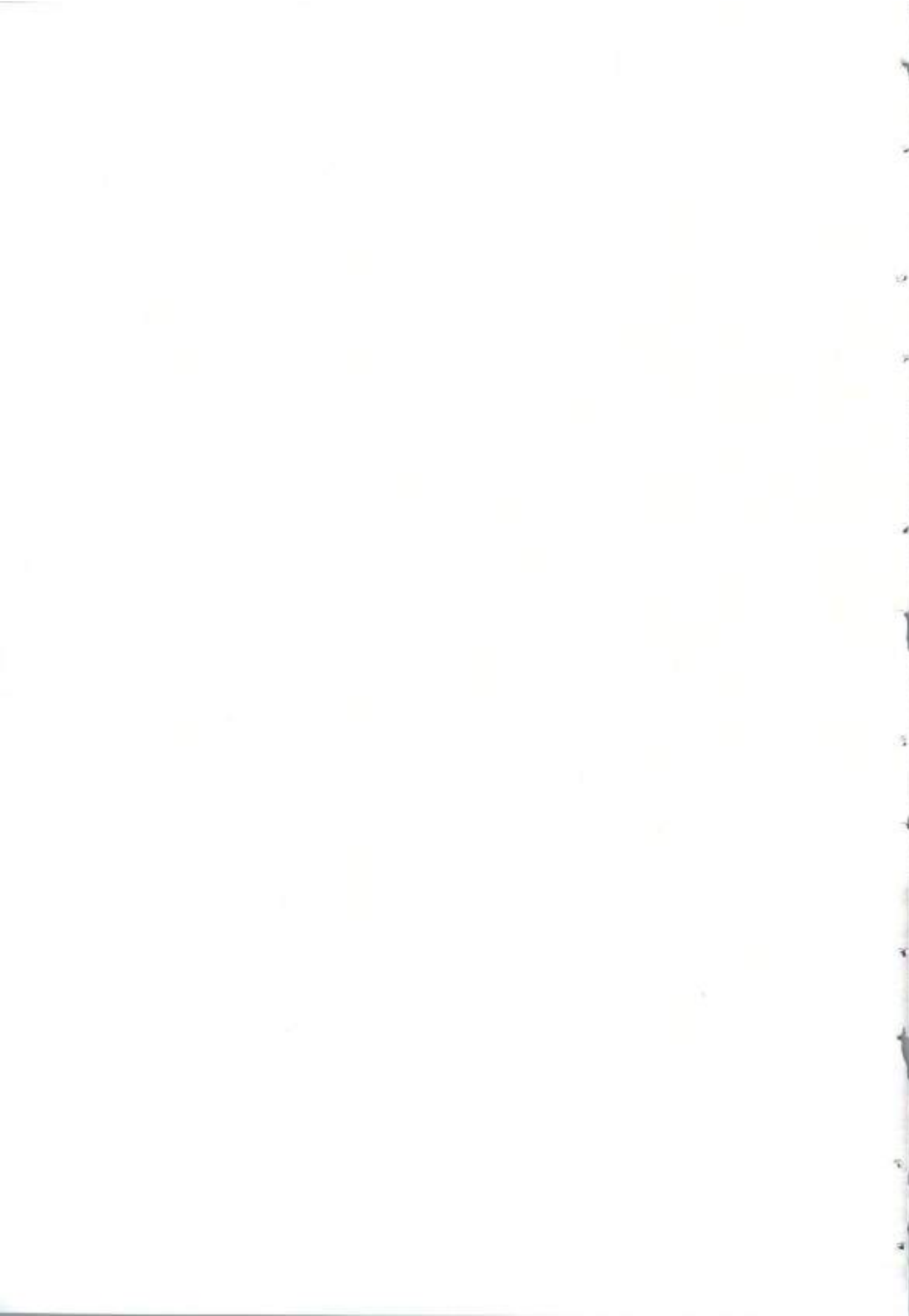
छठा स्मार्ट सिटीज इंडिया 2021 एक्सपो द्वारा एक ऐसा मंच प्रदान किया गया, जो सामाजिक समस्याओं को

हल करने के लिए गहन संचार और अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण को सक्षम बनाता है, स्मार्ट शहरों को वास्तविकता बनाने की दिशा में काम करने वाले संगठनों के लिए व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है।

टीडीबी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और नवीन तकनीकी उद्यमों के लिए टीडीबी में उपलब्ध धन के अवसरों को साझा किया।



नई दिल्ली में छठा स्मार्ट सिटीज इंडिया 2021 एक्सपो





प्रशासन

प्रशासन

वार्षिक रिपोर्ट और लेखा विवरण

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 की धारा 12 वित्तपोषण किया गया है कि बोर्ड पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का पूरा लेखा-जोखा देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम की धारा 13 (4) के अनुसार, बोर्ड को केंद्र सरकार को लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ खातों की लेखा परीक्षित प्रति प्रस्तुत करनी होती है।

वर्ष 2019-20 के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षित प्रति सहित वार्षिक रिपोर्ट को क्रमशः 09.02.2021 और 12.02.2021 को राज्य सभा और लोकसभा के समक्ष रखा गया।

टीडीबी सचिवालय

श्रीमती निष्ठा भटनागर, पूर्व प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, टीडीबी में 08.02.2021 से लेखा अधिकारी के रूप में शामिल हुई हैं।

राजभाषा का कार्यान्वयन

राजभाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन



सुनिश्चित करने की दृष्टि से, टीडीबी सभी आधिकारिक संचार में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करता रहा है। सितंबर, 2020 के माह में हिंदी पखवाड़ा/हिंदी दिवस मनाया गया, जिसमें श्रुतलेख, निबंध लेखन, कविता, भाषण, अनुवाद आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

2020-21 के दौरान 18.11.2020 को हिंदी संसदीय राजभाषा समिति की मसौदा एवं साध्य उपसमिति द्वारा टीडीबी का निरीक्षण किया गया।

सतर्कता सप्ताह का पालन

भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्राप्त करने के लिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग 'भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता' की नीति को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2020 के लिए, आयोग ने 27 अक्टूबर से 02 नवंबर 2020 तक 'सतर्क भारत, समृद्ध भारत' विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का निर्णय लिया।

टीडीबी ने भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता नीति के

सख्त पालन के साथ एक भ्रष्टाचार मुक्त संगठन होने की जिम्मेदारी स्वीकार की, जिसके लिए टीडीबी ने 27 अक्टूबर से 02 नवंबर 2020 तक सतर्कता सप्ताह मनाया, जिसकी शुरुआत सभी अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों द्वारा ईमानदारी की शपथ के साथ हुई। सप्ताह के दौरान

प्रश्नोत्तरी, वाद-विवाद, भाषण, निबंध लेखन और नारा लेखन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। टीडीबी के प्रत्येक स्टाफ सदस्य ने जोश और उत्साह के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया।





वार्षिक विवरण



खातों का लेखापरीक्षित वार्षिक विवरण वर्ष 2020-21 के लिए

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड 31 मार्च, 2021 की स्थितिनुसार तुलन-पत्र

(राशि रु. में)

	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
कॉरपस / कैपिटल फंड और दायित्व			
कॉरपस / कैपिटल फंड	1	15,68,59,44,667	14,68,52,37,882
रिजर्व और सरप्लस	2	-	-
निर्धारित / इनडॉवमेंट फंड	3	8,60,24,859	4,63,51,775
सुरक्षित ऋण और लेनदारी	4	-	-
असुरक्षित ऋण और लेनदारी	5	-	-
आस्थगित क्रेडिट दायित्व	6	-	-
वर्तमान दायित्व और प्रावधान	7	73,68,10,769	77,34,99,891
कुल		16,50,87,80,295	15,50,50,89,548
परिसम्पत्तियाँ			
निर्धारित परिसम्पत्तियाँ	8	84,95,873	66,77,633
निर्धारित इनडॉवमेंट फंड में निवेश	9	65,99,000	65,99,000
निवेश - अन्य	10	1,16,63,34,106	1,40,19,52,366
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि	11	15,32,73,51,316	14,08,98,60,549
विविध खर्च (घूट न दिए जाने अथवा समायोजित न किए जाने की सीमा तक)			
कुल		16,50,87,80,295	15,50,50,89,548
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24	-	-
आकरिमक दायित्व और लेखों पर टिप्पणियाँ	25	-	-

-इ-
(राजेश जैन)
निदेशक
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

-इ-
(डॉ. भीरज शर्मा)
सचिव
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

-इ-
(प्रो. आशुतोष शर्मा)
अध्यक्ष
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

(राशि रु. में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
विक्री / सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान / सस्किडी	13	11,56,38,978	98,38,34,331
फीस / अंशदान	14	-	-
निवेश से आय (ईयरमाकड/इनडॉवमेंट में निवेश पर आय)	15	-	-
राजरव, प्रकाशन आदि से आय	16	35,09,803	44,87,232
अर्जित ब्याज	17	60,00,36,912	63,60,54,565
अन्य आय	18	35,78,35,993	3,03,563
पूर्ण हो चुकी और चल रही मदों में वृद्धि/गिरावट	19		
कुल (क)		1,07,70,21,687	1,62,46,79,691
व्यय			
स्थापना व्यय	20	3,66,06,098	3,35,32,639
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	3,26,45,669	35,21,08,711
अनुदान, सस्किडी इत्यादि पर व्यय	22	12,05,791	10,84,242
ध्याज	23	-	209,24,330
मूल्यहास (अनुसूची 8 के अनुरूप वर्ष के अंत में सकल योग)		14,32,703	11,03,455
कुल (ख)		7,18,90,260	40,87,53,377
व्यय पर आय में अधिकता (क-ख)		1,00,51,31,426	1,21,59,26,314
पूर्व अवधि समायोजन		(44,24,641)	(2,45,734)
निवेश के हानि के लिए प्राकधान			
सामान्य आरक्षित कोष में अंतरण		-	-
कॉरपस फंड में दिया गया अतिरिक्त शेष		1,00,07,06,785	1,21,56,80,580
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक दायित्व और लेखा टिप्पणियां	25		

-ह-
(राजेश जैन)
निदेशक
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

-ह-
(डॉ. नीरज शर्मा)
सचिव
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

-ह-
(प्रो. आशुतोष शर्मा)
अध्यक्ष
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा

(राशि रु. में)

प्राप्तियाँ		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आरम्भिक शेष:			
i)	अत्यावधि जमा में निवेश	56,99,00,000	49,95,00,000
ii)	चुलम नकद	34,976	23,520
	बैंक में शेष		
a)	बैंक में शेष	1,26,10,21,180	7,59,89,345
b)	बैंक में शेष-डीएफआईडी इन्वेंट	3,97,52,776	13,66,14,643
प्रौद्योगिकी विकास और आवेदन निधि			
i)	टी डी फंड	10,00,00,000	98,00,00,000
ii)	फाइटिंग कोविड-19 के लिए निधि	-	75,00,00,000
iii)	अत्यावधि जमा पर ब्याज	4,23,09,523	3,34,75,287
iv)	ऋण पर ब्याज	18,08,99,609	7,64,94,764
v)	राजस्व पर ब्याज	2,16,794	2,95,247
vi)	ऋण वसूली के खिलाफ लंबित समायोजन	14,78,533	-
vii)	ऋण की अदायगी	96,47,10,885	63,33,72,600
viii)	राजस्व	35,09,803	44,87,232
ix)	दान	2,00,000	3,00,000
x)	अव्ययित अनुदान वापिस आया	1,56,38,978	38,34,331
xi)	बचत खातों पर ब्याज (ईपीएफ खाते सहित)	1,79,99,301	86,65,931
xii)	डीसीएफ फंड से प्राप्त आय	36,60,29,271	-
xiii)	विविध प्राप्तियाँ	32,399	3,563
xiv)	संपत्ति प्राप्तियाँ	12,399	-
xv)	सुरक्षा जमा/अग्रिम धन प्राप्त/अन्य	-	1,64,231
xvi)	मल्टी सेक्टर सीड फंड	9,61,39,030	76,55,900
xvii)	यूटीआई एसेट इंडिया फंड	-	1,46,31,293
xviii)	आरपीसीएफ	1,17,74,229	34,34,150
xix)	जीवीएफएल	-	-
xxi)	इक्विटी प्राप्ति	7,02,64,200	6,56,68,800

xxii)	सिडबी वेंचर फंड	2,25,23,262	1,44,18,678
xxiii)	इंडियन फंड फॉर सस्टेनेबल एनर्जी (सी आई आई ई)	77,66,033	-
xxiv)	आईवी कंपनी वेंचर ट्रस्ट फंड-1	1,57,41,937	10,34,438
xxv)	एपीआईडीसी वेंचर फंड	39,60,314	2,50,00,000
xxvi)	सीफ-इंडिया फंड	11,21,514	1,86,63,888
xxvii)	सुरक्षा जमा एवं कर्मचारियों को अग्रिम वापसी राशि	93,085	-
xxviii)	डीएफआईडी इन्वेंट परियोजना के लिए प्राप्ति	3,76,96,231	-
xxvix)	डी एफ आई डी इन्वेंट बचत ब्याज	19,76,923	31,38,224
	कुल	3,83,28,03,186	3,35,68,66,065

-इ-
(राजेश जैन)
निदेशक
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

-इ-
(डॉ. नीरज शर्मा)
सचिव
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

-इ-
(प्रो. आशुतोष शर्मा)
अध्यक्ष
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियों एवं भुगतान का लेखा

(राशि रु. में)

भुगतान		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
स्थापना व्यय			
i)	वेतन	3,56,72,789	3,16,67,445
ii)	यात्रा व्यय (घरेलू)	13,58,457	17,73,934
iii)	यात्रा व्यय (अंतर्राष्ट्रीय)	-	-
iv)	कर्मचारी कल्याण खर्च	1,11,023	77,000
v)	चिकित्सा व्यय	5,06,052	2,23,558
vi)	प्रतिनियुक्ति के लिए पेशन अंशदान	-	-
कार्यालय व्यय			
i)	टेलीफोन/टेलेक्स	19,23,299	20,66,491
ii)	झाक टिकट	37,310	55,443
iii)	पेट्रोल, तेल एवं लूब्रीकेन्ट्स	19,487	41,422
iv)	मरम्मत कार्य एवं अनुक्षण	25,24,758	12,80,715
v)	उपभोज्य स्टोर्स एवं मुद्रण	6,59,099	12,09,624
vi)	समाचार पत्र एवं पत्रिका	-	36,123
vii)	मनोरंजन एवं अतिथि सत्कार	86,601	1,90,132
viii)	बैठकों पर व्यय	2,31,719	15,33,468
ix)	विज्ञापन एवं प्रचार	44,20,269	63,26,171
x)	प्रौद्योगिकी दिवस पर खर्च	18,94,259	6,96,212
xi)	विविध खर्च	7,69,525	6,59,475
xii)	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	-	885
xiii)	कानूनी शुल्क	34,95,859	44,78,038
xiv)	परिसम्पत्ति प्रबंधन प्रभार	29,74,302	71,96,785
xv)	विशेषज्ञों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	2,85,667	26,04,299
xvi)	विशेषज्ञों एवं सदस्यों को मानदेय	46,28,073	55,00,880
xvii)	सदस्यता शुल्क	47,200	23,600
xix)	लेखा परीक्षा शुल्क	-	77,850
xx)	किराया	68,28,548	85,36,700
xxi)	अन्य विभागों को पुनर्वसूली का प्रेषण	-	-
xxii)	सुरक्षा जमा एवं कर्मचारी को अग्रिम राशि	-	46,505
xxiii)	अग्रिम अन्य	40,453	-
xxiv)	शुल्क एवं कर	1,12,088	4,60,031
xxv)	पानी एवं बिजली	3,71,929	-

बोर्ड खर्च			
i)	सदस्यों को यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता	9,308	24,457
ii)	शुल्क एवं बोर्ड की बैठक पर खर्च	-	1,43,645
पूँजीगत व्यय			
i)	अचल संपत्तियाँ	32,63,343	9,12,353
संवितरण			
i)	ऋण	47,56,85,000	1,28,37,12,000
ii)	अनुदान	12,05,791	10,84,242
iii)	दिए गए अनुदान पर ब्याज	-	2,09,24,330
iv)	कोविड-19 अनुदान के तहत जारी ऋण	2,12,00,000	-
v)	कोविड के लिए अनुदान	1,39,38,000	
vi)	एसईएएफ इंडिया एग्री बिजनस फंड	-	5,77,473
vii)	इंडियन फंड फॉर सस्टेनेबल एनर्जी (सीआईआईई)	10,89,645	20,15,756
viii)	डीएफआईडी इन्वेंट परियोजना व्यय	-	10,00,00,000
ix)	डीएफआईडी इन्वेंट बैंक प्रभार	71	91
x)	अन्य देय व्यय	18,35,268	-
अंतर्शेष			
i)	अत्यावधि जमा में निवेश	1,66,99,00,000	56,99,00,000
ii)	सुलभ रोकड़	22,149	34,976
	बैंक में नकदी		
a)	बैंक में जमा (ईपीएफ खाते सहित)	1,49,62,29,986	1,26,10,21,180
b)	बैंक में जमा-डीएफआईडी इन्वेंट	7,94,25,859	3,97,52,776
	कुल	3,83,28,03,186	3,35,68,66,065

-ह-
(राजेश जैन)
निदेशक
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

-ह-
(श्री. नीरज शर्मा)
सचिव
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

-ह-
(प्रो. आशुतोष शर्मा)
अध्यक्ष
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष को तुलन पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची -1 कॉरपस/कैपिटल फंड			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
वर्ष के प्रारंभ की स्थिति के अनुसार शेष	14,68,52,37,882		13,46,95,57,302
जमा: कॉरपस/कैपिटल फंड: के लिए अंशदान	-		-
जमा: आय और व्यय लेखे से स्थानांतरित सकल आय का शेष [नोट न. 25(11) देखें]	1,00,07,06,785		1,21,56,80,580
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार शेष		15,68,59,44,667	14,68,52,37,882

अनुसूची 2- आरक्षित एवं अधिशेष राशि			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1. कैपिटल रिजर्व:			
अंतिम लेखा के अनुसार			
वर्ष के दौरान जमा			
घटा: वर्ष के दौरान कटीती	-	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व:			
अंतिम लेखा के अनुसार			
वर्ष के दौरान जमा			
घटा: वर्ष के दौरान कटीती	-	-	-
3. विशेष रिजर्व:			
अंतिम लेखा के अनुसार			
वर्ष के दौरान जमा			
घटा: वर्ष के दौरान कटीती	-	-	-
4. सामान्य रिजर्व:			
अंतिम लेखा के अनुसार			
वर्ष के दौरान जमा			
घटा: वर्ष के दौरान कटीती			
कुल	-	-	-

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष को तुलन पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 3- अलग से निर्धारित/इनडोवमेंट विधि

दायित्व	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. आईडीबीआई का वीसीएफ				
1. भारत सरकार से आई डी बी आई द्वारा प्राप्त अंशदान		28,84,00,000		28,84,00,000
निवेश से आय				
(क) ब्याज	13,31,47,041		13,08,52,144	
(ख) राजस्व	5,51,97,900		5,51,97,900	
(ग) लाभांश	86,23,794		86,23,794	
(घ) उपार्जित आय घटा छूट	2,38,80,81,913		2,39,03,76,810	
	2,58,50,50,648		2,58,50,50,648	
घटा : टीडीबी को दी गई राशि	21,25,00,000		21,25,00,000	
	2,66,09,50,648		2,37,25,50,648	
घटा : मूलधन में समायोजित पूर्य प्राप्त अधिशेष रॉयल्टी	1,12,50,000		1,12,50,000	
	2,64,97,00,648		2,36,13,00,648	
घटा : बट्टे खातों में डाला गया ऋण	4,36,36,450		4,36,36,450	
घटा : निवेश की बिजली पर हानि	26,76,250		26,76,250	
	2,60,33,87,948		2,31,49,87,948	
घटा : ऋण विषयक प्रावधान	8,32,79,357		8,10,04,357	
घटा : ब्याज विषयक प्रावधान एवं एफआईएलडी	2,38,80,81,913		2,39,03,76,810	
घटा : लेखा परीक्षा शुल्क एवं अन्य व्यय	18,32,324		17,52,075	
घटा : आईडीबीआई को प्रदान किया गया प्रबंधन शुल्क	15,71,80,000		14,32,60,000	
घटा : निवेश के मूल्य में कमी	26,26,000	(2,96,11,646)	26,26,000	(30,40,31,294)
		(296,11,646)		-1,56,31,294
*टी डी बी से प्राप्य धनराशि (दिनांक 31.03.2019)		3,62,10,646		222,30,294
		65,99,000		65,99,000
ख. इन्वेंट - डीएफआईडी		7,94,25,859		3,97,52,775
	कुल	8,60,24,859		4,63,51,775

*नोट:

1. विधि के तहत- निष्पादन की वजह से आई डी बी आई द्वारा दावा किए गए प्रबंधन खर्च की राशि को टी डी बी द्वारा विवादित कर दिया गया है।
2. आई डी बी आई द्वारा ₹ 3,62,10,646/- रूपए की राशि का दावा किया गया है जो दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के उनके अंतिम लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार टी डी बी द्वारा देय है। उक्त राशि आई डी बी आई द्वारा प्रभारित उच्च प्रबंधन शुल्क के कारण उत्पन्न हुई है। टी डी बी उक्त राशि के समन्धान को लंबित रखते हुए उक्त राशि का भुगतान स्वीकार नहीं करता है।

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष को तुलन पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 4- प्रतिभूत ऋण एवं उधार				
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	1. केन्द्र सरकार	-	-	-
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं				
(क) आवधिक ऋण				
(ख) अर्जित ब्याज एवं देय	-	-	-	-
4. बैंक				
(क) आवधिक ऋण				
- अर्जित ब्याज एवं देय				
(ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)				
- अर्जित ब्याज एवं देय	-	-	-	-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	-	-	-	-
6. डिबेंचर्स एवं बॉन्ड्स	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
नोट : एक वर्ष के भीतर बकाया राशि				

(राशि रु. में)

अनुसूची 5- अप्रतिभूत ऋण एवं उधार				
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	1. केन्द्र सरकार	-	-	-
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)				
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-	-	-
4. बैंक				
(क) आवधिक ऋण	-	-	-	-
(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	-	-	-	-
6. डिबेंचर्स एवं बॉन्ड्स	-	-	-	-
7. अचल जमा	-	-	-	-
8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
नोट : वर्ष के भीतर देय राशि				

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष को तुलना पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 6- आस्थगित ऋण देयताएं				
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. कैपिटल उपकरणों एवं अन्य परिसंपत्तियों के ऋण भार द्वारा सुरक्षित सहमति	-	-	-	-
ख. अन्य				
	कुल			
नोट : वर्ष के भीतर देय राशि				

(राशि रु. में)

अनुसूची 7- चालू देयताएं एवं प्रावधान				
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. चालू देयताएं				
1. "कोविड-19 से लड़ने" के लिए सहायता अनुदान का अप्रयुक्त शेष	73,60,62,000			75,00,00,000
घटा: कोविड-19 फंड के तहत ऋण के लिए उपयोग किया गया	2,12,00,000	71,48,62,000		
2. विविध लेनदार				
क. माल के लिए	-			
ख. अन्य	-	-		
3. प्राप्त प्रतिभूति				-
4. अर्जित ब्याज जो निम्नलिखित पर देय नहीं है:				
क. प्रतिभूत ऋण/उधार				
ख. अप्रतिभूत ऋण/उधार	-	-		-
5. सांविधिक देयताएं				
क. टीडीएस	2,80,049		3,60,502	
ख. जीएसटी	28,029		48,961	
ग. जीपीएस देय				
घ. ईपीएस देय	3,23,094	6,31,172	3,33,797	7,43,260
6. अन्य चालू देयताएं				
क. प्रतिनियुक्ति के लिए पेंशन अंशदान				
ख. देय लेखा परीक्षा शुल्क	4,69,839			3,89,839
ग. लंबित समायोजन	-			-
घ. अन्य	-	4,69,839		-
	कुल (क)	71,59,63,011		75,11,33,099
ख. प्रावधान				
1. ग्रेज्युटी	21,39,484			17,08,387
2. देय वेतन	16,91,054			18,05,917
3. देय विधिक प्रभार	-			
4. देय राष्ट्रीय पुरस्कार	1,70,00,000			1,70,00,000
5. देय अन्य खर्च	17,220	2,08,47,758		18,52,488
	कुल (ख)	2,08,47,758		2,23,66,792
	कुल (क+ख)	73,68,10,769		77,34,99,891

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष को पुलन पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

विवरण	सकल खर्च			अवशुद्धन				निवल खर्च	
	वर्ष के प्रारंभ से स्थिति के अनुसार लागत/मूल्य	वर्ष के दौरान खर्च/मूल्य	वर्ष के अंत में समाप्त/मूल्य	वर्ष के प्रारंभ से स्थिति के अनुसार अनुसार	वर्ष के दौरान फर्निचर के खर्च/मूल्य	वर्ष के अंत तक जोड़	विवर्धन / समाप्त/मूल्य	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार
क. स्थायी परिसम्पत्ति									
1. भूमि									
क. प्रीपेय्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. विलेय									
क. प्रीपेय्ड भूमि पर									
ख. लीजहोल्ड भूमि पर									
ग. स्वामित्वकारी परदेह / परिसर									
घ. जमीन पर अधिरचना अस्तित्व से संबद्ध नहीं									
3. प्लॉट एवं मशीनरी									
4. कठन	6,74,375	-	6,74,375	3,22,347	52,804	3,75,151	-	2,99,224	3,52,028
5. मशीन/विकासपर	50,84,975	-	50,84,975	23,46,988	2,73,799	26,20,787	-	24,64,188	27,37,987
6. भागीदार उपकरण	54,82,572	5,00,869	59,83,441	28,72,308	4,40,274	33,12,582		26,70,859	26,10,264
7. कंप्यूटर उपकरण / सॉफ्टवेयर	29,06,870	-	29,06,870	25,04,639	1,55,932	25,94,691	12,399	2,33,899	4,02,231
8. इलेक्ट्रिक अधिसूचना									
9. उपकरणों के मूल्य									
10. सॉफ्टवेयर (मूल्य) (40%)	7,18,904	-	7,18,904	1,43,781	3,71,770	5,15,551		2,03,353	5,75,123
11. अन्य अवल परिसम्पत्तियाँ	27,62,474	-	27,62,474	-	1,38,124	1,38,124		26,24,350	-
11. अन्य अवल परिसम्पत्तियाँ									
सकल वर्ष का कुल खर्च	148,67,696	32,63,343	180,52,759	81,90,063	14,32,703	95,56,886	12,399	84,95,873	66,77,633
ख. पूंजीगत कार्यों प्रगति पर (सॉफ्टवेयर)									
कुल	148,67,696	32,63,343	180,52,759	81,90,063	14,32,703	95,56,886	12,399	84,95,873	66,77,633
(सर्वोच्च सहित विवरण पर कम आकार पर परिसम्पत्तियों की लागत पर दी जाने वाली छिपकियाँ)									
विवरण	139,55,343	9,12,353	148,67,696	70,86,608	11,03,455	81,90,063	-	66,77,633	68,68,735

नोट:
1. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान (मि.ए.ए.ए.) पर मूल्यांकन ₹2,36,201/- से कम प्रचारित किया गया था। इस राशि का दावा वार्षिक वर्ष में जोड़कर मूल्यांकन के रूप में किया गया है।
2. वर्ष के दौरान पूंजीगत ई-सामान्य सॉफ्टवेयर पर मूल्यांकन को 88 वर्ष के जीवन के पूर्ण मूल्य के परिकल्पना के लिए सीमा रखा के आधार पर प्रारंभ किया गया है।

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष को तुलना पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 9- निर्धारित / अक्षय निधियों से निवेश			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		-	-
3. शेयर		-	-
4. डिबेंचर और बॉन्ड्स		-	-
5. सक्तिडिबेंचरिज एवं संयुक्त उद्यम		-	-
6. आई डी वी आई का वीसीएफ (परिसम्पत्ति)		-	-
निवेश			
(i) ऋण	8,10,04,357		8,10,04,357
घटा : प्रावधान	8,10,04,357	-	8,10,04,357
(ii) इक्विटी	92,25,000		92,25,000
घटा : निवेश के मूल्य में कमी	26,26,000	65,99,000	26,26,000
वसूली योग्य			
(i) ब्याज	29,97,69,021		29,97,69,021
(ii) एफआईएलडी	2,09,06,07,789		2,09,06,07,789
	2,39,03,76,810		2,39,03,76,810
घटा : प्रावधान	2,39,03,76,810	-	2,39,03,76,810
कुल		65,99,000	65,99,000

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष को तुलना पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 10 – निवेश – अन्य			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में			
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों			
3. शेयर- इक्विटी/अधिमान भागीदारी	20,81,62,967		20,81,62,967
घटा : शेयर की तुलना में प्राप्ति	7,02,64,200	13,78,98,767	
4. डिबेंचर्स और बॉन्ड्स			
5. सहायक उद्यम एवं संयुक्त उद्यम			
6. वेन्चर फंड			
क. यूटीआई एसएट इंडिया फंड	-		
ख. एपीआईडीसी वेन्चर निधि	20,97,86,000		
घटा : विमोचन	39,60,314	20,58,25,686	20,97,86,000
ग. वेचर ईस्ट टीनेट फंड	4,41,43,882		
घटा : विमोचन	-	4,41,43,882	4,41,43,882
घ. जीवीएफएल	1,50,000		
घटा : विमोचन	-	1,50,000	1,50,000
ड. आरवीसीएफ	11,44,40,574		
घटा : विमोचन	2,02,02,156	9,42,38,418	11,44,40,574
च. सिडबी वीसीएफ	17,43,08,185		
जमा : वितरण	-		
घटा : विमोचन	2,25,23,262	15,17,84,923	17,43,08,185
छ. आईबी कंपनी वेचर ट्रस्ट फंड-1	21,58,57,800		
जमा : वितरण	-		
जमा : पूर्व अवधि समायोजन	10,10,541		
घटा : विमोचन	1,57,41,937	20,11,26,404	21,58,57,800
ज. मल्टी सेक्टर सीड कैपिटल फंड	9,63,44,100		
घटा : विमोचन	9,61,39,030	2,05,070	9,63,44,100
झ. सीफ इंडिया एग्री बिजनेस फंड	21,00,49,055		
जमा : सवितरण	-		
घटा : विमोचन	11,21,514	20,89,27,541	21,00,49,055
ञ. इंडियन फंड फॉर सस्टेनेबल एनर्जी (सीआईआईई)	5,66,59,803		
जमा : सवितरण	10,89,645		
घटा : विमोचन	77,66,033	4,99,83,415	5,66,59,803
7. जी आई टी ए	7,20,50,000		
जमा : वितरण	-	7,20,50,000	7,20,50,000
कुल		1,16,63,34,106	1,40,19,52,366

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष को तुलना पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि ₹. में)

अनुसूची 11 – चालू परिसम्पत्ति, ऋण एवं अग्रिम आदि			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
क. चालू परिसम्पतियां:			
1. सूची :			
क) भंडार एवं अतिरिक्त			
ख) अनिश्चित साधन (लूज टूल्स)			
ग) स्टॉक इन ट्रेड			
i) निर्मित वस्तुएं			
ii) कार्य प्रगति पर			
iii) कच्चा माल	-	-	-
2. विविध देनदार			
क) छ: माह से अधिक की अवधि से लंबित ऋण			
ख) अन्य		-	-
3. हाथ में शेष रोकड़ (चेक/ड्राफ्ट एवं बयाना सहित)		22,149	34,976
4. बैंक में जमा			
क) सूचीगत बैंकों के साथ			
- चालू खाते पर			
- बचत खाते में – टी डी बी (ई पी एफ खाता सहित)	1,49,62,29,986		1,26,10,21,180
- बचत खाता-इन्वेंट-डीएफआईडी	7,94,25,85,859	1,57,56,55,845	3,97,52,776
ख) सूचीगत बैंकों के साथ लघु अवधि जमा			
- जमा खाते पर	1,66,99,00,000	1,66,99,00,000	56,99,00,000
- जमा खाते पर इन्वेंट पर डीएफआईडी			
कुल (क)		3,24,55,77,994	1,87,07,08,932

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष को तुलना पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 11 - चालू परिसम्पत्ति, ऋण, अग्रिम इत्यादि (जारी है)			
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां :			
1. ऋण:			
(क) कर्मचारी			
(ख) अन्य सत्ताएं जो उनसे मिलती जुलती सत्ताओं की गतिविधियों / उद्देश्यों में सम्मिलित	-		-
(ग) ऋण- औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सहायता	-		-
आरंभिक	7,90,43,22,401		7,30,99,65,366
जमा : वर्ष के दौरान	47,56,85,000		1,28,37,12,000
घटा : ऋण की अदायगी / समायोजन	96,47,10,885		67,63,10,641
घटा : खातों के निपटारे के कारण से बढ़े खातों में डाला गया	-		1,11,54,978
घटा : अर्जित ब्याज में अंतरण	-		18,89,347
जमा : पूर्व अवधि समायोजन	26,78,872		
	7,41,26,17,644		7,90,43,22,401
घटा : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	-		-
प्रावधान के बाद ऋण शेष राशि बंद करना		7,41,26,17,644	7,90,43,22,401
2. नकद अथवा वस्तु में अदायगी करने योग्य अग्रिम एवं अन्य राशि अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य			
क) कर्मचारियों को अग्रिम	7,78,195		8,71,280
ख) पुनः प्राप्ति करने योग्य आयकर	14,91,903		11,38,824
ग) अन्य-प्रतिभूति जमा	9,90,280		9,90,280
घ) विक्रेताओं के पास अग्रिम धनराशि	-		-
इ) अन्य	64,509	33,24,887	24,056
3. अर्जित आय :			
क) बचत खातों पर			
ख) निर्धारित / इनडोवमेंट फंड से निवेश पर	63,00,311		-
ग) निवेश पर - अल्पावधि जमा	94,98,531	1,57,98,842	36,83,794
अल्पावधि जमा- इन्वेंट-डीएफआईडी	-		-
घ) ब्याज एवं अग्रिम राशि पर	4,88,56,24,552		4,56,25,70,377
घटा : वर्ष के दौरान वसूली नहीं करने योग्य ब्याज को बढ़े खातों में डाला गया	-		2,28,56,713
घटा : ऋण में अंतरण	-		
घटा : वर्ष के दौरान पूर्व अवधि समायोजन	27,56,310		6,45,734
जमा : ऋण से अंतरण	-		18,89,347
	4,88,28,68,242		4,54,09,57,277
घटा : ऋण ब्याज प्रावधान :	23,28,36,293		23,28,36,294
		4,65,00,31,949	4,30,81,20,983
कुल (ख)		12,08,17,73,322	12,21,91,51,617
कुल (क+ख)		15,32,73,51,316	14,08,98,60,549

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष को आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 12 - बिक्री / सेवाओं से आय :			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1. बिक्री से आय			
क) निर्मित वस्तुओं की बिक्री			
ख) कच्चे माल की बिक्री			
ग) कबाड़ की बिक्री	-	-	-
2. सेवाओं से आय			
क) श्रम एवं संसाधित प्रभार			
ख) व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएं			
ग) एजेंसी कमीशन और दलाली			
घ) रखरखाव सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)			
ड) अन्य (निर्दिष्ट करें)			-
कुल	-	-	-

(राशि रु. में)

अनुसूची 13 - अनुदान / सन्धिः (गैर-वसूली योग्य अनुदान एवं वसूली गई सन्धिः)			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार		10,00,00,000	98,00,00,000
2. राज्य सरकार (रि)			
3. संस्थान/कल्याण बोर्ड		-	-
4. अंतर्राष्ट्रीय संगठन			
5. अन्य - अव्ययित अनुदान वापिस आया		1,56,38,978	38,34,331
कुल		11,56,38,978	98,38,34,331

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष को आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 14 – शुल्क/अंशदान			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1) प्रवेश शुल्क	-	-	-
2) वार्षिक शुल्क/अंशदान			
3) गोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-	-	-
4) परामर्शी शुल्क	-	-	-
कुल	-	-	-
टिप्पणी : प्रत्येक मद की बताई जाने वाली लेखा नीतियों का निर्धारित फंड से निवेश			

(राशि रु. में)

अनुसूची 15 – निवेश से आय: (फंड में हस्तांतरित किया गया निर्धारित/इनडोवमेंट फंड से निवेश पर आय)			
	निर्धारित फंड से निवेश		अन्य निवेश
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष
1) ब्याज			
क) सरकारी प्रतिभूति पर			
ख) अन्य बॉन्ड्स पत्र/डिबेंचर			
2) लामांश			
क) शेयर पर			
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर			
3) किराए	-	-	-
4) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-
कुल			
निर्धारित/इनडोवमेंट फंड में हस्तांतरित			

(राशि रु. में)

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकारान आदि से आय		
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) रॉयल्टी से आय	35,09,803	44,87,232
2) उपार्जित रॉयल्टी		
घटा: राजस्व माफी		-
3) अन्य: (निर्दिष्ट करें)		
कुल	35,09,803	44,87,232

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष को आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज		
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) आवधिक जमा पर:		
क) सूचीगत बैंकों के साथ	4,81,24,260	2,91,22,606
ख) गैर-सूचीगत बैंकों के साथ		-
ग) संस्थाओं के साथ		-
2) बचत खातों पर:		
क) सूचीगत बैंकों के साथ (ईपीएफ खाता सहित)	2,42,99,612	86,65,931
ख) गैर-सूचीगत बैंकों में		-
ग) एक घर बचत खाता		-
घ) अन्य		
3) ऋण पर:		
क) कर्मचारी/स्टाफ		
ख) औद्योगिक इकाई को ऋण सहायता	52,59,17,713	59,79,70,781
4) राजस्व पर ब्याज	2,16,794	2,95,247
5) अनुदान पर ब्याज	14,78,533	-
कुल	60,00,36,912	63,60,54,565
नोट : स्रोत पर कर कटौती को दर्शाया जाएगा।		

(राशि रु. में)

अनुसूची 18 - अन्य आय		
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) संपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:		
क) प्राप्त संपत्ति-यूटीआई		
ख) अनुदान से अधिश्रुत अथवा निशुल्क प्राप्त संपत्ति		
2) यूनिटों के विमोचन से लाभ	35,76,01,344	-
3) लाभांश	-	-
4) विविध आय	4,649	3,563
5) बैठक शुल्क	30,000	-
6) दान	2,00,000	3,00,000
7) वेन्चर फंड से आय	-	-
कुल	35,78,35,993	3,03,563

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष को आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 19 – निर्मित वस्तुओं के भंडार में वृद्धि/ह्रास			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
क) बंद स्टॉक			
– तैयार माल			
– चल रहा कार्य	-	-	-
ख) घटा : ओपनिंग स्टॉक			
– तैयार माल			
– चल रहा कार्य	-	-	-
निवल वृद्धि/(घटाव) (क-ख)	-	-	-

(राशि रु. में)

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
क. वेतन एवं मजूदारी		3,41,15,706	3,09,94,096
ख. भत्ता		29,023	4,32,759
ग. भविष्य निधि में नियोजता का अंशदान		14,42,220	14,49,312
घ. यूनिफॉर्म		-	-
ङ. कर्मचारी कल्याण खर्च		82,000	77,000
च. कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभों पर व्यय		-	-
छ. विकित्सा प्रभासों की प्रतिपूर्ति		5,06,052	2,23,558
ज. ग्रेज्यूटी		4,31,097	3,55,914
	कुल	3,66,06,098	3,35,32,639

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की आय एवं व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय इत्वादि	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) राष्ट्रीय पुरस्कार	-	1,70,00,000
ख) विधि प्रभार	34,95,859	45,81,332
ग) संपत्ति प्रबंधन शुल्क	29,74,302	71,96,785
घ) सदस्यता शुल्क	47,200	23,600
ङ) टी.डी.एस एवं ब्याज	-	-
च) परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि	-	-
छ) नरम्मत एवं रख-रखाव	25,24,758	12,80,715
ज) डाक एवं टिकट	37,310	55,443
झ) प्रौद्योगिकी दिवस व्यय	18,94,259	6,96,212
ण) वाहन चालन और रखरखाव	19,487	41,422
ट) टेलीफोन एवं संचार प्रभार	19,23,299	21,25,374
ठ) प्रिंटिंग, स्टेशनरी एवं उपभोग्य	6,59,099	12,34,404
ड) यात्रा क) घरेलू यात्रा खर्च	13,58,457	-
ख) विदेशी यात्रा खर्च	-	-
ग) विशेषज्ञों की यात्रा पर खर्च	2,85,667	16,44,124
ढ) पुस्तकालय की पुस्तकें एवं आवधिक पत्रिका	-	885
ण) बोर्ड के सदस्यों को टीए/डीए	-	24,457
प) लेखा परीक्षा शुल्क	80,000	80,000
फ) आवभगत व्यय	86,601	1,90,132
ब) बैठकों पर व्यय	2,31,719	15,85,545
भ) व्यवसायिक प्रभार	46,28,073	55,12,480
म) क) वर्ष के दौरान अप्राप्य ब्याज को बढ़ते खाते में डाला गया	-	2,28,56,713
ख) ऋण के मूल मूल्य को बढ़ते खाते में डाला गया	-	1,11,54,978
ग) ऋण प्रावधान	-	(89,05,867)
घ) वर्ष का ब्याज प्रावधान	-	(1,10,58,058)
य) बैंक प्रभार	-	-
र) विविध व्यय	7,69,525	6,74,975
ल) समाचार पत्र एवं पत्रिका	-	36,123
व) विज्ञापन एवं प्रचार	44,20,269	63,26,171
श) बोर्ड के व्यय एवं शुल्क	9,308	1,43,645
ष) किराया	68,28,548	90,69,257
स) नवीनीकरण एवं पुनर्संज्जा	3,71,929	-
ह) वेंचर फंड समापन के कारण हानि (अनुसूची 25 नोट 5 का संदर्भ लें)	-	27,52,88,902
कुल	3,26,45,679	35,21,08,711

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की आय एवं व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 22 – अनुदान पर व्यय		
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) संस्थाओं एवं संगठनों को दिया गया अनुदान		
(i) इन्क्यूबेटर्स	12,05,791	10,84,242
(ii) अन्य एजेंसियां	-	-
2) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सब्सिडी		
कुल	12,05,791	10,84,242
नोट: संस्थाओं के नाम, उनकी गतिविधियों के साथ अनुदान/सब्सिडी का खुलासा।		

(राशि रु. में)

अनुसूची 23 – ब्याज		
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) अचल ऋण पर		
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)		
ग) अन्य-डीएसटी से प्राप्त अनुदान	-	2,09,24,330
कुल		2,09,24,330

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

लेखा: 2020-21 पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और टिप्पणियाँ

क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. प्राप्तियाँ और भुगतान के ब्यौरे खाते नकद प्राप्ति पत्रिका से तैयार किए जाते हैं और विभिन्न शीर्षों के तहत नकद लेनदेन का सारांश है। इसमें पूंजी और राजस्व स्वरूप दोनों की प्राप्तियों और भुगतानों को रिकॉर्ड किया जाता है।
2. आय और व्यय खाता वर्ष की आय और व्यय का सारांश है। इसे प्रोद्घवन के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें केवल राजस्व स्वरूप की आय और व्यय को रिकॉर्ड किया जाता है। वितरित ऋण राशि पर अर्जित उपाजित ब्याज को उस वर्ष में शामिल किया जाता है जिसमें ऋण किस्त जारी की जाती है, जबकि, संबंधित ऋण करारों के नियमों और शर्तों के अनुसार परियोजनाओं को पूरा करने के बाद ब्याज वास्तव में प्राप्य राशि होती है। वर्ष के दौरान देय और स्वीकृत व्यय के प्रावधान का लेखा विवरण बनाया जाता है।
3. अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास, हासमान शेष राशि विधि पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित दरों और आधार पर प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान बेची गई / हस्तांतरित / त्याग दी गई अचल परिसंपत्तियों पर कोई मूल्यहास प्रदान नहीं किया जाता है। अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि का हिसाब अधिग्रहण की लागत पर किया जाता है।
4. रॉयल्टी भुगतान प्राप्ति और भुगतान खाते और आय और व्यय खाते में प्राप्ति के आधार पर लिया जाता है।
5. सरकारी अनुदानों को प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है। अव्ययित शेष राशि भारत सरकार को वापस

नहीं की जानी चाहिए क्योंकि सरकार द्वारा जारी अनुदान प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 की धारा 9(1) (क) के संदर्भ में प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग के लिए निधि में जमा किया जाता है और इस प्रकार वापसी की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, भारत सरकार को वापसी के लिए कोई राशि देय नहीं है।

6. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 की धारा 9 (1) के अनुसार, प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग हेतु निधि से दी गई राशियों, ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, रॉयल्टी, दान और किसी अन्य स्रोत से प्राप्त राशियों से की गई वसूली को कोष के लिए क्रेडिट किया जाता है। इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए तुलन पत्र तैयार किया गया है।
7. आईडीबीआई द्वारा रखे गए निर्धारित/धर्मादा निधि (उद्यम पूंजी निधि) के तुलन पत्र में निम्नलिखित संकेत दिए गए हैं :-
 - क) तुलन पत्र आय/व्यय के संबंध में रॉयल्टी प्रबंधन शुल्क और उस पर दंडात्मक ब्याज को छोड़कर प्रोद्घवन आधार पर तैयार किया जाता है, जिसे वास्तविक प्राप्ति/भुगतान पर मान्यता दी जाती है।
 - ख) परिसंपत्तियों / ऋणों / निवेशों का मूल्यांकन आईडीबीआई (निधि प्रबंधक) द्वारा मूल्यांकन मूल्य पर किया गया है और वित्तीय विवरणों में उपलब्ध कराए गए नोटों के अनुसार परिसंपत्तियों के बही मूल्य को कम करने का प्रावधान दर्ज किया गया है।
 - ग) आईडीबीआई (वीसीएफ) के वित्तीय विवरणों को आईडीबीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए तुलन पत्र

के साथ संलग्न अन्य नोटों और स्पष्टीकरणों के साथ पढ़ा जाना है। वित्तीय विवरणों और खातों की टिप्पणियों को आईडीबीआई द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रमाणित और उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट के रूप में रिकॉर्ड में लिया जाता है।

8. राष्ट्रीयकृत बैंकों में निधि की शेष राशि अल्पावधि जमा में रखी जाती है। अल्पकालिक जमा राशियों पर ब्याज प्राप्ति और भुगतान खाते और तुलन पत्र में परिलक्षित होता है।
9. कंपनियों में निवेश लागत मूल्य पर बताया गया है। टीडीबी के अधिदेश के अनुसार, निवेश को पूंजी वृद्धि के लिए या टीडीबी को किसी अन्य लाभ के लिए नहीं रखा जाता है, शेषों को अधिग्रहण की लागत पर तब तक रखा जाता है जब तक कि वे अंततः प्राप्त नहीं हो जाते। जबकि, संबंधित कंपनी के समापन या विघटन या किसी अन्य कारण से निवेश के उचित मूल्य में कोई स्थायी गिरावट, गिरावट का मूल्य आय और व्यय खाते पर प्रभारित किया जाता है।
10. चूक के मामले में, पुनर्निर्धारण करार जो भी किया जाता है, उसे ऋण करार के नियमों और शर्तों के अनुसार अलग रखा जाता है और खाते में शेष मूल करार को बहाल कर दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप मूल करार पर वापस लौटने के कारण उधारकर्ता की बकाया राशि में वृद्धि हो सकती है।
11. उस मामले में जहां उधारकर्ता ऋण करार की शर्तों के अनुसार ऋण / ब्याज राशि का भुगतान करने में असमर्थ है और जब ऋण करार के गैर-अनुपालन से उत्पन्न विवाद और परिणामस्वरूप मामला मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है। ऐसे मामलों में ऋण और ब्याज की बकाया राशि को मध्यस्थता के संदर्भ की तिथि पर रोक दिया जाता है। एवॉर्ड की शर्तों के अनुसार एवॉर्ड पारित होने के बाद ही बकाया ब्याज में आगे प्रावधान या समायोजन किया जाता है।
12. ऐसे मामले में जहां उधारकर्ता ने ऋण करार के अनुसार अपने ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है और तब से परिसमापन में चला गया है, ब्याज की बुकिंग परिसमापन की तारीख तक सीमित कर दी गई है। आधिकारिक समापक से अंतिम भुगतान की प्राप्ति के बाद मूलधन और ब्याज के लिए बट्टे खाते में डालने का अंतिम प्रावधान किया जाता है क्योंकि वसूली की तिथि तक ब्याज का दावा करने का अधिकार टीडीबी द्वारा बनाए रखा जाता है।
13. कंपनी जिसकी स्थिति को पंजीकृत कंपनियों की सूची से हटा दिया गया है या कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के रिकॉर्ड के अनुसार परिसमापन के दौर से गुजर रहा है, जहां ऋण राशि और ब्याज अतिदेय / अमुगतानित रहता है, कानूनी खंड को संदर्भित किया गया है। जबकि, चूक की उच्च संभावना और शेष राशि की पुष्टि न होने के कारण, चालू वर्ष के लिए कोई ब्याज नहीं लिया गया है। संदिग्ध वसूली या बट्टे खाते में डालने का अंतिम प्रावधान प्रत्येक कंपनी के मामले में कानूनी विभाग द्वारा मामले को कानूनी रूप से बंद करने की सिफारिश और पुष्टि के अधीन है।
14. एक उधारकर्ता द्वारा चूक के मामले में और बाद में एक मध्यस्थता एवॉर्ड के पारित होने के मामले में, ऋण और ब्याज का पुनर्कथन और ब्याज की वसूली भी एवॉर्ड के अनुसार की जाती है। इसके परिणामस्वरूप उधारकर्ता से बकाया ब्याज की राशि में कमी / वृद्धि हो सकती है।
15. मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू होने के मामले में, ब्याज का प्रभार कार्यवाही शुरू होने की तिथि से निर्णय पारित होने तक बंद कर दिया जाता है। एवॉर्ड के बाद, अन्य शर्तें स्थिर बनी रहती हैं, ऋण और उस पर ब्याज का हिसाब एवॉर्ड के अनुसार होता है।
16. यदि पूर्ण सहमत राशि के लिए धन राशि जारी नहीं की गई है और समयबद्ध पुनर्भुगतान अनुसूची सक्रिय है, तो ब्याज की गणना करार के अनुसार लागू दर पर जारी राशि के आधार पर की जाती है।
17. उद्यम निधि के साथ निवेश अन्य सीड निधि लागत पर किया जाता है। चूंकि निधि अपनी गतिविधियों के

संदर्भ में लगातार विकसित हो रहे हैं और यह एक सतत चिंता का विषय है, निवेश के मूल्य में कोई स्थायी परिवर्तन की परिकल्पना या प्रावधान नहीं किया गया है। आय/हानि को उद्यम निधि निवेश में या तो निधि के समापन होने या निधि की अवधि के दौरान आय के वितरण पर मान्यता दी जाती है।

18. जब तक टीडीबी द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, तब तक एक उधारकर्ता से प्राप्त भुगतान को निम्नलिखित क्रम में इस तरह के बकाया के

लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, अर्थात्, अतिरिक्त ब्याज सहित ब्याज; चूक राशि पर आगे ब्याज और परिसमाप्त क्षति; मूलधन की चुकौती देय किश्तें और देय या बोर्ड द्वारा तय और अनुमोदित तरीके से।

19. प्रबंधन द्वारा वार्षिक आधार पर स्टॉक सत्यापन किया जाता है।

20. आंकड़ों को निकटतम रूप में पूर्णांकित किया जाता है।

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

लेखा: 2020-21 पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और टिप्पणियाँ

खातों पर टिप्पणियाँ

1. टीडीबी को वित्तीय वर्ष 2020.21 के दौरान अनुदान के रूप में ₹ 1000 लाख रुपए (पिछले वर्ष ₹ 9800 लाख रुपए) मिले।
2. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के पास 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार ₹ 21937.28 लाख रुपए (पिछले वर्ष ₹ 21765.44 लाख रुपए) की बकाया ऋण चुकौती (देय राशि लेकिन प्राप्त नहीं हुई) है। इसके अतिरिक्त, साधारण ब्याज ₹ 10994.42 लाख रुपए (पिछले वर्ष ₹ 10810.20 लाख रुपए), ₹ 23265.42 लाख रुपए (पिछले वर्ष ₹ 21751.21 लाख रुपए) के ऋण पर अतिरिक्त ब्याज तथा ₹ 8347.34 लाख रुपए
4. उद्यम पूंजी निधि (डीसीएफ) में निवेश और मूल्यांकन :

(पिछले वर्ष ₹ 7533.55 लाख रुपए) साधारण ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज के रूप में भी बकाया थे।

3. गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) और इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी नीति 2016 पर सरकार की नीति में बदलाव के साथ, टीडीबी अतिदेय खातों के पर्याप्त प्रतिशत की वसूली के लिए आशान्वित है। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान उधारकर्ताओं के साथ निपटान के लिए अभ्यावेदन, विवाद समाधान समिति (डीआरसी) की सिफारिश या ऐसे मामलों में कानूनी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई अन्य जानकारी के आधार पर किया जाता है, और दावा राशि के अंतिम निपटान पर स्थायी हानि की पहचान की जाती है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई का सम मूल्य	निर्दिष्ट एवं सतिपूर्ति की गई राशि						अति इकाई एनपी			
			31.03.2019 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि		वर्ष के दौरान जमा		वर्ष के दौरान सतिपूर्ति/हानि		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार जमा राशि		31.03.19 की स्थिति के अनुसार एनपी	31.03.20 की स्थिति के अनुसार एनपी
			राशि (रुपये में)	इकाई की संख्या	राशि (रुपये में)	इकाई की संख्या	राशि (रुपये में)	इकाई की संख्या	राशि (रुपये में)	इकाई की संख्या		
1	एचआईवीसी वेयर कंपिटल फंड प्राइवेट लिमिटेड	1,00,000	20,97,86,000	2,098	-	-	39,60,314	40	20,98,25,000	2,058.26	3,239	1,86,333
2	जीडीएनएल लिमिटेड अल्पव्यवध	1,00,000	1,50,000	1.50	-	-	-	-	1,50,000	1.30	1,42,77,994	1,35,42,460
3	आईसीएच वेयर इंटल प्रॉडक्ट्स	1,00,000	21,56,57,800	2,369	-	-	1,57,41,937	157	20,11,26,404	2,011	79,099	1,64,702
4	ब्लू वेयर कंपिटल फंड/बल्टी वेयर वेयर कंपिटल फंड	10,000	9,63,44,100	9,634	-	-	9,61,39,030	9,814	2,05,070	21	28,383	34,235
5	एनएनटीएच एंड-ऑपरेटिव इंटल II	100	11,44,40,574	11,44,404	-	-	2,02,82,156	2,02,822	9,42,36,418	9,42,384	106	120
6	राष्ट्रिय ड्रिग एंड क्लियर फंड	5,00,000	21,00,49,053	420	-	1	11,21,514	2	20,89,27,541	417.86	48,754	23,356
7	मिडवे वेयर कंपिटल लिमिटेड - इंडिया ओपेरेटिव्स फंड	1,000	17,43,08,185	1,74,308	-	-	2,24,23,262	22,523	15,17,84,923	1,51,785	677	623
8	वेयर इंटल लिमिटेड फंड II	758	4,41,43,882	1,30,000	-	-	-	-	4,41,43,882	1,30,000	1,090	830
9	सीआईआई-इंडियन फंड फॉर सर्वोपेक एनपी (आईईई इंटल)	100	5,66,59,803	5,66,598	10,89,645	10,896	77,66,033	77,660	4,99,83,415	4,99,834	125	125
			1,12,27,49,940	20,49,632	10,89,643	10,896	16,74,54,346	3,12,018	95,63,85,319			

(*) लेखा परीक्ष नहीं किए गए परिसंपत्तियों के अनुसार अनिश्चित एनपी
 (**) लेखा टिप्पणियों की अनुसूची 25 में संख्या 3 का संदर्भ में है

	एनपी मूल्य (रुपये में)	निवेश की लागत	अनुप्राणित (हानि)/लाभ
संशोधन एवं विकास	75,80,73,932	95,63,85,339	- 19,83,11,407
विकास	96,95,53,550	1,12,27,49,940	- 15,31,96,390

टिप्पणी :

- 1) ऊपर उल्लिखित अनुसूची 24 के पैरा 17 के अनुसार निधि द्वारा वितरण के आधार पर मान्यता प्राप्त उद्यम निधि से मोचन

क) वर्ष के दौरान अर्जित वर्ष के दौरान उद्यम निधि निवेश की इकाइयों के मोचन पर आय (हानि) :

(राशि ₹. में)

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभ / (हानि) लाख में
1.	मेसर्स आइवीकैप वेंचर ट्रस्ट फंड	3181.68
2.	मेसर्स ब्लूम वेंचर कैपिटल फंड	478.61
3.	मेसर्स एसएमई टेक फंड - आरवीसीएफ ट्रस्ट II	(84.28)
	कुल लाभ (हानि)	3576.01

5. टीडीबी ने सीआईआई के साथ संयुक्त उद्यम में मेसर्स ग्लोबल इनोवेशन टेक्नोलॉजी एलायंस (जीआईटीए) के साथ क्रमशः 51 : 49 के इक्विटी योगदान में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के सभी प्रमुख तत्वों को कवर करने हेतु करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे डीएसटी और अन्य संगठनों के साथ उद्योग और प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप लाभान्वित होते हैं। 31 मार्च 2021 तक जीआईटीए में टीडीबी की इक्विटी भागीदारी 7.21 करोड़ रुपए है।
6. वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित सहायता अनुदान वितरित किया गया।

क्र. सं.	कंपनी का नाम	उद्देश्य	राशि (₹. लाख में)
1.	उन्नत अनुसंधान संवर्धन इंडो क्रेंच सेंटर (सीईएफआईपीआरए)	कार्यक्रम प्रबंधन	12.06
	कुल		12.06

7. निर्धारित / धर्मादा निधि : (अनुसूची 3)

(क) भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान से संबंधित उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) लेनदेन के कारण 1 सितंबर 1996 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) की बहियों में बकाया धन प्राप्तियों

और देनदारियों का हस्तांतरण बोर्ड को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है। आईडीबीआई ने 31.3.2021 को समाप्त चालू वर्ष के लिए खातों का लेखापरीक्षित विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। आईडीबीआई द्वारा पिछले कई वर्षों से उनके द्वारा धारित पोर्टफोलियो में मौजूदा निवेश के प्रति कोई और निवेश या वसूली की सूचना नहीं दी गई है। 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (जो कि आईडीबीआई की जिम्मेदारी थी) प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए 31.03.2019 को वित्तीय मूल्यों को शामिल किया गया है।

(ख) उधारकर्ता के बकाया/वसूली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अर्थात् : उधारकर्ता से वसूली योग्य राशि जिसमें अर्जित ब्याज की राशि/झापन बहियों में अतिरिक्त ब्याज शामिल होगा, की सूचना दी गई है। इसके अलावा, अर्जित ब्याज सहित अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जहां वसूली प्रक्रिया समाप्त हो गई है और ऋण खातों से कोई और पुनर्भुगतान की उम्मीद नहीं है और इसे बोर्ड द्वारा बट्टे खाते में डालने के लिए अनुमोदित किया गया है।

(ग) परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिए आईडीबीआई द्वारा लिया गया प्रबंधन शुल्क टीडीबी द्वारा देय होने के लिए सहमत नहीं है तथा इसे निपटान के लिए आईडीबीआई के साथ लिया गया है। टीडीबी द्वारा आईडीबीआई को देय होने का दावा की गई 3,62,10,646 रुपए की राशि अंतिम निपटान के लिए आकरिमक है।

8. आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) और अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी), ग्रेट ब्रिटेन की सरकार के माध्यम से भारत सरकार के बीच समझौते के अनुसार टीडीबी के साथ समझौता ज्ञापन दिनांक 29.8.2013 को सहमति व्यक्त की गई थी कि विकास के लिए नवाचारी उद्यम और प्रौद्योगिकी (इनवेंट) कार्यक्रम के ऊष्मायन घटक को टीडीबी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, और भारत सरकार के साथ कार्यान्वित और उसकी निगरानी की जाएगी। टीडीबी की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि परियोजना के समग्र आउटपुट और परिणाम देने के लिए आवश्यक अनुमोदित गतिविधियों पर धन खर्च किया जाएगा। टीडीबी इस निधि को एक

अलग बैंक खाते में रखने के लिए बाध्य है तथा बैंक जमा पर अर्जित ब्याज कार्यक्रम के लिए उपलब्ध अतिरिक्त निधि के हिस्से के रूप में निधि में जमा किया जाना है और निधि प्रबंधक के रूप में समय से परियोजना दिशानिर्देश के अनुसार जारी किया जाना है और डीएफआईडी को प्रगति रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा प्रस्तुत करें।

9. परियोजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार डीएसटी/सीड/टीडीबी/कोविड-19/एससीएसपी (जी) के आदेश के अनुसार, 7500.00 लाख रुपए कोविड 19 से निपटने के लिए अनुदान और ऋण के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान के लिए इक्विटी अधिकारिता और विकास (बीज) प्रभाग द्वारा जारी किए गए थे। कोविड-19 वायरस द्वारा देश में हुए कहर को दूर करने के इरादे से टीडीबी को निधि प्रदान की गई थी। प्राप्त राशि को लक्षित परियोजना निधि के अंतर्गत लेखा किया जाता है और सरकार की ओर से उपयोग/प्राप्ति और वापसी, यदि कोई हो, को उक्त निधि में शामिल किया जाता है। लेनदेन टीडीबी अनुदान का हिस्सा नहीं है।
10. टीडीबी ने उन कंपनियों को कोविड महामारी के कारण स्थगन राहत प्रदान की है, जिनका पुनर्भुगतान अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2020 के बीच होता है।

टीडीबी ने उस अवधि के दौरान मूलधन पर केवल 5 प्रतिशत साधारण ब्याज लगाया है। यह 11 अप्रैल, 2020 और 24 जून, 2020 की कोविड नीति के अनुसार है।

11. टीडीबी ने अपने ऋण की वसूली और एनआईसीसीओ कॉर्पोरेशन (प्रा.) लिमिटेड में इक्विटी में अपने निवेश से पहले एनसीएलटी के समक्ष एक आवेदन को प्राथमिकता दी थी। एनसीएलटी ने इक्विटी में निवेश को टीडीबी द्वारा दिए गए ऋण के हिस्से के रूप में माने जाने का आदेश दिया है। कंपनी की परिसमापन कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली सभी प्राप्तियों को पहले बकाया ऋण राशि और शेष राशि को इक्विटी के तहत निवेश की लागत के प्रति समायोजित किया गया है।
12. निम्नलिखित कंपनियों के खिलाफ संदिग्ध ब्याज और ऋण पर अतिरिक्त ब्याज और मूल राशि का प्रावधान किया गया है, जो विवाद समाधान समिति (डीआरसी) की प्रस्तावित सिफारिश और उप द्वारा अनुमोदित के अनुसार अपने बकाया/बकाया का निपटान करने के लिए सहमत हुए हैं। बोर्ड की समिति या जहां मामला ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में स्वीकार किया गया है और वसूली को संदिग्ध माना जाता है। वर्ष के दौरान कोई और ब्याज प्रदान नहीं किया गया है।

31.03.2021 तक प्रावधान का विवरण निम्नलिखित है।

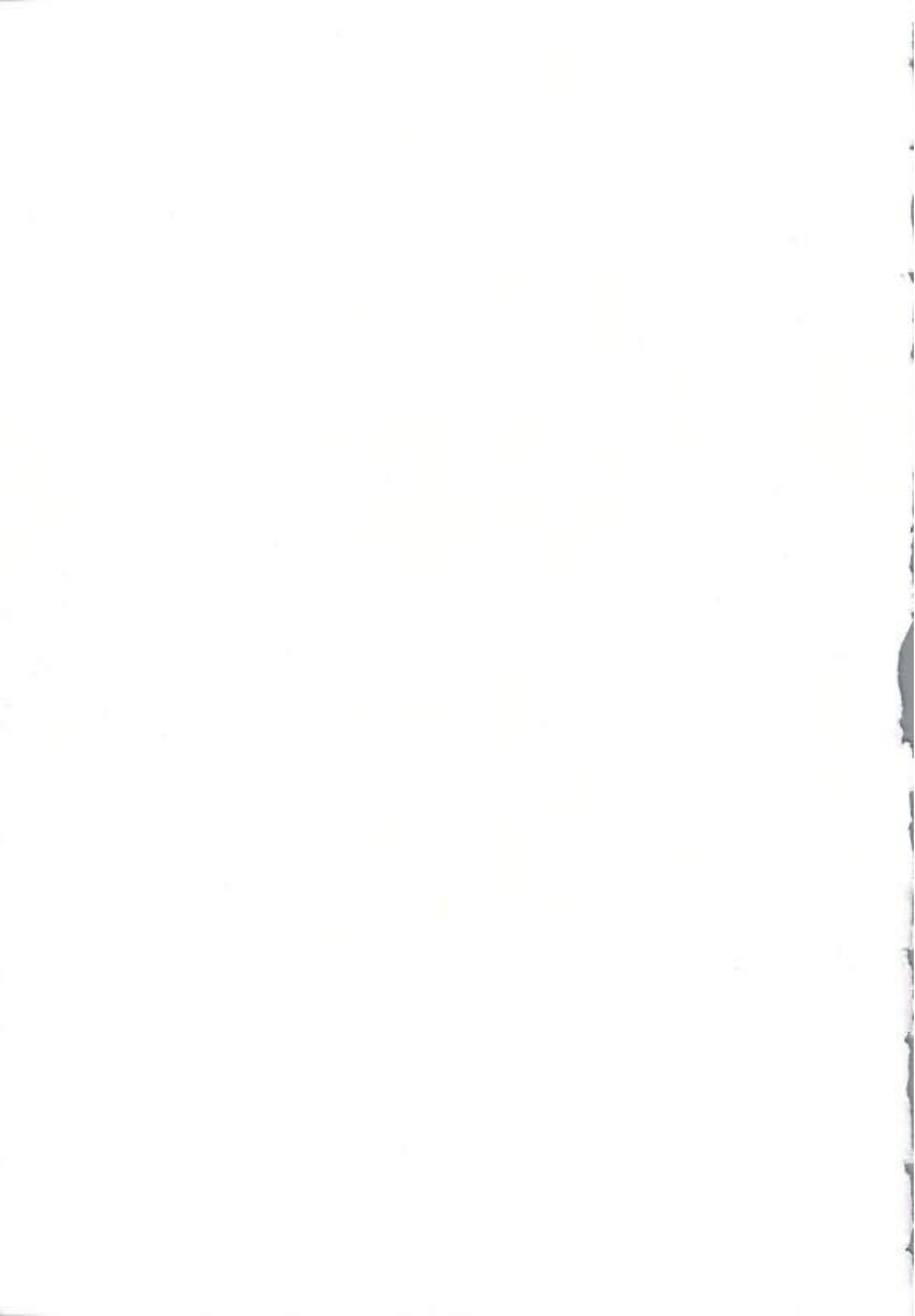
कंपनियों का नाम	ब्याज और अतिरिक्त ब्याज का प्रावधान (रु. लाख में)			
	2016-17	2017-18	2019-20	Total
मेसर्स मेडिराड		408.81	-	1114.21
मेसर्स कोरल टेलीकॉम		23.29	-	123.33
मेसर्स वाटरलाइफ		1.01	-	1.01
मेसर्स अमलगम लेदर	-	880.78	-	880.78
मेसर्स एक्सपोनेंशियल		92.88	-	92.88
मेसर्स डोरबन एग्रो	-	-	116.16	116.16
कुल	805.44	1,406.77	116.16	2,328.37

13. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना योग्य बनाने के लिए पुनः सनूहित और पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

-इ-
(राजेश जैन)
निदेशक
प्रायोगिकी विकास बोर्ड

-इ-
(डॉ. नीरज शर्मा)
सचिव
प्रायोगिकी विकास बोर्ड

-इ-
(प्रो. आशुतोष शर्मा)
अध्यक्ष
प्रायोगिकी विकास बोर्ड





**पृथक लेखा
परीक्षा रिपोर्ट**
2020-21



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा,
वैज्ञानिक विभाग
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली 110 002
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT,
SCIENTIFIC DEPARTMENTS,
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110002

महा.नि.ले.प.(वै.वि.)/नि./2(20)/TDB/Annual A/cs/2021-22/ 711-712

Dated: 10-11-2021

सेवा में,

अवर सचिव
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड
ए-विंग, ग्राउंड फ्लोर,
विश्वकर्मा भवन,
शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली - 110 016

विषय: प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के लेखों पर पृथक ऑडिट रिपोर्ट।

महोदय,

मुझे प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के लेखों पर पृथक ऑडिट रिपोर्ट अरोपित करने का निर्देश हुआ है।

संसद के दोनों सदनो में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखों को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा अपनाया जाए। प्रत्येक दस्तावेज जो संसद में प्रस्तुत किया जाए उसकी तीन प्रतियां इस कार्यालय तथा दो प्रतियां भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अरोपित की जाए। संसद के दोनों सदनो में प्रस्तुत करने की तिथि (यां) भी इस कार्यालय को सूचित की जाएं।

आपसे अनुरोध है कि पृथक ऑडिट रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद अपने कार्यालय में कराने के पश्चात सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी दोनों में हमें भेज दें ताकि हिन्दी प्रति को शीघ्र अरोपित किया जा सके।

यह महानिदेशक द्वारा अनुमोदित है।

अनदीय,

संलग्नक: यथोपरि।

निदेशक (निरीक्षण)

प्रतिलिपि:

1. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, रिपोर्ट (स्वा.नि.), कार्यालय भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली को इस कार्यालय में e-mail दिनांक 28.10.2021 के संदर्भ में। आपके कार्यालय द्वारा किये गए परिवर्तन/सुझाव को सम्मिलित कर लिया गया है। पृथक ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम कॉपी भी मुख्यालय की टिप्पणियों के उत्तर और प्रपत्र की प्रति भी इसके साथ संलग्न की जा रही है।

निदेशक (निरीक्षण)

वर्ष 2020-21 के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

नई दिल्ली के लेखा पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

- हमने 31 मार्च 2021 तक प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी), नई दिल्ली के संलग्न तुलन पत्र और प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (1995 की संख्या 44) की धारा 13 (2) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के 19 (2) (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता / प्राप्तियां और भुगतान खाते की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण बोर्ड के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करें।
- इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन उपचार पर हैं। कानून नियम और विनियम (उचितता और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन पहलू आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन देन पर लेखा परीक्षा टिप्पणियां शामिल हैं, यदि कोई हों, को निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है।
- हमने भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षा किया है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरणों से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की जांच शामिल है। लेखा परीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।
- अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि -
 - हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे,
 - इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र, आय और व्यय खाते और प्राप्तियां और भुगतान खाते को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है,
 - हमारी राय में, बोर्ड द्वारा उचित लेखा पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का रखरखाव किया गया है, जहां तक ऐसी बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है,
 - हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) तुलन पत्र

देयताएं

वर्तमान देनदारियां और प्रावधान : ₹ 7368.11 लाख (अनुसूची 7)

टीडीबी ने प्रोजेक्ट "फाइंटिंग कोविड 19" के लिए ₹ 75 करोड़ के अनुदान पर अर्जित ब्याज ₹ 2.19 करोड़ को वर्तमान देनदारियों के बजाय अर्जित ब्याज के रूप में दिखाया है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.19 करोड़ तक की आय और वर्तमान देनदारियों को कम करके दिखाया गया।

ख. सामान्य

1. निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश – 65.99 लाख रुपए (अनुसूची 9)

पिछले वर्षों की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से टीडीबी के ध्यान में यह पहले ही लाया गया था कि कंपनियों में 'इक्विटी' के आकार में किए गए निवेश को उचित बाजार मूल्य पर दिखाना आवश्यक था।

हालांकि, टीडीबी ने इक्विटी (इसके मूल्य में कमी के बाद) में किए गए निवेश के मूल्य के पिछले वर्ष के ₹ 65.99 लाख के आंकड़े को अपनाया/शामिल किया। वर्ष 2020-21 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण आईडीबीआई से प्राप्त नहीं हुआ था और टीडीबी ने 31 मार्च 2019 को निर्धारित निधि के मूल्य को शामिल किया है। चूंकि चालू वर्ष के लिए इक्विटी का वारतविक/लेखापरीक्षित आंकड़ा (इसके मूल्य में कमी के बाद) वर्ष 2020-21 के लिए खातों की बहियों में दर्ज नहीं किया गया था, इसलिए, 31 मार्च 2021 को निवेश (इक्विटी) के रूप में रिपोर्ट की गई ₹ 65.99 लाख की राशि को लेखा परीक्षा के दौरान सत्यापित नहीं किया जा सका।

2. निवेश – अन्य – 11663.34 लाख रुपए (अनुसूची 10)

अनुसूची 10 में ₹ 116.63 करोड़ की राशि की सूचना दी गई थी: 'निवेश-अन्य' को 2020-21 के लिए टीडीबी के तुलन पत्र में जोड़ा गया, क्योंकि विभिन्न कंपनियों में 'इक्विटी/उद्यम पूंजी निधियों (वीसीएफ)' के आकार में निवेश किया गया था।

यह देखा गया था कि वहन राशि में कमी और इस तरह की कमी के किसी भी विपरीत हिसाब से लाभ और हानि के लिए चार्ज या क्रेडिट किया जाना आवश्यक था। हालांकि, पिछले वर्ष की अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किए जाने के बावजूद, टीडीबी ने उचित बाजार मूल्य पर उनका पुनर्मूल्यांकन नहीं किया।

3. टीडीबी ने उन कंपनियों की सूची को खातों पर अनुसूची-24 नोटों में नहीं दिखाया था, जिनकी स्थिति को पंजीकृत कंपनियों की सूची से हटा दिया गया है या कंपनी रजिस्टर (आरओसी) के रिकॉर्ड के अनुसार परिसमापन किया जा रहा है, जहां ऋण राशि और ब्याज अतिदेय/अभुगतानित बना रहता है।

ग. सहायता अनुदान

टीडीबी, अनुसंधान एवं विकास उपकर में से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से अनुदान प्राप्त करता है और प्रौद्योगिकी के आयात के लिए किए गए भुगतान पर सरकार द्वारा पांच प्रतिशत की दर से एकत्र किया जाता है। टीडीबी को 2020-21 के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से ₹ 10.00 करोड़ का अनुदान मिला।

टीडीबी को 187.07 करोड़ रुपए के प्रारंभिक नकद/बैंक शेष के अलावा, ₹ 196.21 करोड़ की राशि वर्ष 2019-20 के दौरान अल्पावधि जमा/ऋण/सॉयल्टी/अनुदान, ऋण की अदायगी, सॉयल्टी, उद्यम निधि से आय, दान आदि, पर ब्याज के रूप में प्राप्त हुई थी। निवेश, स्थापना/कार्यालय व्यय और ऋण/अनुदान के वितरण आदि के लिए कुल ₹ 58.72 करोड़ का भुगतान करने के बाद, 31 मार्च 2021 तक ₹ 324.55 करोड़ को अव्यय के रूप में दिखाया गया था।

घ. प्रबंधन पत्र :

वे कमियां जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से सचिव, टीडीबी के ध्यान में लाया गया है।

(v) पिछले पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र, आय और व्यय खाते और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए प्राप्तियां और भुगतान खाते खातों की बहियों के अनुरूप हैं।

(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाते हैं, और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और अन्य मामलों के अधीन हैं। इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिए गए हैं :

क. जहां तक यह 31 मार्च 2021 को प्रौद्योगिकी और विकास बोर्ड के मामलों की स्थिति के तुलन पत्र से संबंधित है; तथा

ख. जहां तक यह आय और व्यय खातों, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष से संबंधित है।

भारत के सीएजी के लिए और उनकी ओर से

—६०—

निदेशक महा लेखा परीक्षक
(पर्यावरण और वैज्ञानिक विभाग)

लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक -1

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

वर्ष 2018-20 के लिए टीडीबी की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई है। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि वर्ष 2008-10 से 2018-20 से संबंधित कुल 20 आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा 31 मार्च 2021 तक अनुपालन/निपटान के लिए बकाया थे।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 238 के अनुसार, प्रत्येक अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, यह दर्शाता है कि अनुदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था। तथापि, पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किए जाने के बावजूद, टीडीबी ने अनुदानग्राही संस्थानों से कुल ₹ 47.80 लाख के 3 मामलों के संबंध में समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया।

3. अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2020-21 के लिए अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था और प्रबंधन पत्र में विसंगतियों की सूचना दी गई है।

4. माल के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

टीडीबी ने उत्तर दिया कि उसके पास केवल 'अचल परिसंपत्ति' और 'उपभोग योग्य सामान' हैं। तदनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दोनों का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया गया है।

5. सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता :

कोई वैधानिक बकाया बकाया नहीं था।

संजय कुमार झा

डी.ओ.सं.डीजीए (ईएसडी) / निरीक्षण / 2(20) / ए / सी-टीडीबी / 2021-22 / 208

दिनांक : 10-11-2021

श्रीमान,

मैंने वर्ष 2020-21 के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वार्षिक लेखों का अंकेक्षण किया है और उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया है। लेखापरीक्षा के दौरान, कुछ कमियां देखी गईं जो अपेक्षाकृत मामूली प्रकृति की थीं और इसलिए, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गईं और अब अनुलग्नक में संलग्न हैं। इन्हें उपचारात्मक और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए आपके संज्ञान में लाया जा रहा है।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

भवदीय,

संलग्नक : अनुलग्नक

-80-

श्री राजेश कुमार पाठक

सचिव,

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड,

टेक्नोलॉजी भवन, नई दिल्ली 110016

प्रबंधन पत्र का अनुलग्नक

परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्ति : ₹ 84.96 लाख (अनुसूची 8)

टीडीबी ने कंप्यूटर परिधीय उपकरणों को 'कंप्यूटर के बजाय 'उपकरण/मशीनरी' शीर्ष के तहत दिखाया था, जिसके परिणामस्वरूप मूल्यवृद्धि का शुल्क कम किया गया और अचल परिसंपत्तियों को ₹ 2.09 लाख की सीमा तक बढ़ा दिया गया था। (अनुलग्नक-क)।

-ह0-

निदेशक (निरीक्षण)

अनुलग्नक-क

क्र. सं.	परिसंपत्ति का नाम	शुद्ध कुल संपत्तियां	2020-21 में जमा	कुल	2020-21 के लिए प्रभारित मूल्यहास (15 प्रतिशत की दर पर)	2020-21 के लिए प्रभारित की जाने पर मूल्यहास (40 प्रतिशत की दर पर)	अंतर
1.	प्रिंटर	264407	119451	383858	57579	153543	- 95964
2.	यूपीएस (500 / 1000)	362310	5150	367460	54733	145954	- 91221
3.	स्कैनर	4832	—	4832	725	1933	- 1208
4.	एमएस ऑफिस (मैक)		7951	7951	597	1590	- 993
5.	कंप्यूटर	7665	—	7665	1150	3066	- 1916
6.	यूपीएस 3केवीए	42061	—	42061	6309	160824	- 10515
7.	यूपीएस 2केवीए	31407	—	31407	4711	12563	- 7852
	कुल	81133	7951	845234	125804	335473	- 209669



Technology Development Board

Department of Science & Technology
Government of India



25th

Annual Report

2020-21



CONTENTS



SECRETARY'S DESK	01
TDB'S MANDATE	02
BOARD MEMBERS	04
OVERVIEW	06
TDB-YEAR AT A GLANCE	19
AGREEMENT SIGNED	27
PROJECT COMPLETED	41
PROMOTIONAL ACTIVITIES	45
ADMINISTRATION	57
AUDITED ANNUAL ACCOUNTS STATEMENT FOR THE YEAR 2020-21	61
SEPARATE AUDIT REPORT FOR THE YEAR 2020-21	91





From Secretary's Desk

As I reflect over this past year, I cannot help but think about the challenges thrown at us by the COVID-19 pandemic. The challenges we faced, at both personal and professional level, were immense. However, the pandemic has helped us to unite as a nation and face it head-on. The pandemic has also highlighted the need for resilient and adaptable science and technology led interventions for health, economic, and social systems.

In the year 2020-21, TDB received 264 applications that included 235 applications against call for proposals for "Fighting COVID-19". TDB issued the call for proposal seeking solutions for fighting COVID-19 pandemic and selected Indian companies, majorly start-ups, for providing financial support for commercialization of their products in the field of testing kits, masks & sanitization, thermal scanners and medical devices. Some of these companies have made meaningful contributions in India's fight against COVID-19.

TDB celebrated the Technology Day on May 11th by organizing a Digital Conference on "RE-START (Reboot the Economy through Science, Technology and Research Translations)" that brought together scientists, technocrats, government officials, diplomats, WHO officials and dignitaries from national and international Industry, Research Institutions and Academic Institutions to share their insights on the role of Science, Technology and Innovation in the global healthcare crisis and find solutions that would assist during the pandemic as well as help in facing the challenges ahead. TDB also actively participated via virtual mode in national conference, webinars and other events which helped in boosting TDB's role as a technology promoter towards making India self-reliant.

In this year, TDB entered into 13 agreements to provide financial assistance to various industrial concerns. Through these agreements, TDB has committed ₹ 23.74 crore as a loan and ₹ 7.30 crore as grant out of total project cost of ₹ 80.92 crore, covering various sectors such as Health & Medical, Engineering and Information Technology. Further, TDB has disbursed an amount of ₹ 47.80 crore towards on-going, new projects and other schemes. This included ₹ 47.57 crore as loan; ₹ 0.12 crore as grant and ₹ 0.11 crore to UTI/Other VCF/ITVUS for investment.

TDB also disbursed an amount of ₹ 3.51 crore against call for proposals "Fighting COVID-19" which include ₹ 2.12 crore as loan and ₹ 1.39 crore as grant.

Of the projects sanctioned earlier, 02 were declared completed and commercialized, one of which was by TATA Power Ltd SED for large scale manufacturing of Defence products with financial assistance of ₹ 109.00 crore from TDB at a total project cost of ₹ 385.00 crore. The second project was by SoftTech Engineers Limited for Development & commercialization of Rule Buddy as an e-Commerce portal to provide services for project feasibility and building permits with assistance of ₹ 245.00 lakh against the total project cost of ₹ 615.46 lakh.

This year has been a year of crisis that has caused considerable loss and presented challenges. But with every challenge comes an opportunity. TDB has been instrumental in encouraging indigenous innovations by supporting start-ups in up-scaling and commercializing their products promoting the goal of Atmanirbhar Bharat.

Dr. Neeraj Sharma

TDB's Mandate

- Provide Financial Assistance to industrial concerns and other agencies attempting commercial application of indigenous technology or adapting imported technology for wider domestic applications;
- Provide financial assistance to such research and development institutions engaged in developing indigenous technology or adaptation of imported technology for commercial application, as may be recognized by the central government;
- Perform such other functions as may be entrusted to it by the central Government

Sectors supported by TDB, since inception:

TDB being sector agnostic, has so far broadly supported the following sectors:



Composition of Technology Development Board

(As on 31st March, 2021)

Prof. Ashutosh Sharma Secretary, Department of Science & Technology	Ex-officio Chairperson
Dr. Shekhar C. Mande Secretary, Department of Scientific & Industrial Research	Ex-officio Member
Dr. G. Satheesh Reddy Secretary, Department of Defence Research & Development	Ex-officio Member
Dr. T. V. Somanathan Secretary, Department of Expenditure	Ex-officio Member
Dr. Guruprasad Mohapatra Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion	Ex-officio Member
Shri Nagendra Nath Sinha Secretary, Department of Rural Development	Ex-officio Member
Shri Pradeep Goyal Chairman, Pradeep Metals Ltd., Navi Mumbai	Member
Ms. Bineesha P. Executive Director International Institute of Waste Management, Bangalore	Member
Prof. Deshdeep Sahdev Mentor, Quazar Technologies Private Limited., New Delhi	Member
Shri Sabu M. Jacob Managing Director, Kitex Garments Ltd., Ernakulam, Kerala	Member
Dr. Neeraj Sharma Secretary, Technology Development Board	Ex-officio Member (Member Secretary)

Board Members

(As on 31st March, 2021)



Prof. Ashutosh Sharma
Chairperson, TDB & Secretary, DST



Dr. Shekhar C. Mande



Dr. G. Satheesh Reddy



Dr. T. V. Somanathan



Dr. Guruprasad Mohapatra



Sh. Nagendra Nath Sinha



Sh. Pradeep Goyal



Ms. Bineesha P.



Prof. Deshdeep Sahdev



Sh. Sabu M. Jacob



Dr. Neeraj Sharma

OVERVIEW

The image is a vertical graphic with a blue color palette. At the top, the word "OVERVIEW" is written in a bold, sans-serif font. The background consists of a grid of small, light blue squares. Overlaid on this grid are several curved, glowing lines that sweep across the frame. In the lower-left quadrant, there are three interlocking gears of varying sizes, rendered in a dark blue color. The overall aesthetic is clean, modern, and technical.

OVERVIEW

The Government of India constituted the Technology Development Board (TDB) on September 01, 1996 as per the provisions of the Technology Development Board Act, 1995 with an aim to promote development and commercialization of indigenous technology and adaptation of imported technology for wider domestic applications. TDB provides financial assistance to industrial concerns and other agencies attempting such development and commercial application.

The Act enabled the creation of a fund for Technology Development and Application to be administered by TDB. The said fund receives grants from the Government of India out of the R&D Cess collected by the Government from the industrial concerns under the provisions of the Research and Development Cess Act, 1986, as amended in 1995. The Act also enables TDB to build up the fund by crediting all sums received by TDB from any other source, recoveries made of the amounts granted from the fund, and any income from investment of the amount of the Fund. The Finance Act, 1999, enabled full deductions to donations to the Fund for income tax purposes.

In its General Budget 2017-18, the Central Government abolished 'Research and Development Cess Act, 1986' w.e.f. April 01, 2017. During the period of 1996-97 to 2016-17, the Government collected ₹7974.32 crore as R&D Cess.

TDB received a cumulative sum of ₹987.47 crore over the period of 25 years (1996-97 to 2020-21)

as Grant-in-Aid from the non-plan budget of the Department of Science & Technology, Government of India. In addition, TDB also received ₹75.00 crore in FY 2019-20 as separate Grant-in-Aid for specific purpose towards "Fighting COVID-19" call.

1.0 Modes of Financial Assistance

The financial assistance from TDB is available in the form of loan or equity and/or as a grant (in exceptional cases). Application for financial assistance is accepted throughout the year from Industrial concerns incorporated under the Companies Act, 1956/ 2013.

1.1 Loan

The financial assistance to the industrial concerns is provided as a soft loan at 5% simple rate of interest per annum. The limit of financial assistance in the form of Loan is 50% of the un-incurred project cost. The loan amount is disbursed in instalments as per the implementation of associated milestones in accordance with the terms and conditions as stipulated in the Loan Agreement. Royalty is payable on sales of products under TDB's project during the concurrency of loan.

In some cases, TDB may have nominee director(s) on the Board of Directors of the assisted industrial concern. The implementation period of a project should generally not exceed three years. The loan and interest is secured through collaterals and guarantees. Normally, the repayment of the loan and payment of interest commences after

the project is completed and a moratorium period not exceeding one year. The loan amount is generally recoverable in nine, half yearly instalments. The accumulated interest up to the repayment of the first instalment is distributed over a period of three years.

TDB does not collect administrative, processing or commitment charges from the applicants.

1.2 Equity

TDB contributes by way of equity capital in industrial concerns on its commencement, start-up and/or growth stages according to the requirements as assessed by TDB, keeping in view the debt-equity ratio. The equity subscription is decided by the full Board of the TDB. It is up to 25% of the approved project cost, provided such investment does not exceed the capital paid-up by the promoters.

TDB does not consider substituting the existing loan or equity of the industrial concerns which have obtained such finances from other institutions.

1.3 Grant

TDB also provides financial assistance by way of grants to industrial concerns and R&D institutions engaged in developing indigenous technologies. The sanction of grants is decided by the full Board and provided in exceptional cases having importance towards fulfilling national interest.

1.4 Financial contribution of TDB to industrial concerns (1996-2021)

1.4.1 The following table indicates the mode and financial contribution of TDB (since inception to March 31, 2021), this excludes details towards "Fighting COVID-19" call :

(Rs. in crore)

Instrument	*Sanctioned by TDB	Disbursement by TDB
Loan	1753.74	1553.72
Equity	33.06	35.67
Grant	157.13	150.50
Venture Funds	285.00	258.13
Total	2228.93	1998.02

* The actual sanctioned amount by TDB as on 31.03.2021 may vary due to conversion of loan into equity in some cases in the past and revision in quantum of financial assistance, foreclosure and cancellation.

Till FY 2019-20, the actual disbursement made by TDB was ₹ 1950.23 crore which include ₹ 1506.16 crore as loan, ₹ 150.38 crore as grant, ₹ 35.67 crore as equity, and ₹ 258.02 crore towards venture funds.

1.4.2: Financial contribution of TDB to industrial concerns towards "Fighting COVID-19" call

(Rs. in crore)

Instrument	Sanctioned by TDB	Disbursement by TDB
Loan	3.25	2.12
Grant	7.65	1.39
Total	10.90	3.51

2.0 Sectors

TDB is sector agnostic and has funded almost all sectors of Industries. Since inception, sector wise and state wise coverage is placed below:

2.1 Sector-wise Coverage (1996-2021)

TDB's financial assistance is available for all the sectors. Since inception in 1996 to

OVERVIEW

March 31, 2021, TDB has signed a total of 373 agreements with industrial concerns of discrete sectors, with a total project cost of

₹ 8488.56 crore and TDB's commitment of ₹ 2228.93 crore.

The following table gives sector-wise breakup of projects sanctioned by TDB upto March 31, 2021, since inception in 1996-97.

(Rs. in crore)

S. No.	Sector	Number of Agreements	Total cost	TDB's Commitment
1	Health & Medical	105	2083.47	612.92
2	Engineering	71	706.57	259.95
3	Information Technology	47	461.00	172.31
4	Chemical	26	236.80	84.69
5	Agriculture	27	217.48	69.85
6	Tele-communications	12	99.88	37.85
7	Road Transport	10	527.04	81.20
8	Energy & Waste Utilization	10	140.10	59.61
9	Electronics	4	52.56	17.75
10	Defence and Civil Aviation	10	648.83	229.95
12	Textile	1	689.00	250.00
13	Others			
	a) Venture Funds	11	2463.00	285.00
	b) STEP-TBI	35	35.00	35.00
	c) CII	1	0.83	0.50
	d) Millennium Alliance	1	112.00	25.00
	e) Global Innovation & Technology Alliance	1	15.00	7.35
	f) INVENT Programme	1		
	TOTAL	373	8488.56	2228.93

The support by TDB is largely market-driven and technology oriented in all its new ventures and various industrial sectors.

2.2 State-wise Coverage (1996-2021)

The State-wise distribution (based on registered office of the company) of agreements signed during the years 1996-2021 is given below:

(Rs. in crore)

S. No.	State, Union Territory	Number of Agreements	Total cost	TDB's Commitment
1	Assam	1	18.31	8.20
2	Andhra Pradesh/ Telangana	88	1719.36	557.08
3	Karnataka	49	1040.78	361.59
4	Maharashtra	51	1641.75	456.35
6	Tamil Nadu	38	321.87	101.56
7	Delhi	24	313.10	115.36
8	Gujarat	14	149.06	45.94
9	West Bengal	10	137.39	57.57
10	Uttar Pradesh	12	94.77	50.44
11	Madhya Pradesh	7	155.92	42.20
12	Haryana	7	47.57	19.48
13	Punjab	7	91.79	21.98
14	Chandigarh	4	43.75	16.50
15	Kerala	5	21.63	8.15
16	Himachal Pradesh	1	6.24	1.90
17	Jammu & Kashmir	1	5.65	2.38
18	Manipur	1	7.94	2.70
19	Pondicherry	1	5.83	1.90
20	Rajasthan	1	35.77	3.00
21	Odisha	1	4.25	1.80
22	Others - Including:			
	Venture Funds	11	2463.00	285.00
	STEP-TBIs	35	35.00	35.00
	CII	1	0.83	0.50
	Millennium Alliance	1	112.00	25.00
	Global Innovation & Technology Alliance	1	15.00	7.35
	INVENT Programme	1		
	Grand Total	373	8488.56	2228.93

3.0 Submission of the Project Proposal to TDB

An industrial concern seeking financial assistance from TDB is required to submit the application in the prescribed format. The format of the application for seeking financial assistance and other details are provided in 'Project Funding Guidelines' available on TDB's website (www.tdb.gov.in).

Industrial concerns may apply online, any time throughout the year via http://e-techcom.tdb.gov.in.

4.0 Processing of Project Proposals

Applications received are processed extensively by the Committee comprising domain Experts both on Technical and Financial side. A quick description of this extensive process is given below:

4.1 Evaluation Criteria

The application is evaluated for its scientific, technological, commercial and financial merits. The evaluation criteria include:

- Uniqueness and innovative content of the proposal;
- Soundness, scientific quality and technological merit;
- Potential for wide application and the benefits expected to accrue from commercialization;
- Adequacy of the proposed effort;
- Capability of the R&D institution(s) in the proposed action network;
- Organizational and commercial capability of the enterprise including its internal accruals;
- Reasonableness of the proposed cost and financing pattern;
- Measurable objectives, targets and milestones;
- Track record of the entrepreneur.

4.2 Confidentiality and Transparency

TDB understands that it is important to maintain confidentiality, as each proposal is a commercial proposal involving a new product or process. So the respective protocol is followed during the evaluation.

Also, in cases where the applicant mentions that some information provided in the project proposal has to be treated as strictly confidential, the Committee also respects the sensibility of the applicant's apprehensions in disclosing certain vital information of the processes.

4.3 Initial Screening of Application

A duly constituted Initial Screening Committee (ISC) preliminarily examines the applications received for financial assistance, from the view point of its completeness, objective of the project, status of the technology etc...

The committee composition involves Technical and Financial domain Experts from reputed National Institutions/Organizations. Applicants and/ or technology providers are given a chance to give a detailed presentation before the Committee which is further followed by a questionnaire, to have more clarity on the submitted project proposal.

As per the suggestion/ remarks of the Committee, if additional information/ details or further clarification is required for assessment, it is sought from the Company.

If the application does not meet the eligibility criteria prescribed for TDB's financial assistance, the ISC may not recommend the application for further processing after providing written reasons to the applicant.

4.4 Project Evaluation Committee (PEC)

Based on the recommendations of the ISC, the application is further referred to the Project Evaluation Committee (PEC) for more detailed assessment and evaluation including visit to the project site. For each project, a PEC is constituted keeping in view the nature of the project.

PEC consists of domain Experts (scientific & technical and financial) in the relevant fields from outside TDB for a fair and independent evaluation of the project. These experts (serving or retired) may belong to government departments, R&D organizations, academic institutions, industry, industry associations, financial institutions and commercial banks.

The applicant along with the technology provider (if any) is given a fair opportunity to give a detailed presentation before the said Committee, on the scientific, technical, marketing, commercial and financial aspects of the project, to provide in-depth information on various issues related to the project and the company.

4.5 Approval of Financial Assistance

The recommendations of the said PEC are further approved by the Chairperson, TDB. All the project proposals recommended by the PEC where TDB's assistance exceeds ₹ 10.00 crore, are processed for third party due-diligence.

The PEC inputs along with third party due-diligence reports are put up to the Board for their approval. Rest of the recommended cases are put up to the respective Competent Authority for their approval.

4.6 Monitoring and Review

TDB disburses the approved financial

assistance to the beneficiaries in instalments that are based on compliance of pre-defined milestones as per the mutually agreed Loan Agreement.

The project is monitored periodically by the Project Monitoring Committee. The PMC consists of scientific/ technical and financial experts.

5.0 Proactive Role

Besides responding to the applications received from industrial concerns and other agencies, TDB takes a pro-active role to ensure comprehensive support for technology development and commercialization.

Under the aegis of its mandate, TDB has encouraged development and commercialization of indigenous technologies through various initiatives. Some of them are as follows:

5.1 Participation in Venture Capital Funds (VCFs)

Technology Development Board (TDB) realized that many technological projects are unable to satisfy the traditional requirements of financial institutions and commercial banks. In addition to directly supporting indigenous technologies for commercialization, TDB felt the need for networking with other institutions to encourage technology focused Venture Capital Fund (VCF) to ensure that lack of adequate funds is not an obstacle for innovative and technologically viable projects.

TDB thus participated in Venture Capital Funds to provide support to early stage ventures through SMEs having innovation and innovative products / services. TDB's motivation and participation has resulted

in the venture capitalists contouring their assistance to TDB's mission. The Board also considered TDB's participation in VCFs as a tool for increasing geographical spread of the mandate of TDB to support technology companies especially in the MSME/SME category having innovation and innovative products / services.

The initiative of TDB has also given confidence to Venture Capitalist/Private Equity Funds to come up in a big way to support technology-based projects with a pronounced emphasis on sectors which are growth drivers of Indian economy.

5.2 Seed Support for Start-ups in Incubators

In 2005, TDB instituted the Seed Support Scheme to provide early stage/start-up financial assistance to young entrepreneurs with innovative technology venture ideas to incubate and bring their ideas under development to fruition and finally to reach the market place. The proposed assistance was positioned to act as a bridge between development & commercialization of the technologies. The scheme was started for providing financial assistance to startups incubated in Science & Technology Entrepreneur Park /Technology Business Incubators (STEP/TBI) administered by the National Science & Technology Entrepreneurship Development Board (NSTEDB) of DST.

Till March 31, 2018, TDB has supported 35 TBIs and STEPs (including two times financial assistance to 4 TBIs/STEPS) with a financial assistance of ₹ 1.00 crore each aggregating to ₹ 35.00 crore.

These incubators have provided assistance to several incubatees for their project to spread in the areas of Telecom, IT, Robotics,

Agriculture, Instrumentation, Engineering, Environment, Pharma, Food, Solar, Textile and Biotechnology. The scheme progressed well and benefited a number of entrepreneurs in up-scaling and related work. It also facilitated in building up a corpus of incubation fund by the incubators.

5.3. International Collaboration

5.3.1 MoU with Bpifrance

TDB continues its technical collaboration with Bpifrance erstwhile, OSEO, France as per renewed Memorandum of Understanding (MoU) between TDB and Bpifrance along with CEFIPRA as the managing partner. The agreement was signed in 2016 and is valid for a period of 5 years.

The agreement entails to carry out activities related to the exchange of best practices and setting up of coordinated measures to foster technological exchanges in the field of Science, Technology and Innovation through collaboration between companies, organizations and institutions of France & India. This program aims to fund proposals on Aeronautics, Automotive & Biotechnology areas.

5.3.2 MoU with Department for International Development (DFID), UK

TDB in partnership with Department for International Development (DFID), UK initiated the Innovative Ventures and Technologies for Development (INVENT) Programme in the FY 2015-16. The program was designed to create a platform to support inclusive innovation solutions, both technological and process oriented, that have a positive social and economic impact on people in the lower income segments, also known as the Bottom of the Pyramid (BoP). The support

included, but not be limited to the provision of funding, intense mentoring, knowledge and access to capacity building programmes, support services, and relevant networks in the 8 Low Income States (LIS) of India (UP, MP, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Rajasthan, Orissa and West Bengal).

The ultimate aim was to create the viable social enterprises pipeline for impact investment in the above mentioned 8 LIS; Generate 50 investments ready for profit social enterprises in 8 Low Income States; Support 160 entrepreneurs in these 8 Low Income States.

An Agreement was executed between TDB and M/s Villgro Innovations Foundation (VIF) in FY 2015-16 wherein Villgro was selected to act as the lead incubator to provide incubation support aimed at creating a viable social enterprise (for profit) pipeline for impact investments in the 8 LIS of India. VIF supported four incubators viz. IIM Calcutta Innovation Park (IIMCIP), KIIT Technology Business Incubator at Bhubaneswar (KIIT TBI), SIDBI Innovation & Incubation Centre at IIT Kanpur (SIIC IITK) and Startup Oasis (an initiative of CIIE, IIM Ahmedabad and RIICO) in the LIS to hand-hold innovative businesses at seed or early stages of enterprise development that benefited the bottom of pyramid in the LIS of India while being commercially successful.

5.4 National Collaborations:

5.4.1. MoU with World Wide Fund for Nature (WWF)-India for Climate Solver Partner

Considering India's strength in innovation wherein it has been ranked 12th on the Global CleanTech Innovation Index 2012, TDB decided to join the Climate Solver Platform launched by WWF-India on 21st May, 2012.

In India, besides TDB, the Confederation of Indian Industry (CII), New Ventures India, Centre for Innovation Incubation & Entrepreneurship (IIM Ahmedabad) and Sky quest Technology Consulting Private Limited. Participated in this programme.

5.4.2. MoU with Technology Information Forecasting and Assessment Council (TIFAC)

TDB and Technology Information Forecasting and Assessment Council (TIFAC) an autonomous body under DST signed an MoU on "Transformational Technological Innovation" on 10th February, 2018 with an aim to scout for innovative technologies, commercialize indigenous technologies and invest in companies commercializing such technologies. The areas and scope of cooperation include:

- Scouting of emerging (core thrust) technologies/ technological areas with investment trends and the forces driving those;
- Identifying technologies which have the ability to transform social and economic environment as well as generate employment for the growing youth of the nation on immediate, medium-term and long-term basis;
- Developing policy frameworks for easy adoption of technology; up scaling and manufacturing leading to its commercialization in the nation for the identified domains.

5.4.3. MoU with Innovative Change Collaborative (ICCo)

TDB and Innovative Change Collaborative (ICCo) India organisation, a development organisation working in India signed an

MoU on “Transformational Agricultural Technology Business Solutions” on 6th March, 2018 with an aim to scout for innovative agricultural technologies, commercialize indigenous technologies and invest in companies which will exhibit the potential to double farmers’ income. The areas and scope of cooperation include:

- Scouting of relevant agriculture technology business solutions in pre-harvest domain, allied agriculture, post-harvest domain;
- Identifying technologies and business solutions which demonstrate the ability to transform rural economic environment as well as generate employment for rural youth of the nation on immediate, medium-term and long-term basis.
- Assessing the ability of interested agri-tech businesses in the identified domains to truly improve farmers’ income level by evaluating their technology readiness and business model for commercial and financial viability.

5.4.4. MoU with PHD Chambers of Commerce and Industry (PHDCCI)

TDB and PHD Chambers of Commerce and Industry (PHDCCI) signed MoU on 25th April, 2018 to scout for emerging technologies/ technological areas of National Importance such as Agribusiness and Food Processing, Healthcare and Pharmaceuticals, Electric Mobility, Water and Waste to Energy, Automobiles, etc. And identify factors driving those; also to develop policy frameworks for easy adoption of technology, upscaling and manufacturing leading to its commercialization. Both the organizations are collaborating in identifying industries with technology-driven projects which may have social and economic implications

and generate employment on immediate, medium-term and long-term basis.

5.4.5. MoU with Associated Chambers of Commerce & Industry of India (ASSOCHAM)

TDB and the Associated Chambers of Commerce & Industry of India (ASSOCHAM) signed an MoU on 3rd May, 2018 to scout for emerging technologies/ technological areas of national importance such as Pharmaceuticals, Medical Devices & Diagnostics, Agriculture, Food Processing, Defense & Aerospace, Electric Mobility and Automobiles; and identify factors driving those; also to develop policy frameworks for easy adoption of technology, upscaling and manufacturing leading to its commercialization. Both the organizations are working in close association through seminar, symposia and project-writing workshops to identify companies with prototypes technologies/technology-driven projects with commercial outcome on immediate, medium-term and long-term basis

5.4.6. MoU with Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC)

For bringing synergy between various industry supporting organizations for “Commercialization of Indigenously Developed Technologies”, a MoU was signed between Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC) and Technology Development Board (TDB) on 7th September, 2018 for creating and fostering a global and national ecosystem for Biomedical/ Biotechnological Innovations, Translation and Commercialization in a seamless manner.

The area and scope of co-operation include :

- BIRAC and TDB shall enable joint inter-organizational mechanism for concerted

efforts to meet the innovation and commercialization gap.

- Mutually agree upon the Biotechnology projects that can fall within the respective organizational scope for seamless evaluation and funding assistance considerations by establishment of a coactive governance structure.
- The Parties shall create a synergy to benefit from their respective organizational strength to mobilize effective funding and subtend technology readiness gap.
- The projects for cross reference will be decided on mutual understanding with respect to operative period of MoU; financial obligations and extent of cooperation.
- The Parties through this MoU have jointly agreed to share knowledge base, in-house processes and project inputs in furtherance to attainment of the united initiative.

5.5. Alliances

5.5.1 Global Innovation & Technology Alliance (GITA)

As an outcome of the Prime Minister's Council on Trade & Industry, to support acceleration of India's industrial R&D efforts, The Global Innovation & Technology Alliance (GITA) was set up in 2011, as a PPP JV between the Confederation of Indian Industry (CII) and the Technology Development Board, Department of Science & Technology (DST), Government of India.

GITA is an innovative platform that maps technology gaps, evaluates technologies available across the globe and forges techno-strategic collaborative partnerships appropriate for the Indian economy. GITA connects industrial and institutional partners

for effective matchmaking and collaborative industrial R&D projects, facilitating funding for technology development/ acquisition/ customization / deployment.

Over the years, GITA has been successfully managing various national and bilateral Industrial R&D and technology acquisition projects under the partnership of various Government of India Ministries and Departments, such as the Department of Science & Technology (DST), Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY), the Department of Heavy Industry (DHI), the Defence Research & Development Organisation (DRDO), the Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) and the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MoMSME). GITA has also collaborated with multilateral bodies such as the European Commission for enhancing the innovation ecosystem.

Interventions have focused on sectors of national relevance to India's technological aspirations e.g., Affordable Healthcare, Clean Technologies including Energy and Transportation, Advanced Manufacturing, Capital Goods Sector, Defence& Aerospace, Information & Communication Technology (ICT), Electronic System Design & Manufacturing (ESDM), Water Technologies (including Water Purification, Desalination, Irrigation Technologies, Waste Water Treatment and Management) etc.

GITA also broadened and formalised its engagement with the Indian innovation ecosystem with the GITA Innovation Exchange (GIXC). The GIXC is a unique, virtual platform that endeavours to create credible connections for technological partnerships, technologies, IP services and finance for innovation, for actors across the innovation spectrum.

5.5.2 Millennium Alliance (MA)

The Millennium Alliance (MA) Program was launched in 2011 jointly by TDB, United States Agency for International Development (USAID) and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) as a platform to identify, test, and scale innovations which bring improvements at the Bottom of the Pyramid (BoP) level. This alliance was forged as an innovation partnership for global development focusing on important sectors including health, basic education, water & sanitation, food security/agriculture and clean energy to ensure that the benefits of innovation percolate to the BoP population. Later, the platform was joined by UK's DFID, ICCO Cooperation, ICICI Foundation for Inclusive Growth, World Bank Group and Facebook.

Each MA partner brought along financial and knowledge based resources with an end aim of supporting social enterprises that could bring about transformational change. The MA was an inclusive platform to leverage Indian creativity, expertise, and resources to identify and scale innovative solutions being developed and tested in India to address development challenges that benefited BoP populations across India and the world. The MA was a network to bring together various social innovators, philanthropy organizations, social venture capitalists, angel investors, donors, service providers and corporate foundations to stimulate and facilitate financial and other support to the innovators.

A USD 25 million fund was setup for a period of 5 years of which contributed ₹ 25.00 crore (₹ 5.00 crore per year). Under The Program, innovators were provided with seed funding, grants, incubation, networking opportunities, business support, knowledge exchange and technical assistance which facilitates further access to equity, debt, and other capital.

The program completed its 5 rounds in the year 2018-19. Through these rounds, the program directly supported 124 innovative projects with a funding support of ₹ 86.7 crore. These projects have touched millions of lives, increasing farmer incomes, providing them access to early grade education, clean drinking water, energy for their homes, affordable & digital healthcare and sanitation facilities.

The supported enterprises were able to leverage the grant given as a catalytic fund to raise external funds as well as develop partnerships for extensive and sustainable project implementation. The projects funded by MA were implemented in 21 states in India. The funds also supported interventions in 11 countries. MA is the only program of its kind to support 22 Indian companies replicate and scale their innovations in Africa (Kenya, Rwanda, Uganda, Ethiopia, Burkina Faso and Malawi) and South Asia (Afghanistan, Bangladesh, Srilanka and Nepal).

The program has played a significant role in entrepreneurship development in the social sector across the globe.

5.6 Technology Day and Presentation of National Awards

5.6.1 Technology Day

Every year National Technology Day is observed across India on May 11. National Technology Day is being commemorated to celebrate the anniversary of first of the five tests of Operation Shakti (Pokhran-II) nuclear test which was held on May 11, 1998 in Pokhran, Rajasthan.

On this day first indigenous aircraft Hansa-3 was test flown at Bangalore and India also conducted successful test firing of the Trishul

missile on the same day. Considering all these achievements May 11 was chosen to be commemorated as National Technology Day.

This day emphasizes the importance of science in day-to-day life and motivates students to adopt science as a career option.

This day urged the industry to build powerful partnerships with the national laboratories and to create knowledge networks with academic institutions for promoting research and development and gaining entry into global markets.

5.6.2 National Award

To commemorate National Technology Day and to encourage the techpreneurs, TDB had instituted National Award. This award is conferred to various industries for successful commercialization of innovative Indigenous Technology.

The Award was given for the very first time on the occasion of the National Technology Day falling on May 11, 1999. M/s Shantha Biotechnics Private Limited, Hyderabad was the first recipient of this award for commercial production of "Recombinant DNA based Hepatitis – B vaccine" disseminated by the then Hon'ble Prime Minister of India, Shri Atal Bihari Vajpayee.

The award carried a cash prize of ₹ 10.00 Lakh and a trophy. In case a technology has been developed and commercialized by separate entities, both are eligible to get the award separately. In 2016, the quantum of the award was increased to ₹ 25.00 lakh.

In August 2000, TDB introduced a cash award of ₹ 2.00 Lakh and a trophy to a Small Sector Industry (SSI) unit that has successfully commercialized a technology-based product.

The first SSI award was given on May 11, 2001. The number and quantum of the award was increased to three and ₹ 5.00 lakh, respectively in the year 2011.

In 2016, this award was renamed as 'MSME Award' and the quantum was increased to ₹ 15.00 Lakh.

During the year 2017-18, TDB introduced a new category of award worth ₹ 15.00 Lakh and a trophy for Start-ups for promising new technology with potential for commercialization.

From 11th May, 2017 onwards, following three categories of awards are given as a part of the Technology Day Celebration:

- *National Award for Successful Commercialization of Indigenous Technology (01*)* – Cash award worth ₹ 25.00 Lakh and a trophy to an industrial concern towards successful development & commercialization of an indigenous technology; in case the technology developer and commercializing organizations are different, each one is eligible for cash prize and trophy;
- *National Award under MSME category for successful commercialization of a technology-based product (03*)* – Cash award worth ₹ 15.00 lakh and a trophy to a MSME that has successfully commercialized product based on indigenous technology;
- *National Award under Start-up Category(01*)* – Cash award worth ₹ 15.00 Lakh and a trophy for promising new technology with potential for commercialization.

* The Selection Committee for National Awards may change the number of awards to be given or may differ if the entries are not found suitable.

5.7 Issuance of “Call for Proposals”

The Board takes a pro-active approach and from time to time issues “Call for Proposal” in different areas of importance in order to familiarise local industry towards the intent of TDB support innovation –driven technology focused projects in various strategic areas as per the policies and the initiatives by Government of India like “Make in India”, “Startup India” and “Atmanirbhar Bharat” etc..

5.8 Dispute Resolution Committee (DRC)

Since inception of TDB, many cases have been declared stressed either due to technology failure or commercialization failure. Owing to these NPAs/Stressed cases, pre-litigation and litigation cases, the Board initiated a mechanism for addressing such cases by constituting a “Dispute Resolution Committee (DRC)” in late 2015.

The objective of DRC is to provide companies a platform to resolve issues related to payment of TDB dues. However, DRC nowhere interferes with the legal proceedings already initiated by TDB. The recommendations of DRC are placed before the Board, for approval. Through this process, issues with many companies have been resolved and recoveries made.

5.9 Online Submission of Project Proposals

Since 2017-18, TDB is practicing digitalized and paperless submission of the application submission process, a way forward towards “Digital India”. This initiative brought more transparency and efficiency in working procedures. “Online Submission of Project Proposals” is done via “Project Management System (PMS)” @<http://www.e-techcom.tdb.gov.in/>.

5.10 Exhibitions/Seminars

To create awareness in the industry, entrepreneurs and R&D institutions about the available financial support from TDB, various activities were undertaken such as interactive meetings/participation in exhibitions in collaboration with other organizations.

5.11 Creation of Social Media Platform

In order to get transparency in functioning, getting broader connectivity and also considering the importance of Social Media platforms in present scenario, TDB felt the need to have its own Social Media platforms and created its official pages as follows:

Facebook: www.facebook.com/tdbgoi

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/technology-development-board/>

Twitter: <https://twitter.com/tdbgoi>

Instagram: www.instagram.com/technologydevelopmentboard/



**Year at a
Glance**

YEAR AT A GLANCE

In the FY 2020-21, TDB entered into thirteen agreements to provide financial assistance to various industrial concerns. Through these agreements, TDB has committed ₹ 23.74 crore as a Loan and ₹ 7.30 crore as a Grant out of total project cost of ₹ 80.92 crore, covering various sectors.

1.0 Applications Received in 2020-21

During the FY 2020-21, TDB received 29

applications via regular mode and 235 applications were received via call for proposal "Fighting COVID-19". This call was announced on March 23, 2020 where TDB invited proposals/applications from Indian companies and enterprises. Out of these 235 applications, 114 applications were found in order as per TDB's Funding Guidelines. So this year a total 143 applications were processed by TDB.

1.1 Sector wise breakup:

Sector wise distribution of these 143 applications is as under:

(Rs.in crore)

S. No	Sectors	Number of Applications	Estimated Total Cost	Assistance sought from TDB
1	Health & Medical	80	1349.67	599.60
2	Engineering	4	141.48	63.06
3	Information Technology	42	254.08	108.21
4	Chemical	1	21.25	10.00
5	Agriculture	3	75.13	10.87
6	Tele-Communication	1	19.79	3.10
7	Road Transport	2	27.40	12.45
8	Energy - and Waste Utilization	2	16.46	6.73
9	Electronics	8	111.40	43.80
	Total	143	2016.66	857.81

1.2. State wise breakup:

State wise distribution of these 143 applications is as under:

(Rs.in crore)

S. No	States	Number of Applications	Estimated Total Cost	Assistance sought from TDB
1	Karnataka	40	267.65	129.55
2	New Delhi	22	177.27	76.57

3	Andhra Pradesh/Telangana	14	349.99	150.03
4	Haryana	3	201.35	55.00
5	Maharashtra	26	562.27	251.10
6	Gujarat	1	7.10	1.00
7	Tamil Nadu	11	99.99	33.34
8	Uttar Pradesh	10	159.63	69.97
9	Orissa	2	0.77	0.32
10	Manipur	0	0.00	0.00
11	Bihar	1	1.18	0.52
12	Jharkhand	1	0.15	0.15
13	Punjab	2	70.43	10.10
14	West Bengal	5	12.03	5.89
15	Goa	1	100.00	70.00
16	Kerala	1	0.80	0.35
17	Madhya Pradesh	1	1.33	1.33
18	Rajasthan	2	4.71	2.60
Total		143	2016.66	857.81

2.0 Agreements Signed during FY 2020-21

This year TDB signed thirteen agreements with various industrial concerns. Details are as follows:

S.No	Name of the Company	Name of the Project	Sector
1	M/s Mylab Discovery Solutions Private Limited, Pune	Manufacturing of Testing Kits to detect Covid Corona Virus	Health & Medical
2	M/s Thincr Technologies India Private Limited, Pune	Development of low cost and more efficient masks coated with antiviral agents to protect spread and protection of Covid19 and other viral infections	Health & Medical
3	M/s Medzome Life Sciences Private Limited, New Delhi	Development and commercialization of fluorescence-based Rapid COVID-19 Detection Kit	Health & Medical
4	M/s QuNu Labs Private Limited., Bangalore	Commercialization of QuNu's Quantum Technology Security Products	Information Technology
5	M/s Advance Mechanical Services Private Limited, Bangalore	Industrial IOT enabled IR Thermography-based Temperature Scanner	Engineering

6	M/s Cocoslabs Innovative Solutions Private Limited, Bangalore	Advanced video analytics for low-cost thermal cameras to identify persons with abnormal body temperature in public places	Engineering
7	M/s Evobi Automations Private Limited, Bangalore	Portable Ultra-Violet based Box Sterilizer & Modular Movable Ultra-Violet based Indoor Room Sterilizer	Health & Medical
8	M/s Nanoclean Global Private Limited, New Delhi	Nanomask Semi-Automatic N95 production Machine	Health & Medical
9	M/s inDNA life Sciences Private Limited, Bhubhneshwar	inPhilia-Solutions for parenthood comprehensive genetic screening for optimize parenting	Health & Medical
10	M/s Salcit Technologies Private Limited, Hyderabad	kAs, a screening and monitoring tool for COVID 19	Information Technology
11	M/s Iatome Electric (I) Private Limited, Coimbatore	Battery Powered Compact Digital Portable X-ray Machine	Health & Medical
12	M/s Briota Technologies Private Limited, Pune	Covid-19 Monitoring and Management solution for Affected, Quarantined or Co-Morbidity High Risk Patients to avoid or delay Lung Complications in order to reduce Case Fatality Rate (CFR)	Health & Medical
13	M/s RCC Laboratories India Private Limited, Hyderabad	Establishment of Specific Pathogen Free (SPF) Laboratories Animal Breeding and Testing Facility	Health & Medical

3.0 Disbursement

TDB had disbursed an amount of ₹ 47.80 crore towards on-going, new projects and other schemes in FY 2020-21. This included ₹ 47.57 crore as loan; ₹ 0.12 crore as grant and ₹ 0.11 crore to UTI/other VCF/ITVUS for investment.

TDB has disbursed an amount of ₹ 3.51 crore against call for proposals "Fighting COVID-19", this include ₹ 2.12 crore as loan and ₹ 1.39 crore as grant.

4.0 Projects Completed

The following companies supported by TDB declared their project completed during the FY 2020-21:

S.No	Name of the Company	Name of the Project	Sector
1	M/s TATA Power Company Limited, Bangalore	Setting up Defence Manufacturing Facility at 50 acres Land at Vemagal Industrial Area, Kolar District, Karnataka	Defence & Civil Aviation
2	M/s. SoftTech Engineers Limited, Pune	Development and commercialization of Rule Buddy products (erstwhile "ArchiTx")	Information Technology

5.0 Settlement / Repayment of Loan

During the year, following companies financed by TDB repaid their loan / settled their loan account:

S. No	Company name	Project titled
1	M/s Basic Healthcare Products Private Limited, Chandigarh	Commercialization of Indigenous Bone Grafting technology
2	M/s i2i Telesolutions & Telemedicine Private Limited, Bangalore	Development & Commercialization of technologies for a TelePACSTM based Healthcare Exchange for internet and mobile based Healthcare access
3	M/s Sickle Innovations Private Limited, Ahmedabad	Grading and sorting machine for fruit and vegetables
4	M/s Siechem Technologies Private Limited, Chennai	Development and commercialization of (i) High temperature resistant Hybrid EBXL power cables; (ii) High heat & fire resistant EBXL cable which is rodent, termite, insect resistant for use in High rise buildings, running trains and marine applications; and (iii) White colour Synthetic coated, Electron Beam Cured leather for making cricket balls
5	M/s Ind-swift Laboratories Limited, Chandigarh	Setting up a project for Commercialization of APIs". The company proposed to manufacture APIs namely: Quetiapine, Fumarate, Ropinirole HCl, Aripiprazole, ClopidogrelBesylate, Risedronate Sodium, Venlafaxine HCl, Donepezil, Nateglinide and Fluvastatin Sodium

6.0 Technology Day

The following winners have been awarded with the National Award-2020 under following three categories:

Award Category	Awardees (Company Name)
National Award for successful commercialization of Indigenous technology	<ul style="list-style-type: none"> • M/s L&T Special Steels And Heavy Forgings, Surat, Gujarat (Technology Provider – Nuclear Power Corporation of India Limited, Mumbai, Maharashtra) for - "Indigenous Technology Development of Low Alloy Steel Heavy Forgings For 700 MW Nuclear Power Plant Steam Generators" • M/s Vinati Organics Limited., Mumbai, Maharashtra (Technology Provider – CSIR-Indian Institute of Chemical Technology., Hyderabad, Telangana) for - "p-TertButyltoluene & p-TertButylbenzoic acid (from Lab to Pilot to commercial scale)".

<p>National Awards under MSME category for successful commercialization of a technology-based product</p>	<ul style="list-style-type: none"> • M/s AKS Information Technology Services Private Limited, Delhi for- 1. AKS Forensic Workstation; 2. Web Application Firewall 3.Anti-DDOS Solution; 3. Anti-DDOS Solution. • M/s SVP Laser Technologies Private Limited, Chennai, Tamil Nadu, for- “Multi CNC Large Scale Foam Rapid Prototyping machine (LSFRP) with indigenously developed MultiCNC controller &AutoCAM2D software” • M/s KanBiosys Private Limited, Pune, Maharashtra, for- “Speed Kompost TM for In-situ Accelerated and Sustainable Rice Straw Decomposition [ASRSD]” • M/s AlgalR Nutra Pharms Private Limited, Thanjavur, Tamil Nadu, for- “Veg-an Omega-3 (Algal Dha Oil, Algal Dha Powder), Omega3-animal feeds”
<p>National Awards under Start-up Category</p>	<ul style="list-style-type: none"> • M/s RAR Engineering Private Limited, Delhi for – “Indigenous Active Recoil Buffer System and Vibration Control Equipments for Defence, Aerospace and Civil Applications” • M/s Fibroheal Woundcare Private Limited, Bangalore, Karnataka for- “Fibroheal –Silk protein derived wound dressing” • M/s Althion Tech Innovations Private Limited, Hyderabad, Telangana for- “Novel RO membrane and process for ultra-pure water” • M/s KBCols Sciences Private Limited, Pune, Maharashtra for- “Natural and safe Colors from renewable resources as an alternative to harmful chemical colors used in all industries (eg: Textiles, Foods, cosmetics)” • M/s ShiraMedTech Private Limited, Ahmedabad, Gujarat, for- “Shira Clamps” • M/s Newndra Innovations Private Limited, Jaipur, Rajasthan for- “Jaipur Belt: Efficient, affordable, un-powered and lightweight exoskeleton for spine and waist problems.”

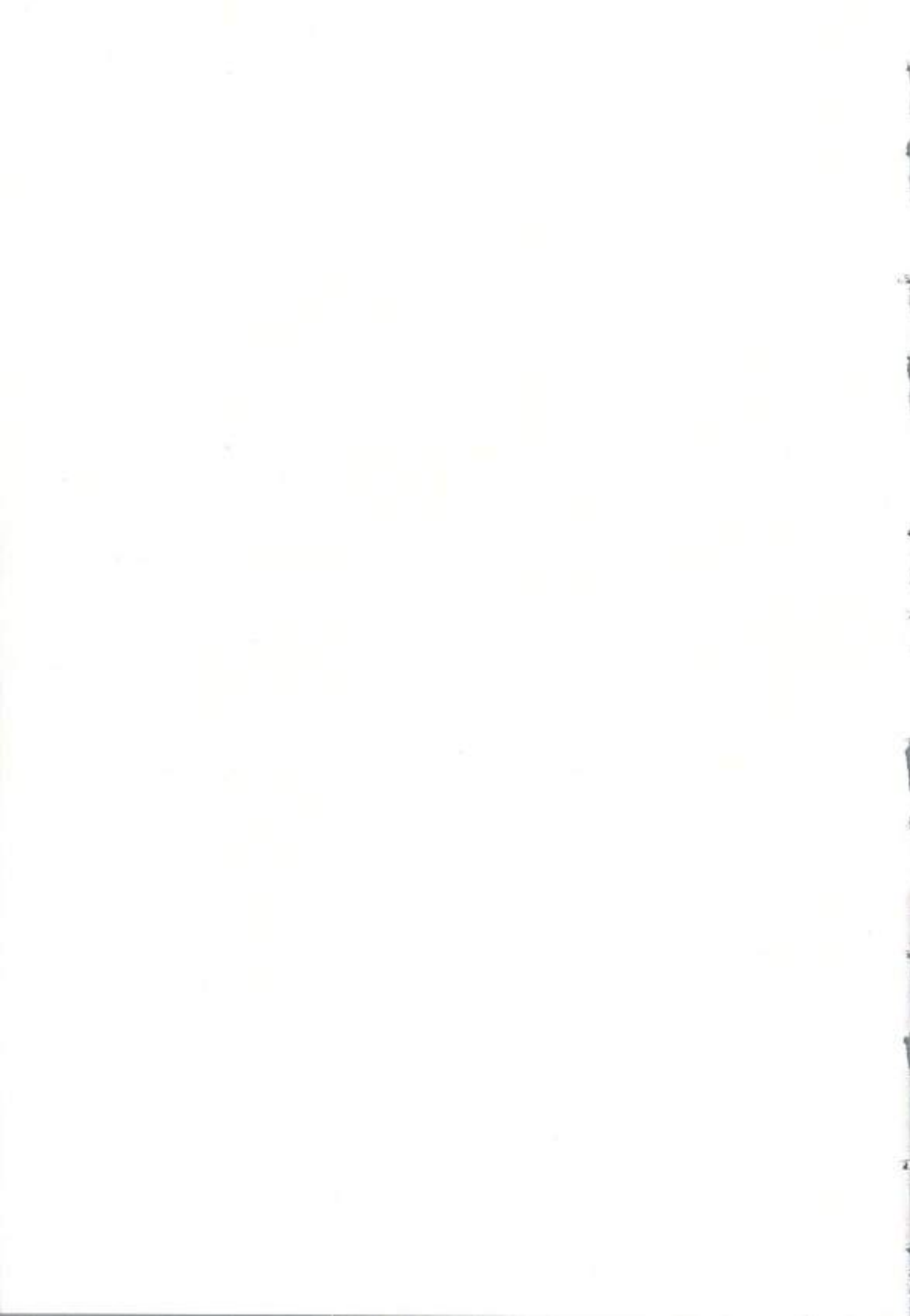
7.0 Participation in Venture Capital Funds (VCFs)

TDB has so far (till March 31, 2021) participated in 11 Venture Capital Funds, along with other investors, with total commitment of ₹ 285.00 crore, leveraging total funds aggregating to ₹ 2281.77 crore. (as submitted by Investment manager) from other investors. TDB has disbursed ₹ 258.13 crore towards its committed disbursement and has received an amount of ₹ 225.55 crore from the exit proceeds of these funds. TDB's funds have been invested in close to 209 companies, through participation in these VCF's

This year ₹ 15.88 crore was received towards redemption. Details are placed in table below:

(Rs. in crore)

S.No	Fund Name	Investment Manager	Total Fund size	TDB Commitment	Receipts during FY 2020-21 towards redemption
01	Biotechnology Venture Fund (BVF)	APIC Venture Capital Ltd, Hyderabad	155.00	30.00	0.396
02	SME Technology Venture Fund	Gujarat Venture Finance Ltd (GVFL), Ahmadabad	89.32	15.00	-
03	Ivycap ventures Trust Fund I	Ivycap ventures Advisors Pvt Ltd, Mumbai	238.20	25.00	1.57
04	Multi Sector Seed Capital Fund	Blume Ventures Advisors Pvt Ltd, Mumbai	100.00	25.00	9.61
05	SME Tech Fund RVCF II	Rajasthan Asset Management Company Pvt Ltd, Rajasthan	150.00	15.00	1.18
06	SEAF India Agribusiness Fund	SEAF India Investment Advisors Pvt Ltd, Mumbai	106.25	25.00	0.11
07	India opportunities Fund (IOF)	SIDBI Venture Capital Ltd, Fund	421.30	25.00	2.25
08	Ventureast Tenet Fund II	Ventureast Fund Advisors (India) Pvt Ltd, Chennai	54.45	15.00	-
09	Indian Fund for sustainable Energy	CII, IIM Ahmadabad	125.00	10.00	0.77
Total					15.88





**Agreement
Signed**



Manufacturing of Testing Kits to detect Covid Corona Virus



M/s Mylab Discovery Solutions Private Limited, Pune

SECTOR: Health & Medical

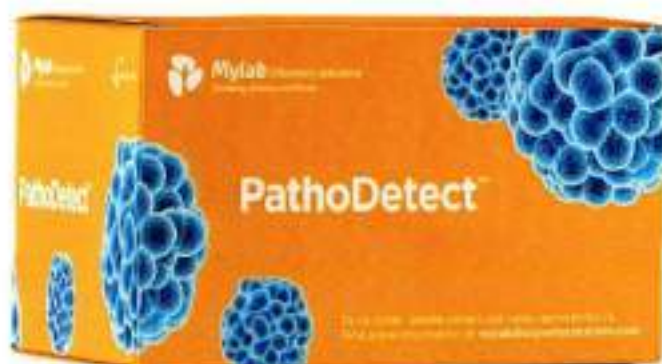
Technology Development Board (TDB) has entered into an agreement on 22.05.2020 with M/s Mylab Discovery Solutions Private Limited, Pune for implementation of their project titled "Manufacturing of Testing Kits to detect Covid Corona Virus" for financial assistance of ₹ 400.00 lakh against the total project cost of ₹ 1360.00 lakh.

About The Company

M/s Mylab Discovery Private Limited, Pune was the first indigenous company to have developed a real-time PCR-based molecular diagnostic kit that screens and detects samples of people who display flu-like symptoms. The kit was developed, approved by ICMR and CDSCO, and deployed in a very short time. Further, the company has developed a highly sensitive antigen kit reaching more than 2 crore Indians in remote areas who did not have access to RT-PCR testing as well as Compact XL to automate RT-PCR testing and resolve delays and errors in diagnostics.

About the Project and Product

The objective of the Project is to develop a setup for manufacturing 4000 kits a day (4 lakh tests a day) by bringing in the automation machines in the process. The company with this project will be able to produce and fulfil the increasing demand for COVID-19 testing. The availability of these kits will also help the country to increase the number of tests that can be conducted on daily basis.



RT-PCR testing Kit by M/s Mylab Discovery Private Limited., Pune

Financial Assistance:

₹ **400.00** lakh

Project cost:

₹ **1360.00** lakh

Development of low cost and more efficient masks coated with antiviral agents to protect spread and protection of Covid 19 and other viral infections



M/s Thincr Technologies India Private Limited, Pune

SECTOR: Health & Medical

Technology Development Board (TDB) has entered into an agreement on 03.07.2020 with M/s Thincr Technologies India Private Limited, Pune for implementation of their project titled "Development of low cost and more efficient masks coated with antiviral agents to protect spread and protection of Covid 19 and other viral infections" for financial assistance of ₹ 7.50 lakh against the total project cost of ₹ 27.40 lakh.

About The Company

M/s Thincr Technologies India Private Limited, Pune is working on various new innovative products such as Home Automation system, 3D-Printers, Automatic Dispenser, Automatic Elevated Plus Maze system. Company has built innovative FDM type 3D printers. Their core objective of working on their 3D-Thincr project is to develop 3D printers for pharmaceutical applications and to develop new 3D printed pharmaceutical formulations. They worked on 3D printing filaments of some of the medications (e.g. Amlodipine, telmisartan and Dextromethorphan) and its 3D printed formulations.

About the Project and Product

The project submitted to TDB was for the 3D printing of anti-viral agents on the masks as a preventive measure against COVID-19. Sodium Olefin Sulfonate based mixture which is widely used in cosmetics is formulated as a coating on the mask. Sodium olefin sulfonate which is a soap forming agent has hydrophilic and hydrophobic properties when come in contact with enveloped viruses, it disrupts the outer membrane of the latter.

The company could successfully establish the setup and the chemical formulation and started the production of antiviral coated mask in the month of February 2021.

In addition, the company will collaborate to focus on developing different types of virucidal coating formulations. These formulations can be incorporated as an additional layer in N-95 masks, 3-Ply masks, simple cloth masks through 3D printing technology and can be an added protection beyond the normal masks. The company is further exploring the possibility of using Fused Deposition Modeling (FDM) 3D printers for new pharmaceutical formulations and drug-loaded filaments of different types.



Thincr- Virucidal coated masks by M/s Thincr Technologies India Private Limited, Pune

Financial Assistance:

₹ **7.50** lakh

Project cost:

₹ **27.40** lakh

Development and commercialization of fluorescence-based Rapid COVID-19 Detection Kit



M/s Medzome Life Sciencez Private Limited, New Delhi

SECTOR: Health & Medical

Technology Development Board (TDB) has entered into an agreement on 09.07.2020 with M/s Medzome Life Sciencez Private Limited, New Delhi for implementation of their project title "Development and commercialization of fluorescence-based Rapid COVID-19 Detection Kit" for Grant assistance of ₹ 47.50 lakh against the total project cost of ₹ 100.00 lakh.

About The Company

M/s Medzome Life Sciencez Pvt Ltd, New Delhi is a manufacturing unit for rapid diagnostic devices based on lateral flow immunoassay. The Company is registered at New Delhi and the project implementation site is at Baddi, HP. They are already in the market with their diagnostic kits for Malaria, Dengue, Chikungunya, Typhoid and Syphilis among others. The mission of the Company is to manufacture high quality, cost-effective, technologically advanced diagnostic test kits.

About the Project and Product

The Company will develop a fluorescence based rapid COVID-19 Detection Kit based on a lateral flow chromatographic immunoassay. The routinely used antibody-based lateral flow Immuno chromatography test is visualized by colloidal gold-nano particles. To make the test more sensitive, the Company will be using fluorescence tags. The detecting antigen will be labelled with fluorescent dye and the fluorescence reader will be used to detect the dye. The antibody test can be used for the rapid screening of COVID-19 carriers, symptomatic or asymptomatic, in hospitals, clinics, and test laboratories. This test does not require well-established laboratory facilities or technical persons and therefore is expected to be cost effective.



Fluorescence Reader by M/s Medzome Life Sciencez Pvt Ltd., New Delhi

Financial Assistance:

₹ **47.50** lakh

Project cost:

₹ **100.00** lakh

Commercialization of QuNu's Quantum Technology Security Products



M/s QuNu Labs Private Limited, Bangalore

SECTOR: Information Technology

Technology Development Board (TDB) has entered into an agreement on 28.08.2020 with M/s QuNu Labs Private Limited, Bangalore for implementation of their project title "Commercialization of QuNu's Quantum Technology Security Products" for Loan assistance of ₹ 280.00 lakh against the total project cost of ₹ 586.00 lakh. As per the Agreement, the project would be completed by March 31, 2021.

About The Company

M/s QuNu Labs Private Ltd., Bangalore is in the Quantum Security Technology space, engaged in the development of security products based on quantum technologies. The company provides commercial solutions whose security is assured by laws of quantum mechanics.

About the Project and Product

The company is engaged in the development of security products based on quantum technologies. The initial platforms include a Quantum Key Distribution (QKD) system and Quantum Random Number Generator (QRNG). The product variants built on these platforms are listed below:

Brand	Product Category
ARMOS	Quantum Key Distribution
HODOS	Quantum Secure Platform for QKD
TROPOS	Quantum Random Number Generator

This proposal envisages the commercialization of the above products.



ARMOS by M/s QuNu Labs Private Ltd., Bangalore

Quantum Key Distribution (QKD) is a technology by which one can exchange a key for encryption between two ends of a communication link with safety ensured by laws of quantum mechanics. The key exchange process is done on a separate fiber channel called the Quantum Channel, on which the information is sent in the form of encoded Quantum bits or "qubits". Generally, encoded photons are used and since the intensity is low, only a few of them reach the other end. Thereafter, by a process of handshaking between the two sides, done via the "classical" channel, both sides arrive at a common, sifted key. This further goes through a process of error correction and privacy amplification to further enhance its secrecy.

Such a key, derived by this sifting process is deemed to be "unconditionally secure" or in other words, even if an adversary has any amount of physically permissible computational power, he would not be able to discern the key. If an adversary tries to eavesdrop on the communication link, he will either be detected or unable to acquire adequate information and this fact is guaranteed by the principles of Quantum Physics.

QuNu has successfully interfaced the QKD platform with routers/encryptors/proprietary equipment of several large OEM's and PSU's which supply encryption solutions to Indian Defence establishments.

Financial Assistance:

₹ **280.00** lakh

Project cost:

₹ **586.00** lakh

Industrial IOT enabled IR Thermography-based Temperature Scanner



M/s Advance Mechanical Services Private Limited (AMSPL), Bangalore

SECTOR: Engineering

Technology Development Board (TDB) has entered into a Grant Agreement on 4th September, 2020 with M/s Advance Mechanical Services Private Limited (AMSPL), Bangalore for implementation of their project titled "Industrial IOT enabled IR Thermography-based Temperature Scanner" for grant assistance of ₹ 21.50 lakh against the total project cost of ₹ 70.00 lakh. As per the Agreement, the project would be completed on before July 31, 2021.

About The Company

Advance Mechanical Services is a technology conglomerate providing solutions and services around Automation and Engineering to its customers worldwide.

For past several years, Company is providing technology solutions in the areas such as CAD/CAM/CAE/PLM, Design Engineering, Controls Engineering, Automation, Robotics programming, Manufacturing Process Planning and Management, Program/Project management & Digital Manufacturing.

About the Project and Product

The project is to develop a commercial scale and reliable Industrial IOT enabled IR Thermography-based Temperature Scanner. AMSPL intends to commercialize Infrared Thermography-based Scanner for Rapid Measurement and Real Time Decision Making using an uncooled micro bolometer and video analytics platform indigenously developed providing real-time alerts and analytics using AI and IIOT. The product will be launched in the name of AMS Thermal Monitoring and Automation System (ATMAS).

Financial Assistance:

₹ **21.50** lakh

Project cost:

₹ **70.00** lakh

Advanced video analytics for low-cost thermal cameras to identify persons with abnormal body temperature in public places



M/s Cocoslabs Innovative Solutions Private Limited, Bangalore

SECTOR: Engineering

Technology Development Board (TDB) has entered into a Loan Agreement on September 23, 2020 with M/s Cocoslabs Innovative Solutions Private Limited, Bangalore for implementation of their project titled "Advanced video analytics for low-cost thermal cameras to identify persons with abnormal body temperature in public places" for loan assistance of ₹ 275.00 lakh against the total project cost of ₹ 590.94 lakh. As per the Agreement, the project would be completed on before 31st March, 2021.

About The Company

M/s Cocoslabs Innovative Solutions Private Limited, Bangalore, is in intelligent video analytics space. Cocoslabs Innovative Solutions conducts its business under the brand name 'Pixuate'. This company specializes in advanced software in the area of Computer Vision, Machine Learning and Artificial Intelligence.

About the Project and Product

Cocoslabs has developed an innovative Thermal Analytics solution to combat COVID-19 situations and prevent the spread of infection in public places. The thermal analytics solution. They use thermal camera feeds to detect body temperature and map it to the individual's face image, along with elevated body temperature, the solution also provides additional analytics like mask detection, social distance check, person face screenshot with date and time of entry, gender and age. The solution can also be combined with Pixuate's face recognition solution for offices and companies to enable contactless attendance.

Financial Assistance:

₹ **275.00** lakh

Project cost:

₹ **590.94** lakh

Portable Ultra-Violet based Box Sterilizer & Modular Movable Ultra-Violet based Indoor Room Sterilizer

M/s Evobi Automations Private Limited, Bangalore



SECTOR: Health & Medical

Technology Development Board (TDB) has entered into an agreement on 25.09.2020 with M/s Evobi Automations Private Limited, Bangalore for implementation of their project titled "Portable Ultra-Violet based Box Sterilizer & Modular Movable Ultra-Violet based Indoor Room Sterilizer" for financial assistance of ₹ 15.00 lakh against the total project cost of ₹ 35.50 lakh.



Distribution of UV sanitization boxes in different government organizations by M/s Evobi Automations Private Limited, Bangalore

About The Company

The company is working on the next generation of products and software to keep close pace with technology. The Products includes software & hardware platform for kids to tinker and build any idea they have in mind. The platform domains include Robotics, Gaming, Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), personal smart toys, Language and object identification learning toys for younger kids.

About the Project and Product

The company has entered into an agreement for commercialization of its product "Portable Ultra-Violet based Box Sterilizer & Modular Movable Ultra-Violet based Indoor Room Sterilizer". The company has developed Ultraviolet Sanitizers in two different models: one of which is portable model while other is movable. The Company has distributed 450 UV sanitizer boxes to various hospitals including JJ Hospital, Mumbai, Sasson Hospital, Pune, TMC & Nair Hospital, Mumbai and also various Government schools across the country. Company has sold more than 500 UV Sanitizer boxes and is receiving orders from various organizations.

Financial Assistance:

₹ **15.00** lakh

Project cost:

₹ **35.50** lakh

Nasomask Semi-Automatic N95 Production Machine



M/s Nanoclean Global Private Limited, New Delhi

SECTOR: Health & Medical

Technology Development Board (TDB) has entered into an agreement on 24.11.2020 with M/s Nanoclean Global Private Limited, New Delhi for implementation of their project titled "Nasomask Semi-Automatic N95 Production Machine" for financial assistance of ₹ 50.00 lakh against the total project cost of ₹ 153.65 lakh.

About The Company

M/s Nanoclean Global Private Limited. Majorly deals with Anti-Pollution Face Mask, Disposable Nose Filter, and Disposable N95 Mask. They have been awarded with National Startup Award from the President of India in 2017 for the product, Nasofilters.

About the Project and Product

TDB has supported the company for the N95 mask production during the COVID pandemic. The company, with the TDB's financial support, has successfully assembled and installed the semi-automatic N95 mask production machine and started commercial scale production of N95 masks. In return of the grand-in aid support of TDB, the Company has distributed one lakh N95 Masks to the Delhi Police. Further, the company has supported India's fight against COVID 19 by manufacturing and providing more than 3.0 lakhs N95 masks for the citizens.



Signing of Grant Agreement



Mask distribution to Delhi police

Financial Assistance:

₹ **50.00** lakh

Project cost:

₹ **153.65** lakh

inPhilia-Solutions for Parenthood – Comprehensive genetic screening for optimized parenting



M/s in DNA Life Sciences Private Limited., Bhubaneswar

SECTOR: Health & Medical

Technology Development Board (TDB) has entered into an agreement on 02.12.2020 with M/s inDNA Life Sciences Private Limited., Bhubaneswar for implementation of their project titled “inPhilia-Solutions for Parenthood – Comprehensive genetic screening for optimized parenting” for Loan assistance of ₹ 180.00 lakh against the total project cost of ₹ 425.00 lakh.

About The Company

inDNA Life Sciences is the first DNA based Clinic and a molecular platform innovated to offer customized solutions for identification of DNA based changes and its impact on the health and disease outcome. The Company has taken steps to personalize disease management by offering a range of DNA based solutions, to a range of clinical problems, in the fields of Cytogenetics, Cancer, Genetic Disorders, and Mendelian defects. The company has successfully installed a one of its kind Next generation DNA sequencing platform which is a first among such installation in Eastern India. The laboratory is an NABL accredited laboratory, becoming one of the few accredited molecular genetic laboratory presently operating in Eastern part of the country. The laboratory has also successfully collaborated with the leading clinicians in these fields.

About the Project and Product

The Company with financial assistance from TDB, aims to commercialize their indigenous

product ‘inPhilia’ which comprises of two in-house developed panels for molecular testing and screening of genetic variations related to recurrent pregnancy loss and molecular basis of male and female infertility in the Indian Population.

The outcome of the project is expected to be the creation of a genetic sequence library and generation of a database of known and novel mutations pertinent to the population of Indian origin. This will lead to identification of the causative factors behind recurrent pregnancy losses, IVF failures and idiopathic infertility; and clinically correlate lifestyle changes with infertility. The availability of these genetic panels will generate region specific database to benchmark these test in India.

Further, the technology already developed internationally for optimal performance will be validated with the Indian genetic makeup. Additionally, the costs will be optimized in order to increase affordability for citizens of India.

When introduced in the healthcare system, this solution is expected to reduce the burden of genetic diseases in the IVF babies and also aid in providing optimized fertility testing. This will lead to a positive impact on the health of future generations in India.

Financial Assistance:

₹ **180.00** lakh

Project cost:

₹ **425.00** lakh

kAs, a screening and monitoring tool for COVID 19



M/s Salcit Technologies Private Limited, Hyderabad

SECTOR: Information Technology

Technology Development Board (TDB) has entered into an agreement on 11.12..2020 with M/s Salcit Technologies Private Limited, Hyderabad for implementation of their project title "kAs, a screening and monitoring tool for COVID 19" for grant assistance of ₹ 20.00 lakh against the total project cost of ₹ 60.00 lakh. As per the Agreement, the project would be completed on 30.04.2021.

About The Company:

M/s Salcit Technologies Private Limited, Hyderabad is incubated out of VJHUB (ViganaJyothi Centre for Entrepreneurial Excellence, a section 8 registered company) at Hyderabad. The company is in development of digital health solutions for respiratory diseases based on audiometric evaluation of respiratory sounds using their patented Swaasa AI platform.

About the Project and Product

The Company proposed development and commercialization of a mobile application to screen and monitor masses towards containing COVID-19. kAs mobile application with user interface captures symptoms data and record cough sounds. The application also has interface to show the composite risk score and risk trend to user. Swaasa AI platform which does the audiometric analysis based on Machine learning based analytics. The platform received inputs from mobile or web client, process the data and returns the prediction and detailed analytics as output. Salcit tool "kAs" powered by AI platform, "Swaasa", provides precisely this capability to aid Government and other civic authorities in

prioritizing the patients with respiratory illness.

This risk score is a better predictor of the subject's risk as the cough sounds analysis provides a detailed insight into lung health status. Salcit system then allows this Risk Score to be tracked over time for large populations.

Using this tool, lower respiratory tract infection and associated respiratory pattern like Restrictive or Obstructive can be traced. Also, indicative information on diseases like Pneumonia can be provided.

Swaasa's technology is registered with the Clinical Trials Registry- India (CTRI) & WHO's International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) for respiratory sound analysis and its correlations with clinical studies.

Salcit is part of GOI's Bio-incubator at C-CAMP.



Financial Assistance:

₹ **20.00** lakh

Project cost:

₹ **60.00** lakh

Battery Powered Compact Digital Portable X-Ray Machine



M/s IATOME Electric India Private Limited, Coimbatore

SECTOR: Health & Medical

Technology Development Board (TDB) has entered into a Grant Agreement on 22nd January, 2021 with M/s IATOME Electric India Private Limited, Coimbatore for implementation of their project titled "Battery Powered Compact Digital Portable X-Ray Machine" for grant assistance of ₹ 118.00 lakh against the total project cost of ₹ 236.00 lakh. As per the Agreement, the project would be completed on before 30th September, 2022.

About The Company:

M/s IATOME Electric India Private Limited, Coimbatore is a Power Electronics Engineering and Technology company with product profile on X-Ray Generators and High Voltage Electronics. They have developed their own indigenous technology for x-ray generation, involving advanced methods in electrical, mechanical, high voltage, materials & software engineering.



Portable X-Ray Machine by M/s IATOME Electric India Private Limited, Coimbatore

About the Project and Product

The company is in Power Electronics Engineering and Technology with product expertise of X-Ray Generators and High Voltage Electronics. The company provides Engineering Design Development services in the areas of Power Electronics. Over the years, the company invested resources and developed its own technology for x-ray and high voltage products. The new technology of integrating digital control with high frequency power conversion and composite insulation resulted in compact X-ray sources. Further, Iatome is already equipped with AERB licensed facility where X-Ray equipment are being manufactured & testing and certification done in-house. In the wake of rapid spreading of Corona Virus infection to the public of our country and state, the proposed project intends to develop hand held standalone x-ray system that can be taken to the patient, and obtain a radiography image of the chest, extremities (anything other than very thick anatomy). Thus, under the present project, Iatome intends to develop a total 9 units - 01 for concept, 03 for prototype, 05 for Pilot production & Regulatory.

Financial Assistance:

₹ **118.00** lakh

Project cost:

₹ **236.00** lakh

Covid-19 Monitoring and Management solution for Affected, Quarantined or Co-Morbidity High Risk Patients to avoid or delay Lung Complications in order to reduce Case Fatality Rate (CFR)



M/s Briota Technologies Private Limited, Pune

SECTOR: Health & Medical

Technology Development Board (TDB) has entered into a Grant and Loan Agreements on 2nd March, 2021 with M/s Briota Technologies Private Limited, Pune for implementation of their project titled "Covid-19 Monitoring and Management solution for Affected, Quarantined or Co-Morbidity High Risk Patients to avoid or delay Lung Complications in order to reduce Case Fatality Rate (CFR)" for loan assistance of ₹ 85.00 lakh and grant assistance of ₹ 50.00 lakh against the total project cost of ₹ 370.00 lakh. As per the Agreement, the project would be completed on before 31st April, 2022.

About The Company:

The Company is in digital health and wellness space. They are providing innovating tech solutions for remote care, diagnostics and management for chronic respiratory conditions. In order to simplify the treatment and monitoring of conditions like Asthma and COPD, they have provided cutting-edge tech solutions tailored to both patients and doctors.



"SpiroPRO" M/s Briota Technologies Private Limited

About the Project and Product

Development, enhancement and commercialization of Briota's Digital Respiratory Platform to be used as "Covid-19 Monitoring and Management solution for Affected, Quarantined or Co-Morbidity High Risk Patients to avoid or delay Lung Complications in order to reduce Case Fatality Rate (CFR)". The project envisages commercialization of the product named "SpiroPRO" –which is India's first cost effective CDSCO approved indigenous spirometer. The digital handheld spirometer will be used to measure and monitor lung capacity, to diagnose lung infection/reduced capacity. It comes with a Mobile App, NEHA (Nurse Educator and Health Assistant) to assist during monitoring of lung condition and managing Ventilator support with telemedicine/tele counselling facility. Keeping the highly contagious nature of COVID-19 in mind, the project will assist the company to parallelly redesign their Spirometer hardware and add necessary software interfaces for one time use i.e. – Disposable Unit and home use also.

Financial Assistance:

₹ 135.00 lakh

Project cost:

₹ 370.00 lakh

Establishment of Specific Pathogen Free (SPF) Laboratory Animal Breeding and Testing Facility



M/s RCC Laboratories India Private Limited., Hyderabad

SECTOR: Health & Medical

Technology Development Board (TDB) has entered into an agreement on 10.3.2021 with M/s RCC Laboratories India Private Limited., stateHyderabad for implementation of their project title "Establishment of Specific Pathogen Free (SPF) Laboratory Animal Breeding and Testing Facility." For Loan assistance of ₹ 1554.00 lakh against the total project cost of ₹ 4079.00 lakh. As per the Agreement, the project would be completed on/before 30.8.2023

About The Company

RCC Laboratories is one of the premier companies providing Preclinical, Safety, Toxicology&Chemical Testing and maintain high quality standards and services. The company has recognition for OECD GLP certificate issued by National GLP compliance Monitoring Authority, Ministry of Science & Technology and Accredited by Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC). RCC conducts regulatory toxicology studies to meet the registration mandate for various products such as Pharmaceuticals/Drugs, Agrochemicals (pesticides), Biotech, Medical Devices, Industrial Chemicals, Tobacco, Cosmetics etc

About the Project and Product

Through this project, the company intends to establish a Specific Pathogen Free (SPF) animal breeding and testing facility to cater to the needs of Indian and Global Pharmaceutical and Biotechnology companies. The facility will adhere to global regulatory standards for animal breeding and testing following the guidelines laid out by USFDA, USEPA, OECD, EMEA, AAALAC

Schedule Y, RCGM etc. The facility will maintain high quality SPF animals, which will be bred and used for testing of pesticides, pharmaceuticals, Agro- chemicals etc. At a single location.

SPF animals are required to reduce variability, increase reproducibility in experimental results, thereby reducing drug development costs. SPF animals also help eliminate failed drug/chemical candidates early and give early confirmation of successful candidates. Reliable and unambiguous results from animal safety and efficacy studies are required for regulatory submission globally for drugs, chemicals and medical devices etc.

Lack of a SPF animal facility for breeding and testing in India has made several Indian companies import animals regularly from USA and EU for their laboratory testing purposes. This proposed facility would give Indian companies reliable and local infrastructure to evaluate their molecules in a cost and time effective manner.

Financial Assistance:

₹ **1554.00** lakh

Project cost:

₹ **4079.00** lakh



**Project
Completed**

Setting up Defence Manufacturing Facility at 50 acres Land at Vemagal Industrial Area, Kolar District, Karnataka

M/s TATA Power Company Limited, Bangalore



SECTOR: Defence and Civil Aviation



Technology Development Board (TDB) has entered into an agreement on 17.12.2016 with M/s TATA Power Company Limited, Strategic Engineering Division (Tata Power-SED), Bangalore for implementation of project "Setting up Defence Manufacturing Facility at 50 acres Land at Vemagal Industrial Area, Kolar District, Karnataka" for Loan assistance of ₹ 10900.00 lakh against the total project cost of ₹ 38500.00 lakh.

About The Company

The Strategic Engineering Division (SED), now TATA Advanced Systems Limited, is a wholly owned subsidiary of Tata Sons. It is the strategic aerospace and defence arm of the TATA Group with established capabilities and demonstrated deliveries in the areas of missile systems and sub-systems; radar systems and sub-systems; command & control systems; aerospace & aero-structures; unmanned aerial systems; optronic systems and homeland security solutions.

About the Project and Product

The project envisaged setting up a state-of-the-art innovative strategic electronic manufacturing facility for production of five broad range of equipment in the area of telecom products, strategic electronics, avionics, opto-electronics and power supply for Electronics System Design & Manufacturing (ESDM). The technology was based on in-house development in association with technology partners.

The Company has completed the project and commenced commercial operation from 9.09.2020.

Financial Assistance:

₹ **10900.00** lakh

Project cost:

₹ **38500.00** lakh

Development and Commercialization of Rule Buddy products (erstwhile “ArchITx”)

M/s. SoftTech Engineers Limited, Pune



SECTOR: Information Technology

Technology Development Board (TDB) has entered into an agreement on 6th February 2017 with M/s SoftTech Engineers Limited, Pune for implementation of their project title “development and commercialization of Rule Buddy products (erstwhile “ArchITx”)” for Loan assistance of ₹ 245.00 lakh against the total project cost of ₹ 615.46 lakh.

About The Company

M/s SoftTech Engineers Limited is dedicated to innovative reliable and world-class software products for e-governance and construction businesses, keeping in mind specific needs of their customers. SoftTech has put forth an impressive array of innovative software products like STRUDS, AutoDCR, PWIMS, OPTICON and many more. The company pioneered in automating some of the complex government process like building approvals and works management.

About the Project and Product

Develop & commercialize Rule Buddy as an e-Commerce portal to provide services for project feasibility and building permits through leveraging penetration of its flagship product AutoDCR. The scope of the Rule buddy portal is to provide a design for professional depth and information about building bylaws and building plan approval information.

It is completely indigenous product developed in-house as one stop solution to address current pain areas in construction project feasibility and building permits during the conception and design stages. Currently, no online portal is available in India to provide such services.

Financial Assistance:

₹ **245.00** lakh

Project cost:

₹ **615.46** lakh





Promotional Activities



This year, due to travel restrictions on account of COVID-19 pandemic, TDB participated in National Conference / Seminars/ Other Events in hybrid mode.

Cyber Security Investors Conference

April 11, 2020

National Centre of Excellence for Cybersecurity Technology Development and Product Entrepreneurship, a joint initiative of DSCI and the Ministry of Electronics and IT (MeitY), hosted "Security Investors Conference" towards making India a destination of cyber security innovation on April 11, 2020. This event was held virtually.

TDB participated in the event and delivered a talk

on TDB Funding on Cyber security Startup's. It was elaborated that, since the market for security product and services creates a conducive and rewarding environment for investment in cyber security start-ups, investment in cyber security in India have been picking up gradually and there is a scope to improve the understanding of key issue that will shape investment decision making in the coming years.



Cyber Security Investors Conference

FICCI-TDB Webinar on Funding Opportunities for Start-ups/SMEs for Indigenous Technology Commercialization

April 28, 2020

Technology Development Board and The Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) organised a webinar on "Funding Opportunities for Start-ups/SMEs for Indigenous Technology Commercialization", on April 28, 2020.

TDB officials participated in the event and gave brief on funding opportunities available with TDB for providing financial support to small Indian enterprises, encouraging them for

production of competitive consumer products, motivating industries for product innovation and towards development of socially relevant, profitable technologies. It was reflected that in the COVID-19 crisis, technology has been at the forefront of the battle against the pandemic. As the world adjusts to its new normal, business leader's world are rethinking and devising new strategies to harness technologies that would help, drive resilience and make them emerge from the crisis stronger.



FICCI-TDB Webinar on Funding Opportunities for Start-ups/SMEs for Indigenous Technology Commercialization April 28, 2020

Digital Conference “RE-START” on National Technology Day

May 11, 2020

Technology Development Board (TDB) and Confederation of Indian Industry (CII) jointly organized a Digital Conference “RE-START” on the occasion of National Technology Day. The digital conference “RE-START (Reboot the Economy through Science, Technology and Research Translations)” was addressed by Hon’ble Union Minister of Science & Technology, Earth Sciences and Health & Family Welfare, Dr. Harsh Vardhan.

The programme also included special addresses by Dr V. K. Saraswat, Member, NITI Aayog; Prof. K. VijayRaghavan, Principal Scientific Advisor to Government of India; Dr. Saumya Swaminathan, Chief Scientist, World Health Organization; Prof. Ashutosh Sharma, DST Secretary; Dr Renu Swarup, Secretary, Department of Biotechnology, Dr Shekhar C. Mande, DG, CSIR and H.E. Mr Vincenzo de Luca, Ambassador of Italy to India also delivered special addresses in various sessions.

This conference brought together Scientists, Technocrats, Government officials, Diplomats, WHO officials and dignitaries from national and

international Industry, Research Institutions and Academic Institutions on a single platform to share their insights on the role of Science, Technology and Innovation in the global healthcare crisis and find solutions that not only assist during the current pandemic but will also help in facing the challenges ahead.

Apart from the digital conference, a virtual exposition with companies whose technologies have been supported by TDB was available through a digital B2B lounge, showcasing their products.



Virtual Exposition by Companies



Inauguration of Digital Conference “RE-START” on National Technology Day - May 11, 2020

Innovation & Intelligent Healthcare Summit

September 15-16, 2020

ET Government and ET Health World organized a two-day virtual global summit 'Innovation & Intelligent Healthcare Summit' on September 15-16, 2020 with Technology Development Board as a support partner. This virtual summit was

focused on the emerging technologies, including Artificial Intelligence and National Digital Health Blueprint to strengthen the healthcare delivery systems countrywide. Dr. Neeraj Sharma, Secretary, TDB delivered the keynote address.



Innovation & Intelligent Healthcare Summit

International Conference on Waste to Worth

October 30, 2020

Confederation of India Industry (CII) in association with Technology Development Board, GoI and SBM, Ministry of Housing and Urban Affairs, GoI, organized the International Conference on Waste to Worth on October 30, 2020, towards encouraging better waste management across the country. Effective management of waste contributes in improving the public health, environment and national economy. This finally will lead to Swachh, Swasth, Sashakt, Sampann and Atmanirbhar Bharat. The theme of the conference was

'Achieving circular economy through innovative 3R techniques'.

Dr. Neeraj Sharma, Secretary, Technology Development Board, GoI, highlighted the importance and need of waste management technologies in India, along with associated challenges faced by India. He stated that so far, TDB has financially supported a few companies within the sector, and willing to encourage and extend more support to Indian techpreneurs.



International Conference on Waste to Worth- October 30, 2020

Virtual Road show on India's Cyber Security R&D Capabilities

November 06, 2020

TDB Participated in DSCI Road Show, a joint initiative of DSCI and MeitY. The Cyber security R&D Road show was held on Nov 06, 2020 in a virtual mode. The purpose is to make the R&D work of academic researchers, R&D institutes, and the public sector visible to the industry.

This road show was an initiative to have a consolidated view of the collaborative work on Cyber security R&D. It may be a the first step towards many more such future examples for

collaboration among industry, academia, and government to develop India's cyber capabilities.

TDB officials participated in the event and explored the road show to get insight on the research work & state-of-art labs to experience innovative technology prototypes & products and to explore opportunities with researchers and institutes. TDB also contributed in the discussion to boost the country's cyber capabilities.



Virtual Road show on India's Cyber Security R&D Capabilities

56th Annual Seminar of Fertiliser Association of India

December 07-09, 2020

Agriculture has always remained mainstay of livelihood in India. The theme for the Seminar this year is 'Fertilizer and Agriculture during COVID-19'. This platform facilitated exchange of ideas in the areas of fertilizer supply-demand, price trends, policy environment, fertilizer use efficiency, developments in fertilizer production

technologies and supply chain management during COVID-19.

TDB participated in the event and explored the opportunity to comprehend India specific gaps and required support to the Indian agriculture industry.



56th Annual Seminar of Fertiliser Association of India

26th DST-CII India-Portugal Technology Summit

December 07-09, 2020

TDB participated in the 26th DST-CII Technology Summit held during December 07-09, 2020. The focus themes of the summit were Watertech, Agritech, Healthtech, Energy, Climate Change, IT, ICT, Advanced Technologies, Start-ups & Innovation and Space-Ocean Interactions.

Dr. Harsh Vardhan, Hon'ble Minister of Science & Technology, Health and Family Welfare and Earth Sciences, Government of India, inaugurated

the summit and the digital exhibition on 7th December, 2020.

Professor Ashutosh Sharma, Secretary DST & Chairperson TDB, highlighted that this Summit has served as a platform to forge and strengthen bilateral partnerships, led to the formation of new joint ventures, and created new avenues for collaboration to boost trade and investment between the two countries.



26th DST-CII India-Portugal Technology Summit.

Pre-Event of IISF 2020

December 10, 2020

A 'Pre-Event of IISF 2020' was organised on December 10, 2020 which was jointly coordinated by Technology Development Board, CSIR-NEERI and International Institute of Waste Management (IIWM), Bangalore on the theme – "Self-Reliant India through Entrepreneurship Development in Waste Management". The webinar provided an opportunity for aspiring entrepreneurs, early stage impact start-up's and other ecosystem

players in the waste management sector to bring positive changes in the society, to gain insights into subsectors and scope for entrepreneurship and funding avenues.

TDB participated in the event and detailed about the funding avenues available with TDB for innovative Indian technopreneurs.



Pre-Event of IISF 2020

6th Smart Cities India 2021 Expo

March 24 – 26, 2021

The event was organised by the India Trade Promotion Organisation (ITPO) & Exhibitions India Group and was held at Pragati Maidan, New Delhi, from 24-26 March, 2021. The expo key verticals featured smart city framework of Smart Cities including Buildings, Solar, Transport, Water, etc.

6th Smart Cities India 2021 expo provided a platform that enabled deeper communication and

a more practical approach to resolving societal problems, offering business opportunities for organisations working towards making smart cities a reality.

TDB participated in the event and shared the funding avenues available at TDB for innovative techpreneurs.



6th Smart Cities India 2021 Expo at New Delhi





Administration



ADMINISTRATION

Annual Report and Audited Accounts

Section 12 of the Technology Development Board Act, 1995, prescribes that the Board shall prepare its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year. As per section 13(4) of the Technology Development Board Act, the Board has to furnish to the Central Government, its audited copy of accounts together with auditor's report.

The Annual Report, including audited copy of the Annual Accounts of the Technology Development Board for the year 2019-20 was laid before Rajya Sabha and Lok Sabha on 09.02.2021 and 12.02.2021 respectively.

TDB Secretariat

Smt. Nishtha Bhatnagar, former Manager, State Bank of India has joined TDB as Accounts Officer w.e.f. 08.02.2021.

Implementation of Official Language

With a view to ensure compliance of the constitutional provisions regarding official language, TDB has been encouraging the usage

of Hindi in all official communication. Hindi Pakhwada/ Hindi Diwas was celebrated in the month of September, 2020, wherein various competitions such as Shrutilekh, Essay writing, Poetry, Speech, Translation etc. were organized.

During 2020-21, inspection of TDB by Draft & Evidence Sub-committee of Hindi Parliamentary Committee on Official Language was held on 18.11.2020.

Observance of Vigilance Week

To achieve corruption free governance, Central Vigilance Commission is committed to implement the policy of 'Zero Tolerance against Corruption'. For the year 2020, the Commission decided to observe Vigilance Awareness Week from 27th October to 02nd November 2020 with the theme "सतर्क भारत, समृद्ध भारत- Satark Bharat, Samridh Bharat (Vigilant India, Prosperous India)."

TDB acknowledged the responsibility of being a corruption free organization with strict adherence



to Zero Tolerance policy towards Corruption for which TDB observed Vigilance Week from 27th October to 02nd November, 2020, which started with Integrity Pledge taken by all the Officers and Staff Members.

During the week various competition such as Quiz, Debate, Speech, Essay Writing and Slogan Writing were organized. Every staff member of TDB participated in the competition with zeal and enthusiasm.





Annual Statement



ANNUAL STATEMENT OF AUDITED ACCOUNTS FOR THE YEAR 2020-21

Technology Development Board

Balance Sheet as on 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Corpus/capital fund	1	15,68,59,44,667	14,68,52,37,882
Reserves and Surplus	2	-	-
Earmarked/Endowment Funds	3	8,60,24,859	4,63,51,775
Secured Loans and Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans and Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities	6	-	-
Current Liabilities and Provisions	7	73,68,10,769	77,34,99,891
TOTAL		16,50,87,80,295	15,50,50,89,548
Assets			
Fixed Assets	8	84,95,873	66,77,633
Investment - from Earmarked/Endowment Funds	9	65,99,000	65,99,000
Investments - others	10	1,16,63,34,106	1,40,19,52,366
Current Assets, Loan, Advances etc.	11	15,32,73,51,316	14,08,98,60,549
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)			
TOTAL		16,50,87,80,295	15,50,50,89,548
Significant Accounting Policies	24	-	-
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25	-	-

-Sd-
(Rajesh Jain)
Director
Technology Development
Board

-Sd-
(Dr. Neeraj Sharma)
Secretary
Technology Development
Board

-Sd-
(Prof. Ashutosh Sharma)
Chairperson
Technology Development
Board

Technology Development Board

Income and Expenditure Accounts for the Year ending 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
Income from Sales/ Services	12	-	-
Grants / Subsidies	13	11,56,38,978	98,38,34,331
Fees/ Subscriptions	14	-	-
Income from Investments (Income on Invest. from Earmarked/Endow)	15	-	-
Income from Royalty, Publication etc.	16	35,09,803	44,87,232
Interest Earned	17	60,00,36,912	63,60,54,565
Other Income	18	35,78,35,993	3,03,563
Increase/(decrease) in stock of finished goods and works-in-progress	19		
TOTAL (A)		1,07,70,21,687	1,62,46,79,691
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	3,66,06,098	3,35,32,639
Other Administrative Expenses; etc.	21	3,26,45,669	35,21,08,711
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	12,05,791	10,84,242
Interest	23	-	209,24,330
Depreciation (net total at the year-end – corresponding to schedule - 8)		14,32,703	11,03,455
TOTAL (B)		7,18,90,260	40,87,53,377
Balance being Excess of Income Over Expenditure (A-B)		1,00,51,31,426	1,21,59,26,314
Prior Period Adjustments		(44,24,641)	(2,45,734)
Provision for Impairment of Investments			
Transfer to General Reserve		-	-
Balance Being Surplus Carried to Corpus Fund		1,00,07,06,785	1,21,56,80,580
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

-Sd-
(Rajesh Jain)
Director
Technology Development
Board

-Sd-
Dr. Neeraj Sharma
Secretary
Technology Development
Board

-Sd-
(Prof. Ashutosh Sharma)
Chairperson
Technology Development
Board

Technology Development Board

Receipts and Payments Accounts for the Year ending 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

RECEIPTS		Current Year	Previous Year
Opening Balance			
i)	Investment in Short Term Deposits	56,99,00,000	49,95,00,000
ii)	Cash in Hand	34,976	23,520
Cash at Bank			
a)	Bank Balance	1,26,10,21,180	7,59,89,345
b)	Bank Balance - DFID INVENT	3,97,52,776	13,66,14,643
Fund for Technology Development & Application			
i)	TD Fund	10,00,00,000	98,00,00,000
ii)	Fund for Fighting COVID-19	-	75,00,00,000
iii)	Interest on Short Term Deposits	4,23,09,523	3,34,75,287
iv)	Interest on Loans	18,08,99,609	7,64,94,764
v)	Interest on Royalty	2,16,794	2,95,247
vi)	Interest on Grants	14,78,533	-
vii)	Repayment of Loans	96,47,10,885	63,33,72,600
viii)	Royalty	35,09,803	44,87,232
ix)	Donations	2,00,000	3,00,000
x)	Unspent Grant received Back	1,56,38,978	38,34,331
xi)	Interest on Saving Accounts (including EPF A/c)	1,79,99,301	86,65,931
xii)	Income recd from VCF Fund	36,60,29,271	-
xiii)	Miscellaneous Receipts	32,399	3,563
xiv)	Asset Realisation	12,399	
xv)	Security Deposit / Earnest Money received/Others	-	1,64,231
xvi)	Multi Sector Seed Fund	9,61,39,030	76,55,900
xvii)	UTI _ Ascent India Fund	-	1,46,31,293
xviii)	RVCF	1,17,74,229	34,34,150
xix)	GVFL	-	-
xxi)	Equity Realisation	7,02,64,200	6,56,68,800

xxii)	SIDBI Venture Fund	2,25,23,262	1,44,18,678
xxiii)	Indian fund for Sustainable Energy (CIIE)	77,66,033	-
xxiv)	IvyCap Venture Trust Fund-1	1,57,41,937	10,34,438
xxv)	APIDC Venture Fund	39,60,314	2,50,00,000
xxvi)	SEAF India Fund	11,21,514	1,86,63,888
xxvii)	Security Deposit & Advance to staff recovered	93,085	-
xxviii)	DFID Incent Receipt for Project	3,76,96,231	-
xxvix)	DFID Incent Savings Interest	19,76,923	31,38,224
		TOTAL	3,83,28,03,186
			3,35,68,66,065

-Sd-
(Rajesh Jain)
 Director
 Technology Development
 Board

-Sd-
(Dr. Neeraj Sharma)
 Secretary
 Technology Development
 Board

-Sd-
(Prof. Ashutosh Sharma)
 Chairperson
 Technology Development
 Board

Technology Development Board

Receipts and Payments Accounts for the Year ending 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

PAYMENTS		Current Year	Previous Year
Establishment Expenses			
i)	Salaries	3,56,72,789	3,16,67,445
ii)	Travel Expenses (Domestic)	13,58,457	17,73,934
iii)	Travel Expenses (International)	-	-
iv)	Staff welfare Expenses & OTA	1,11,023	77,000
v)	Medical Expenses	5,06,052	2,23,558
vi)	Pension Contribution for Deputationist	-	-
Office Expenses			
i)	Telephone / Telex	19,23,299	20,66,491
ii)	Postage Stamps	37,310	55,443
iii)	Petrol, Oil, Lubricants	19,487	41,422
iv)	Repairs & Maintenance	25,24,758	12,80,715
v)	Consumable Stores & Printing	6,59,099	12,09,624
vi)	Newspapers & Magazines	-	36,123
vii)	Entertainment & Hospitality	86,601	1,90,132
viii)	Meeting Expenses	2,31,719	15,33,468
ix)	Advertisement & Publicity	44,20,269	63,26,171
x)	Technology Day Expenditure	18,94,259	6,96,212
xi)	Miscellaneous Expenses	7,69,525	6,59,475
xii)	Library Books & Journals	-	885
xiii)	Legal Charges	34,95,859	44,78,038
xiv)	Asset Management Charges	29,74,302	71,96,785
xv)	TA / DA to Experts	2,85,667	26,04,299
xvi)	Honorarium to experts and members	46,28,073	55,00,880
xvii)	Membership Fees	47,200	23,600
xix)	Audit Fees	-	77,850
xx)	Rent	68,28,548	85,36,700
xxi)	Remittance of recoveries to other deptts.	-	-
xxii)	Security Deposit & Advance to staff		46,505
xxiii)	Advances Others	40,453	
xxiv)	Duties & Taxes	1,12,088	4,60,031
xxv)	Water & Electricity	3,71,929	-

Board Expenses			
i)	TA / DA to Members	9,308	24,457
ii)	Fee and Board Meeting Expenses	-	1,43,645
Capital Expenditure			
i)	Assets purchase	32,63,343	9,12,353
Disbursements			
i)	Loans	47,56,85,000	1,28,37,12,000
ii)	Grants	12,05,791	10,84,242
iii)	Interest on Grant paid	-	2,09,24,330
iv)	Loan released under COVID-19 Grant	2,12,00,000	-
v)	Grant for Covid	1,39,38,000	
vi)	SEAF India Agribusiness Fund	-	5,77,473
vii)	Indian fund for Sustainable Energy (CIIE)	10,89,645	20,15,756
viii)	DFID INVENT Project Expenditure	-	10,00,00,000
ix)	DFID INVENT Bank Charges	71	91
x)	Other Expenses payable	18,35,268	-
Closing Balance			
i)	Investment in Short Term Deposits	1,66,99,00,000	56,99,00,000
ii)	Cash in Hand	22,149	34,976
Cash at Bank			
a)	Bank Balance (including EPF A/C)	1,49,62,29,986	1,26,10,21,180
b)	Bank Balance- DFID INVENT	7,94,25,859	3,97,52,776
		TOTAL	3,83,28,03,186
			3,35,68,66,065

-Sd-
(Rajesh Jain)
Director
Technology Development
Board

-Sd-
(Dr. Neeraj Sharma)
Secretary
Technology Development
Board

-Sd-
(Prof. Ashutosh Sharma)
Chairperson
Technology Development
Board

Technology Development Board

Schedules Forming Part of Balance Sheet as on 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 1- CORPUS/CAPITAL FUND		
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Balance as at the beginning of the year	14,68,52,37,882	13,46,95,57,302
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund	-	-
Add : Balance of net income transferred from the Income and Expenditure Account [refer to Note No 25 (11)]	1,00,07,06,785	1,21,56,80,580
BALANCE AS AT THE YEAR- END	15,68,59,44,667	14,68,52,37,882

SCHEDULE 2- RESERVES AND SURPLUS				
	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Capital Reserve:				
As per last Account				
Addition during the year				
Less: Deductions during the year	-	-	-	-
2. Revaluation Reserve:				
As per last Account				
Addition during the year				
Less: Deduction during the year	-	-	-	-
3. Special Reserves:				
As per last Account				
Addition during the year				
Less: Deduction during the year	-	-	-	-
4. General Reserve:				
As per last Account				
Addition during the year				
Less: Deduction during the year				
TOTAL	-	-	-	-

Technology Development Board

Schedules Forming Part of Balance Sheet as on 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 3- EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS				
LIABILITIES	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
A. VCF of IDBI				
1) Contribution received by IDBI from Government of India		28,84,00,000		28,84,00,000
Income from Investment				
a. Interest	13,31,47,041		13,08,52,144	
b. Royalty	5,51,97,900		5,51,97,900	
c. Dividend	86,23,794		86,23,794	
d. Accrued income Less waivers	2,38,80,81,913		2,39,03,76,810	
	2,58,50,50,648		2,58,50,50,648	
Less : Amount transferred to TDB	21,25,00,000		21,25,00,000	
	2,66,09,50,648		2,37,25,50,648	
Less: Excess Royalty recd. Earlier adjusted towards principal	1,12,50,000		1,12,50,000	
	2,64,97,00,648		2,36,13,00,648	
Less : Loans written off	4,36,36,450		4,36,36,450	
Less : Loss on sale of Investment	26,76,250		26,76,250	
	2,60,33,87,948		2,31,49,87,948	
Less : Provision on loan	8,32,79,357		8,10,04,357	
Less : Provision on interest & FILD	2,38,80,81,913		2,39,03,76,810	
Less: Audit Fees & other Expenses	18,32,324		17,52,075	
Less : Management fees to IDBI	15,71,80,000		14,32,60,000	
Less: Diminution in value of investment	26,26,000	(2,96,11,646)	26,26,000	(30,40,31,294)
*Amount receivable from TDB (31.03.2019)		(2,96,11,646) 362,10,646		-156,31,294 222,30,294
		65,99,000		65,99,000
B. Innovative Ventures for Technology Development (INVENT) - DFID				
		7,94,25,859		3,97,52,775
TOTAL		8,60,24,859		4,63,51,775

***Note:**

- 1) Due to non performance of the fund, the amount of management expenses claimed by IDBI has been disputed by TDB
- 2) Amount of Rs. 3,62,10,646/- has been claimed by IDBI as payable by TDB as per their last audited balance sheet for the year ended 31.03.2019. The said amount has arisen due to high management fees charged by IDBI which is disputed by TDB. TDB does not acknowledge the payment of said amount pending resolution of said amount.

Technology Development Board

Schedules Forming Part of Balance Sheets as on 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS:				
	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Central Government	-	-	-	-
2. State Government (Specify)	-	-	-	-
3. Financial Institutions				
a) Term Loans				
b) Interest accrued and due	-	-	-	-
4. Banks:				
a) Term Loans				
- Interest accrued and due				
b) Other Loans (Specify)				
- Interest accrued and due	-	-	-	-
5. Other Institutions and Agencies	-	-	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

Note : Amounts due within one Year

Technology Development Board

Schedules Forming Part of Balance Sheets as on 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 5- UNSECURED LOANS AND BORROWINGS				
	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Central Government	-	-	-	-
2. State Government (Specify)				
3. Financial Institutions	-	-	-	-
4. Banks:				
a) Terms Loans	-	-	-	-
b) Other Loans (Specify)	-	-	-	-
5. Other Institutions and Agencies	-	-	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-	-	-
7. Fixed Deposits	-	-	-	-
8. Others (Specify)	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

Note: Amounts due within one Year

Technology Development Board

Schedules Forming Part of Balance Sheet as on 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES			
		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a. Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets		-	-
b. Others			
	TOTAL		

Note : Amounts due within one year

Technology Development Board

Schedules Forming Part of Balance Sheet as on 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
A. CURRENT LIABILITIES			
1. Unutilised balance of Grant in Aid "Fighting COVID-19"	73,60,62,000		75,00,00,000
Less: Utilised towards Loan under COVID-19 Fund	2,12,00,000	71,48,62,000	
2. Sundry Creditors			
a) For Goods	-		
b) Others	-	-	
3. Security Received		-	-
4. Interest accrued but not due on:			
a) Secured Loans/borrowings			
b) Unsecured Loans/borrowings	-	-	-
5. Statutory Liabilities			
a) TDS	2,80,049		3,60,502
b) GST	28,029		48,961
c) GPF payable			
d) EPF payable	3,23,094	6,31,172	3,33,797
6. Other current Liabilities			
a) Pension contribution for deputationist			
b) Audit fee payable	4,69,839		3,89,839
c) Pending Adjustment	-		-
d) others	-	4,69,839	-
	TOTAL (A)	71,59,63,011	75,11,33,099
B. PROVISIONS			
1. Gratuity	21,39,484		17,08,387
2. Salary Payable	16,91,054		18,05,917
3. Legal charges payable	-		
4. National Award Payable	1,70,00,000		1,70,00,000
5. Other Expenses Payable	17,220	2,08,47,758	18,52,488
	TOTAL (B)	2,08,47,758	2,23,66,792
	TOTAL (A+B)	73,68,10,769	77,34,99,891

Technology Development Board

Schedules Forming Part of Balance Sheet as on 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS	DESCRIPTION	GROSS BLOCK			DEPRECIATION			NET BLOCK				
		Cost/ valuation as at Beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost / Valuation at the year-end	As at the Beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Total up to the year - end	Sales/ ad-just-ments	As at 31.3.2021	As at 31.3.2020
A. Fixed assets:												
1. Land:												
A) freehold												
2. Building:												
A) on freehold land												
B) on leasehold land												
C) ownership flats/ premises												
D) superstructures on land not belonging to the entity												
3. Plant machinery & equipment												
4. Vehicles												
5. Furniture, fixtures												
6. Office equipment												
7. Computer/ peripherals												
8. Electric installations												
9. Library books												
10. Software (pms)												
11. E office- software												
11. Other fixed assets												
Total of current year		148,67,696	32,63,343	78,280	180,52,759	81,90,063	14,32,703	65,880	95,56,886	12,399	84,95,873	66,77,633
B. Capital work-in-progress* (Software)												
TOTAL		148,67,696	32,63,343	78,280	180,52,759	81,90,063	14,32,703	65,880	95,56,886	12,399	84,95,873	66,77,633
(Note to be given as to cost of assets on hire purchase basis included above)												
Previous year		139,55,343	9,12,353	-	148,67,696	70,86,608	11,03,455	-	81,90,063	-	66,77,633	68,68,735

Note:

- During the financial year 2019-20, depreciation on (PMS) was less charged by ₹2,36,207/-. This amount has been claimed in the current year as additional depreciation.
- Depreciations on e-office software capitalised during the year has been charged on straight line basis to amortize the full value over its the 5 year life.

Technology Development Board

Schedules Forming Part of Balance Sheet as on 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS			
	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR
1. In Government Securities	-		-
2. Other approved Securities	-		-
3. Shares	-		-
4. Debentures and Bonds	-		-
5. Subsidiaries and Joint Ven- tures	-		-
6. VCF of IDBI (Assets)	-		-
Investment			
(i) Loan	8,10,04,357		8,10,04,357
Less: Provisions	8,10,04,357	-	8,10,04,357
(ii) Equity	92,25,000		92,25,000
Less: Diminution in value of Investment	26,26,000	65,99,000	26,26,000
Receivables			
(i) Interest	29,97,69,021		29,97,69,021
(ii) FILD	2,09,06,07,789		2,09,06,07,789
	2,39,03,76,810		2,39,03,76,810
Less: Provisions	2,39,03,76,810	-	2,39,03,76,810
TOTAL		65,99,000	65,99,000

Technology Development Board

Schedules Forming Part of Balance Sheet as on 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 10 – INVESTMENTS-OTHERS			
	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR
1. In Government Securities			
2. Other approved Securities			
3. Shares-Equity/ Preference participation	20,81,62,967		20,81,62,967
Less: Realisation against shares	7,02,64,200	13,78,98,767	
4. Debentures and Bonds			
5. Subsidiaries and Joint Ventures			
6. Venture Funds			
a) UTI Ascent India Fund	-		
b) APIDC Venture Funds	20,97,86,000		
Less: Redemption	39,60,314	20,58,25,686	20,97,86,000
c) Ventureast TeNet Fund	4,41,43,882		
Less: Redemption	-	4,41,43,882	4,41,43,882
d) CVFL	1,50,000	-	
Less: Redemption	-	1,50,000	1,50,000
e) RVCF	11,44,40,574		
Less: Redemption	2,02,02,156	9,42,38,418	11,44,40,574
f) SIDBI VCF	17,43,08,185		
Add: Disbursement	-		
Less: Redemption	2,25,23,262	15,17,84,923	17,43,08,185
g) IvyCap Venture Trust Fund-1	21,58,57,800		
Add: Disbursement	-		
Add: prior period adjustment	10,10,541		
Less: Redemption	1,57,41,937	20,11,26,404	21,58,57,800
h) Multi Sector Seed Capital Fund	9,63,44,100		
Less: Redemption	9,61,39,030	2,05,070	9,63,44,100
i) SEAF India Agribusiness Fund	21,00,49,055		
Add: Disbursement	-		
Less: Redemption	11,21,514	20,89,27,541	21,00,49,055
j) Indian fund for Sustainable Energy (CIIE)	5,66,59,803		
Add: Disbursement	10,89,645		
Less: Redemption	77,66,033	4,99,83,415	5,66,59,803
7. GITA	7,20,50,000		
Add: Disbursement	-	7,20,50,000	7,20,50,000
TOTAL		1,16,63,34,106	1,40,19,52,366

Technology Development Board

Schedules Forming Part of Balance Sheet as on 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.				
		CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR
A. CURRENT ASSETS:				
1. Inventories:				
a) Stores and Spares				
b) Loose Tools				
c) Stock-in-trade				
i) Finished Goods				
ii) Work-in-progress				
iii) Raw Material		-	-	-
2. Sundry Debtors				
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months				
b) Others			-	-
3. Cash balance in hand (including cheques/drafts and imprest)			22,149	34,976
4. Bank Balances:				
a) With Scheduled Banks:				
- On Current Accounts				
- On Savings Accounts -TDB (including EPF A/c)		1,49,62,29,986		1,26,10,21,180
- On Savings Accounts- INVENT -DFID		7,94,25,85,859	1,57,56,55,845	3,97,52,776
b) Short term Deposits with Scheduled Banks:				
- On Deposit Accounts		1,66,99,00,000	1,66,99,00,000	56,99,00,000
- On Deposit Accounts INVENT-DFID				
TOTAL (A)			3,24,55,77,994	1,87,07,08,932

Technology Development Board

Schedules Forming Part of Balance Sheet as on 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 11- CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)			
	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS:			
1. Loans:			
a) Staff			
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the entity	-		-
c) Loan : Assistance to industrial concerns opening	79043,22,401		73099,65,366
Add: During the year	47,56,85,000		1,28,37,12,000
Less: Repayment/Adjustment of loan	96,47,10,885		67,63,10,641
Less: Written Off due to settlement of accounts	-		1,11,54,978
Less: Transfer to Accrued Interest.	-		18,89,347
Add: Prior period Adjustments.	26,78,872		
	7,41,26,17,644		7,90,43,22,401
Less: Provision for doubtful loan	-		-
Closing loan balance after provision		7,41,26,17,644	7,90,43,22,401
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or of value to be received			
a) Advance to staff members	7,78,195		8,71,280
b) Income tax recoverable	14,91,903		11,38,824
c) Others - Security Deposit	9,90,280		9,90,280
d) Advance with vendors	-		-
e) Others	64,509	33,24,887	24,056
3. Income Accrued:			
a) On Investments from Earmarked/Endow.Funds			
b) On saving account	63,00,311		-
c) On Investments - Short Term Deposits	94,98,531	1,57,98,842	36,83,794
Short Term Deposits- INVENT -DFID	-		-
d) On Loans and Advances	4,88,56,24,552		4,56,25,70,377
Less: Unrecoverable interest written off during the year	-		2,28,56,713
Less: Transfer to loan	-		
Less: Prior Period Adjustments during the year	27,56,310		6,45,734
Add: Transfer from loan	-		18,89,347
	4,88,28,68,242		4,54,09,57,277
Less: Loan Interest Provision :	23,28,36,293		23,28,36,294
		4,65,00,31,949	4,30,81,20,983
TOTAL (B)		12,08,17,73,322	12,21,91,51,617
TOTAL (A+B)		15,32,73,51,316	14,08,98,60,549

Technology Development Board

Schedules Forming Part of Income and Expenditure For the Year Ended 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES/SERVICES			
		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Income from Sales			
a) Sales of Finished Goods			
b) Sale of Raw Material			
c) Sale of Scraps		-	-
2. Income from Services			
a) Labour and Processing Charges			
b) Professional/Consultancy Services			
c) Agency Commission and Brokerage			
d) Maintenance Services(Equipment/Property)			
e) Others (Specify)			-
	TOTAL	-	-

Technology Development Board

Schedules Forming Part of Income and Expenditure For the Year Ended 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 13 - GRANTS/SUBSIDIES (Irrevocable Grants & Subsidies Received)			
		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1) Central Government		10,00,00,000	98,00,00,000
2) State Government(s)			
3) Institutions/Welfare Bodies		-	-
4) International Organisation			
5) Others- Unspent grants received back		1,56,38,978	38,34,331
	TOTAL	11,56,38,978	98,38,34,331

Technology Development Board

Schedules Forming Part of Income and Expenditure For the Year Ended 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 14 - FEES/SUBSCRIPTIONS			
	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR
1) Entrance Fees	-	-	-
2) Annual Fees/Subscriptions			
3) Seminar/Program Fees	-	-	-
4) Consultancy Fees	-	-	-
TOTAL	-	-	-
Note -Accounting Policies towards each item are to be disclosed			

Technology Development Board

Schedules Forming Part of Income and Expenditure For the Year Ended 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 15- INCOME FROM INVESTMENTS			
(Income on Invest. From Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)			
	Investment from earmarked fund		Investment - Others
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR
1) Interest			
a) On Govt. Securities			
b) Other Bonds/Debentures			
2) Dividends			
a) On Shares			
b) On Mutual Fund Securities			
3) Rents	-	-	-
4) Other (Specify)	-	-	-
TOTAL			
Transferred to earmarked/endowment funds			

Technology Development Board

Schedules Forming Part of Income and Expenditure For the Year Ended 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.			
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	
1) Income from Royalty		35,09,803	44,87,232
2) Royalty Accrued			
Less: Royalty written off			-
3) Others (Specify)			
TOTAL		35,09,803	44,87,232

Technology Development Board

Schedules Forming Part of Income and Expenditure For the Year Ended 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 17-INTEREST EARNED			
		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1) On Term Deposits:			
a) With Scheduled Banks		4,81,24,260	2,91,22,606
b) With Non- Scheduled Banks			-
c) With Institutions			-
2) On Savings Accounts:			
a) With Scheduled Banks (including EPF A/c)		2,42,99,612	86,65,931
b) With Non- Scheduled Banks			-
c) Post Office Savings Accounts			-
d) Others			
3) On Loans:			
a) Employees/Staff			
b) Loans assistance to industrial concerns		52,59,17,713	59,79,70,781
4) Interest on royalty		2,16,794	2,95,247
5) Interest on grants		14,78,533	-
	TOTAL	60,00,36,912	63,60,54,565
Note- Tax Deducted at source to be indicated			

Technology Development Board

Schedules Forming Part of Income and Expenditure For the Year Ended 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 18-OTHER INCOME			
		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1) Profit on Sale/disposal of Assets:			
a) Owned assets - UTI			
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost			
2) Profits on redemption of units		35,76,01,344	-
3) Dividend		-	-
4) Miscellaneous Income		4,649	3,563
5) Sitting Fees		30,000	-
6) Donations		2,00,000	3,00,000
7) Income from Venture Fund		-	-
	TOTAL	35,78,35,993	3,03,563

Technology Development Board

Schedules Forming Part of Income and Expenditure For the Year Ended 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 19- INCREASE/(DECREASE) STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS			
	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR
a) Closing Stock:			
- Finished Goods			
- Work-in-progress	-	-	-
b) Less: Opening Stock			
- Finished Goods			
- Work-in-progress	-	-	-
NET INCREASE / (DECREASE) [a-b]	-	-	-

Technology Development Board

Schedules Forming Part of Income and Expenditure For the Year Ended 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 20-ESTABLISHMENT EXPENSES		
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Salaries and Wages	3,41,15,706	3,09,94,096
b) Allowances	29,023	4,32,759
c) Employer Contribution to Provident Fund	14,42,220	14,49,312
d) Uniform	-	-
e) Staff Welfare Expenses	82,000	77,000
f) Expenses on Employees' Retir. And terminal Benefits	-	-
g) Reimbursement of Medical Charges	5,06,052	2,23,558
h) Gratuity	4,31,097	3,55,914
TOTAL	3,66,06,098	3,35,32,639

Technology Development Board

Schedules Forming Part of Income and Expenditure For the Year Ended 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 21-OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.			
		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a)	National Award	-	1,70,00,000
b)	Legal charges	34,95,859	45,81,332
c)	Assets Management Fees	29,74,302	71,96,785
d)	Membership fees	47,200	23,600
e)	TDS and Interest	-	-
f)	Loss on sale of assets	-	-
g)	Repairs and maintenance	25,24,758	12,80,715
h)	Postage & stamps	37,310	55,443
i)	Technology Day Expenditure	18,94,259	6,96,212
j)	Vehicles Running and Maintenance	19,487	41,422
k)	Telephone and Communication Charges	19,23,299	21,25,374
l)	Printing , Stationary & Consumables	6,59,099	12,34,404
m)	Travel Expenses Domestic a) Domestic 13,58,457		-
	Travel Expenses Foreign b) Abroad -		-
	Travel Expenses Experts c) Experts 2,85,667	16,44,124	48,93,086
n)	Library books & periodical	-	885
o)	TA/DA to Board members	-	24,457
p)	Auditors Remuneration	80,000	80,000
q)	Hospitality Expenses	86,601	1,90,132
r)	Meeting Expenses	2,31,719	15,85,545
s)	Professional Charges	46,28,073	55,12,480
t) a)	Unrecoverable Interest written off during the Year	-	2,28,56,713
	b) Loans Written off due to settlement of accounts	-	1,11,54,978
	c) Loan Provision	-	(89,05,867)
	d) Interest Provision for the Year	-	(1,10,58,058)
u)	Bank Charges	-	-
v)	Misc. Expenses	7,69,525	6,74,975
w)	Newspaper & Magazine		36,123
x)	Advertisement and Publicity	44,20,269	63,26,171
y)	Board Expenses & fees	9,308	1,43,645
z)	Rent	68,28,548	90,69,257
	zi) Water and Electricity Charges	3,71,929	-
	zii) Loss on closure of Venture fund (Refer to schedule 25 note no.5)		27,52,88,902
	TOTAL	3,26,45,669	35,21,08,711

Technology Development Board

Schedules Forming Part of Income and Expenditure For the Year Ended 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 22 - EXPENDITURE ON GRANTS		
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1) Grants given to Institutions/ Organisations		
(i) Incubators	12,05,791	10,84,242
(ii) For Covid	-	-
2) Subsidies given to Institutions / Organisations		
TOTAL	12,05,791	10,84,242

Note: Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants/ Subsidies are to be disclosed

Technology Development Board

Schedules Forming Part of Income and Expenditure For the Year Ended 31st March, 2021

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 23-INTEREST		
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) On Fixed Loans		
b) On Other Loans (including bank Charges)		
c) Others-Grant received from DST	-	2,09,24,330
TOTAL		2,09,24,330

Schedule – 24

Technology Development Board

Significant Accounting Policies and Notes on Accounts-2020-21

A. Significant Accounting Policies

1. Receipts and Payments Accounts is prepared from the cash receipt journal and is a summary of cash transactions under various heads. It records receipts and payments of both capital and revenue nature.
2. Income and Expenditure Account is the summary of incomes and expenditures of the year. It is prepared on accrual basis. It records income and expenditure of revenue nature only. The accrued interest earned on the loan amount disbursed is accounted for in the year in which the loan installment is released; however, the interest is actually receivable after the projects have been completed in accordance with the terms and conditions of the respective loan agreements. Provision for expenses due and approved are accounted for during the year.
3. Depreciation on fixed assets is provided on the basis and rates prescribed under the Income Tax Act, 1961, on diminishing balance method. No depreciation is provided on the fixed Assets sold/transferred/discarded during the financial year. Addition in fixed assets are accounted at the cost of acquisition.
4. Royalty payments are taken on receipt basis in Receipts and Payments Account and Income & Expenditure Account.
5. Government grants are recognized on receipt basis. Unspent balances are not to be refunded to the Government of India as the grants released by the Government are credited to the Fund for Technology Development and Application in terms of section 9(1)(a) of the Technology Development Board Act, 1995 and thus there is no such requirement of refund. No amount is, therefore, due for refund to the Government of India.
6. In terms of section 9(1) of the Technology Development Board Act, 1995, recoveries made of the amounts granted from the Fund for Technology Development and Application, receipt of interest on loans, royalty, donations and sums received from any other source are credited to the Fund. Keeping this provision in view, the Balance Sheet has been prepared.
7. The balance sheet of Earmarked/ Endowment funds (Venture Capital Funds) maintained by IDBI has indicated the following:-
 - a) The balance sheet is prepared on accrual basis except for income/expenditure in respect royalty, management fee and penal interest thereon, which are recognized on actual receipt/ payment.
 - b) The valuation of assets/ loans/ investments have been carried at the assessment value by IDBI (Fund manager) and the provision for reducing the book value of the assets is recorded as per the notes provided in the financial statements.

- c) The financial statements of IDBI (VCF) are to be read with other notes and explanations attached with the Balance Sheet provided by IDBI. The financial statements and notes to accounts are taken on record as independently certified by IDBI and the audit report thereon.
8. Fund balances are kept in short term deposits in nationalized banks. Interest on short term deposits is reflected in the Receipts and Payments Account and Balance Sheet.
 9. The investments in companies are stated at cost price. As per the mandate of TDB, the investments are not held for capital appreciation in the strict sense or for any other benefit to TDB, the shares are held at cost of acquisition till they are finally realized. However any permanent decline in the fair value of the investments so held due to the winding up or dissolution of the respective company or any other reason, the value of decline is charged to the income & expenditure account.
 10. In the case of default, rescheduling agreement(s) whatsoever done are set aside in accordance with the terms and conditions of the Loan Agreement and balances in account are restored the original agreement. This may result in increase of outstanding amount of the borrower due to reverting back to the original agreement.
 11. In the case where borrower is unable to pay the loan / interest amount as per the terms of loan agreement and when the dispute arising out of noncompliance of the loan agreement and consequently matter is referred to arbitration. In such instance the outstanding amounts of loan and interest is frozen on the date of reference to arbitration. Further provisioning or adjustment in the outstanding interest is made only after the award is passed in accordance with the award conditions.
 12. In the case where the borrower has defaulted in repayment of its loan and interest as per loan agreement and has since gone into liquidation, booking of interest has been restricted to the date of liquidation. Final provision for write off is made for principal and interest after receipt of final payment from the Official Liquidator since the right to claim interest up to the date of recovery is maintained by TDB.
 13. Company's whose status has been identified as having been struck off from the list of registered companies or undergoing liquidation as per the records of Registrar of Companies (ROC), where the loan amount and interest remains overdue/unpaid, has been referred to the legal section. However due to high probability of default and non-confirmation of balance, no interest for the current year has been accounted. Final provision for doubtful recovery or write off is subject to recommendation and confirmation of legal closure of the matter by the Legal department in case of each company.
 14. In case of default by a borrower and the subsequent passing of an Arbitration Award, the restatement of loan and interest and also the charging of interest is done as per the award. This may result in decrease/ increase of outstanding amount of interest due from the borrower.
 15. In the case of start of Arbitration proceedings, the charge of Interest is discontinued from the date of the start of the proceedings till the award is passed. After the award, other conditions remaining constant, the loan and interest thereon is accounted as per the award.

16. In case funds have not been released for the full agreed amount and the time bound repayment schedule is active, interest is calculated on the basis of the amount released at the rate applicable as per agreement.
17. Investments with Venture Funds other Seed funds are carried at cost. Since the Funds are continuously evolving in terms its activities and is an ongoing concern, no permanent change in the value of the investment is envisaged or provided. Income / Loss is recognized in the Venture Fund Investments either on closure of the funds or disbursement of income during the tenure of the fund.
18. Unless otherwise agreed to by TDB, the payment received from a borrower shall be accounted towards such dues in the following order, viz., Interest including additional interest; further interest and liquidated damages on defaulted amount; repayment instalments of principal due and payable or in the manner as decided and approved by the Board.
19. Stock verification by the management is done on annual basis.
20. Figures are rounded off to the nearest rupee.

Technology Development Board

Significant Accounting Policies and Notes on Accounts-2020-21

Notes on Accounts

1. TDB received Rs. 1000 lakhs (P.Y. Rs. 9800 lakhs) as grant during the financial year 2020-21.
2. Technology Development Board has an overdue loan repayment (amount due but not received) amounting to Rs. 21937.28 lakhs (P.Y. Rs. 21765.44 lakhs) as on 31st March, 2021. In addition, simple interest of Rs. 10994.42 lakhs (P.Y. Rs. 10810.20 lakhs), additional interest on loan amounting to Rs. 23265.42 lakhs (P.Y. Rs. 21751.21 lakhs) and Rs. 8347.34 lakhs (P.Y. Rs. 7533.55 lakhs) as

additional interest on simple interest, were also due.

3. With the change in the Government policy on Non-Performing Assets (NPA) and Insolvency & Bankruptcy Policy 2016, TDB is hopeful to recover substantial percentage of overdue accounts. Provision for doubtful debts is made on basis of representations for settlement with borrowers, recommendation of Dispute Resolution Committee (DRC) or other information as is made available by the legal department in such cases, and permanent impairment is recognized on final settlement of the claim amount.

4. Investment and valuation in Venture capital funds (VCF):

Sl. No.	Particulars	Par Value of Unit	Amount Invested/Redeemed						NAV per Unit			
			Outstanding Amount as on 31.03.2020		Addition during the year		Redemption/Loss during the year		Closing Amount as on 31.03.2021		NAV as on 31.03.20	NAV as on 31.03.21
			Amount (Rs.)	Number of Units	Amount (Rs.)	Number of Units	Amount (Rs.)	Number of Units	Amount (Rs.)	Number of Units		
1.	APJDC Venture capital fund-pvt ltd	1,00,000	28,97,88,000	2,084	-	-	39,89,334	40	28,38,25,888	2,058.26	3,299	186.131
2.	QVFL Limited, Ahmedabad	1,00,000	1,59,209	3,38	-	-	-	-	1,59,209	1.30	1,82,77,984	1,35,42,484
3.	Ivy Cap.venture Trust Fund (*)	1,00,000	21,89,68,341	2,189	-	-	1,37,81,937	157	29,11,36,404	2,011	39,099	1,64,702
4.	These venture capital fund/inch sector seed capital fund	10,000	9,83,44,100	9,834	-	-	9,61,39,030	9,834	2,01,070	21	38,383	34,235
5.	SME Tech Fund-RVCF Trust II	108	11,34,40,374	11,44,498	-	-	2,02,02,156	2,02,022	9,42,39,418	8,47,384	108	120
6.	SRAF India Agri business Fund	1,00,000	21,80,49,933	426	-	-	11,21,214	2	20,89,27,541	41,788	48,754	23,356
7.	SIDBI Venture capital Ltd - India Opposite Fund	1,000	17,45,08,181	1,34,308	-	-	2,14,21,262	22,122	15,17,84,921	1,31,785	877	823
8.	Venture East - TeSto Fund II	758	4,61,41,882	1,30,000	-	-	-	-	4,42,43,882	1,39,800	1,090	830
9.	CIE - India Fund for Sustainable Energy (ISF Trust)	100	1,86,59,207	1,86,398	10,39,643	10,596	77,88,833	77,688	4,89,83,413	4,89,834	115	121
			3,32,27,48,848	38,49,635	33,99,645	10,896	18,74,94,288	3,12,818	95,63,95,339			

(*) Opening Value of Investment in IvyCap VF is restated to adjust for income booked as reimbursement of Investment instead of income amounting to Rs. 18,10,541 in FY 2019-20

	NAV Value (in Rs)	Cost of Investment	Unrealised (Loss)/profit
Current Year	75,02,71,692	95,61,05,339	- 20,58,33,647
Previous Year	86,95,51,352	1,12,27,48,840	- 25,31,97,488

Note:

- 1) The redemption from the Venture Fund recognized on the basis of the distribution by the fund in accordance with Para 17 of Schedule 24 referred above

a) Income (Loss) on redemption of Units of Venture Funds Investment during the year earned during the year:

(Amount in Rupees)

S. No	Name of the Scheme	Profit/(Loss) in lakhs
1.	M/s Iyycap Venture Trust Fund	3181.68
2.	M/s Blume Venture Capita fund	478.61
3.	M/s SME Tech Fund - RVCF Trust II	(84.28)
Net Profit/(Loss)		3576.01

5. TDB has signed agreement with M/s Global Innovation Technology Alliance (GITA), in joint venture with CII, in equity contribution of 51:49 respectively with a mandate to cover all key elements of innovation ecosystem that benefit industry and technology start-ups, with DST and other organizations. The equity participation of TDB in GITA is Rs. 7.21 crore up to 31st March 2021.

6. The following grant-in-aid distributed during the financial year.

Sl. No.	Company's Name	Purpose	Amount (Rs. in lakhs)
1	Indo French Centre for Promotion of Advanced Research (CEFIPRA)	Programme Management	12.06
Total			12.06

7. **Earmarked/ Endowment Fund: (Schedule 3)**

a) The transfer of money receipts and liabilities outstanding in the books of the Industrial Development Bank of India (IDBI) on account of Venture Capital Fund (VCF)

transactions pertaining to grants released by Government of India are required to be transferred to the Board as on 1st September 1996. IDBI has not provided with audited statement of accounts for the current year ended 31.3.2021. No further investment or recovery against existing investments in the portfolio held by them since last several years has been reported by IDBI. Audited financial statements for the year ended 31.03.2020, (which was the responsibility of IDBI) have not been received, therefore financial values as on 31.03.2019 have been incorporated.

b) No change in the borrower outstanding/ recovery i.e.: the amount recoverable from the borrower which would include the amount of accrued interest/ additional interest in memorandum books has been reported. Further write off of bad loans including accrued interest outstanding shall be done where the recovery process has reached a closure and no further repayments are expected from the loan accounts and the same have been approved for write off by the Board.

c) The management fees charged by IDBI for management of the Asset portfolio has not been agreed to be payable by TDB and it has been taken up with IDBI for settlement. The amount of Rs. 3,62,10,646/- claimed to be payable to IDBI by TDB is contingent to the final settlement.

8. In accordance with the Agreement between Government of India through Department of Economic Affairs (DEA) and Department For International Development (DFID), Government of United Kingdom of Great Britain together with TDB bide Memorandum of Understanding dated 29.8.2013, it was agreed that the incubation component of "Innovative Ventures and Technologies for Development (INVENT)

programme will be Implemented and monitored with TDB, Department of Science & Technology, and government of India. The responsibility of TDB is to ensure that funds will be spent on approved activities required to deliver the overall outputs and outcomes of the project. TDB is obliged to hold this fund in a separate bank account and the interest accrued on the bank deposit are to be credited to the fund as part of additional funds available for the program and as fund manager to be released as per project guideline from time and submit progress report and audited accounts to DFID.

9. In accordance with the Project guidelines as per order no. DST/SEED/TDB/COVID19/SCSP (G), Rs. 7500.00 lakhs were released by the Department of Science & Technology, Science for Equity Empowerment and Development (SEED) Division, for providing assistance as grants and loans for fighting COVID 19. The funds were provided to TDB with the express intent to address the havoc caused to the country by the COVID 19 virus. The amount received is accounted under targeted project funds and utilization/realization and refunds if any are accounted against the said fund on behalf of the government. The transactions do not form part of TDB grants.
10. TDB has granted moratorium relief due to COVID pandemics to the companies whose repayments falls between April 2020 to October 2020. TDB has charged only 5% simple interest on the principal due during that period. This is in accordance with the Covid policy dated 11th April, 2020 & 24th June, 2020.
11. TDB had preferred an application before NCLT before the recovery of its Loan and its investments in equity in NICCO Corporation (P) Ltd. The NCLT has ordered the investment in equity to be considered as part of loan given by TDB. All realizations arising out of the liquidation proceedings of the company have first been adjusted against the outstanding loan amount and the balance against the cost of investment held under equity.
12. Provision for doubtful interest and additional interest due on loans and also principal amount has been made against the following companies, which have agreed to settled their outstanding/ dues as per a proposed recommendation of Dispute Resolution Committee (DRC) and approved by the Sub Committee of the Board or where the matter has been admitted in Debt Recovery Tribunal (DRT) and recovery is considered doubtful. During the year no further interest has been provided.

Following are the details of provision upto 31.03.2021.

Companies Name	Provision of Interest & additional interest (Rs. in lakhs)			
	2016-17	2017-18	2019-20	Total
M/s Medirad	705.40	408.81	-	1114.21
M/s Coral Telecom	100.04	23.29	-	123.33
M/s Waterlife	-	1.01	-	1.01
M/s Amalgam Leather	-	880.78	-	880.78
M/s Exponential	-	92.88	-	92.88
M/s Dorvan Agro	-	-	116.16	116.16
TOTAL	805.44	1,406.77	116.16	2,328.37

13. Previous year figures have regrouped and reclassified to make them comparable with current year figures.

-Sd-
(Rajesh Jain)
Director
Technology Development
Board

-Sd-
(Dr. Neeraj Sharma)
Secretary
Technology Development
Board

-Sd-
(Prof. Ashutosh Sharma)
Chairperson
Technology Development
Board





**Separate Audit
Report of
C&AG for the
year 2020-21**



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा,
वैज्ञानिक विभाग
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली 110 002
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT,
SCIENTIFIC DEPARTMENTS,
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110002

महा.नि.ले.प.(वै.वि.)/नि/2(20)/TDB/Annual A/cs/2021-22/ 711-712

Dated: 10-11-2021

सेवा में,

अवर सचिव
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड
ए-ब्लिग, ग्राउंड फ्लोर,
विश्वकर्मा भवन,
शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली - 110 016

विषय: प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के लेखों पर पृथक ऑडिट रिपोर्ट।

महोदय,

मुझे प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के लेखों पर पृथक ऑडिट रिपोर्ट अर्पित करने का निर्देश हुआ है।

संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखों को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा अपनाया जाए। प्रत्येक दस्तावेज जो संसद में प्रस्तुत किया जाए उसकी तीन प्रतियां इस कार्यालय तथा दो प्रतियां भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अर्पित की जाए। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथि (यां) भी इस कार्यालय को सूचित की जाए।

आपसे अनुरोध है कि पृथक ऑडिट रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद अपने कार्यालय में कराने के पश्चात सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी दोनों में हमें भेज दें ताकि हिन्दी प्रति को शीघ्र अर्पित किया जा सके।

यह महानिदेशक द्वारा अनुमोदित है।

भनदीय,

संलग्नक: यथोपरि।

प्रतिक्रिया:

- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, रिपोर्ट (स्व.नि.), कार्यालय भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली को इस कार्यालय में e-mail दिनांक 28.10.2021 के संदर्भ में। आपके कार्यालय द्वारा किये गए परिचर्चन/सुझाव को सम्मिलित कर लिया गया है। पृथक ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम कॉपी भी मुख्यालय की टिप्पणियों के उत्तर और प्रपत्र की प्रति भी इसके साथ संलग्न की जा रही है।

निदेशक (निरीक्षण)

निदेशक (निरीक्षण)

Separate Audit Report of Comptroller and Auditor General of India on the accounts of Technology Development Board, New Delhi for the year 2020-21

We have audited the attached Balance Sheet of Technology Development Board (TDB), New Delhi as of 31st March 2021 and the Income & Expenditure Account/ Receipts & Payments Account for the year ended on that date under 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 13(2) of the Technology Development Board Act, 1995 (No.44 of 1995). These financial statements are the responsibility of the Board's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India on the accounting treatment only regarding classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions regarding compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/Comptroller and Auditor General's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that –

- (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit,
- (ii) The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Government of India,

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Board, as required, in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

(A) Balance Sheet

Liabilities

Current Liabilities and Provisions: Rs.7368.11 lakh (Schedule 7)

TDB has shown the interest earned amounting to Rs. 2.19 crore on grant of Rs. 75 crores for the project "Fighting Covid 19" as interest earned instead of current liabilities. This resulted in the Overstatement of Income and Understatement of Current Liabilities to the extent of Rs. 2.19 crore.

B. General

1. Investments from Earmarked/Endowment Fund – Rs.65.99 lakh

(Schedule 9)

It was already brought to the notice of TDB through previous years' Separate Audit Report that investments made in companies in a shape of 'Equity' were required to be shown at fair market price.

However, TDB adopted/ incorporated the last year's figure of Rs.65.99 lakh of value of investment made in equity (after diminution in its value). Audited Financial Statement for the year 2020-21 was not received from the IDBI and TDB has incorporated the value of earmarked funds as on 31 March 2019. As the actual/ audited figure of equity (after diminution in its value) for the current year was not reported in the books of accounts for the year 2020-21,

therefore, the amount of Rs.65.99 lakh reported as Investment (Equity), as on 31 March 2021 could not be verified during audit.

2. Investments – Others – Rs.11663.34 lakh (Schedule 10)

An amount of Rs.116.63 crore was reported in Schedules 10: 'Investments – others' appended to Balance sheet of TDB for 2020-21, as investments made in different companies in a shape of 'Equity/Venture Capital Funds (VCFs)'.

reduction was required to be charged or credited to the profit and loss accordingly. However, despite being mentioned in previous year's Separate Audit Report, TDB did not revalue them at fair market price.

3. TDB had not shown a list of companies in schedule-24 notes on accounts, whose status has been identified as having been struck off from the list of registered companies or undergoing liquidation as per the records of Register of Companies (ROC), where the loan amount and interest remains overdue/unpaid.

C. Grant-in-Aid

TDB receives grants from Department of Science and Technology out of the R&D Cess levies and collected by the Government at the rate of five per cent on payments made towards import of technology. TDB received a grant of Rs.10.00 crore from the Department of Science and Technology during 2020-21.

In addition to opening balance of Cash/Bank balance of Rs.187.07 crore, an amount of Rs.196.21 crore was received by TDB as interest on short term deposits/loans/royalty/grants, repayment of loans, royalty, income from venture funds, donation etc., during the year 2019-20. After making a total payment of Rs.58.72 crore for investments, establishment/office expenses and disbursement of loans/grants, etc., Rs.324.55 crore was shown as unspent as on 31 March 2021.

D. Management Letter:

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Secretary, TDB through a management letter issued separately for remedial/ corrective action.

- (v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Accounts and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- (vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Significant Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report, give true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

- a. In so far as it related to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Technology and Development Board, as at 31 March 2021; and
- b. In so far as it related to Income & Expenditure Accounts, of the *surplus* for the year ended on that date.

For and on behalf of CAG of India



**Director General of Audit
(Environment and Scientific Department)**

Annexure –I to Audit Report**1. Adequacy of Internal Audit System**

Internal audit of TDB for the year 2018-20 has been conducted. Audit further observed that total 20 internal audit paras pertaining to year 2008-10 to 2018-20 were outstanding for compliance/ settlement, as on 31st March 2021.

2. Adequacy of Internal control system

In terms of Rule 238 of General Financial Rules, each grantee Institution is required to furnish the utilization certificate within 12 months of the closure of the financial year, indicating that the grant has been utilized for the purpose for which it was sanctioned. However, despite being pointed out in earlier Audit Reports, TDB did not obtain the Utilization Certificates in respect of 3 cases aggregating to Rs. 47.80 lakh from grantee institutions in time.

3. System of physical verification of fixed assets

Physical verification of fixed assets had been conducted for the year 2020-21 and discrepancies are reported in the management letter.

4. System of physical verification of inventories

TDB replied that it has 'Fixed Assets' and 'Consumable Goods' only. Accordingly, the annual physical verifications of both have been done after closing of each financial year.

5. Regularity in payment of statutory dues:

No statutory dues were outstanding.

SEPARATE AUDIT REPORT

SANJAY KUMAR JHA

D.O.No.DGA (ESD)/Inspection/2(20)/A/C-TDB/2021-22/208

Dated: 10-11-2021

Dear Sir,

I have audited the Annual Accounts of the Technology Development Board, New Delhi for the year 2020-21 and have issued the Audit Report thereon. During the course of audit, some deficiencies were noticed which were of a relatively minor nature and were, therefore, not included in the Audit Report and are now enclosed in the Annexure. These are being brought to your notice for remedial and corrective action.

With warm regards,

Yours sincerely,



Enclosure: Annexure

Shri Rajesh Kumar Pathak
Secretary,
Technology Development Board,
Technology Bhawan, New Delhi 110016

Annexure to Management Letter

Assets**Fixed Assets: Rs.84.96 lakh (Schedule 8)**

TDB had shown computer peripheral devices under the head 'Equipment/Apparatus/Machinery' instead of 'computers' which resulted in less charge of depreciation and overstatement of fixed assets to the extent of Rs. 2.09 lakhs. (Annexure A).


Director (Insp.)

Annexure-A

Sr. No	Name of Asset	Net Block as on 01.04.2020	Addition in 2020-21	Total	Depreciation Charged for 2020-21(@ 15%)	Depreciation to be Charged for 2020-21(@40%)	Differences
1.	Printer	264407	119451	383858	57579	153543	-95964
2.	UPS(500/1000)	362310	5150	367460	54733	145954	-91221
3.	Scanner	4832	-	4832	725	1933	-1208
4.	MS Office (Mac)*		7951	7951	597	1590	-993
5.	Computer	7665	-	7665	1150	3066	-1916
6.	UPS 3KVA	42061	-	42061	6309	160824	-10515
7.	UPS 2KVA	31407	-	31407	4711	12563	-7852
	Total	81133	7951	845234	125804	335473	-209669